www.indiatodayhindi.in

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

OO

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 54 (आवरण सहित)

आइएसआइएस-केः देश के लिए खतरा

तोक्यो पैरालंपिकः जीत का फॉर्मूला

किसान आंदोलनः भाजपा की मुसीबत

22 सितंबर, 2021 50 रुपए

# इंडिया टुडे

महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के लिए मुंबई में भाजपा का रास्ता रोको आंदोलन

# पिछड़ों की सियासत

जाति जनगणना कराने की विपक्ष की जोरदार मांग से पिछड़ा वर्ग के वोटों के लिए संघर्ष बढ़ने की संभावना. सत्ताधारी भाजपा को अंदेशा है कि इससे उसकी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति बिगड़ सकती है

VISIT…

INDIA TODAY

# BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

# प्रधान संपादक की कलम से

चाहे हम जितना इनकार करें, देश आजादी के 75 साल और काफी आर्थिक तरक्की के बाद भी जाति में फंसा समाज है. यह हमारे समाज और सबसे बढ़कर हमारी राजनीति में रचा-बसा है. अमूमन कहा जाता है, भारत के लोग अपना वोट नहीं देते, बल्कि अपनी जाति को वोट देते हैं. जाति और राजनीति के इस मेल को ज्यादातर निहितस्वार्थी नेता हमेशा बनाए रखना चाहते हैं. 1989-90 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के मंडल आयोग पर अमल करने के फैसले के बाद देशव्यापी विरोध उठ खड़ा हुआ तो जाति की राजनीति केंद्रीय राष्ट्रीय मंच पर आ धमकी. उनका फैसला सामाजिक न्याय के प्रति लगाव से नहीं, बल्कि अपनी गठजोड़ सरकार को बचाए रखने की चतुर गणना से प्रेरित था. उस फैसले ने 27 फीसद सरकारी नौकरियों को ओबीसी या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया. वह राष्ट्रव्यापी जाति वोट बैंक बनाने की शुरुआती कोशिश थी. संविधान ओबीसी को मान्यता देता है, मगर उसने यह तय करने का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया कि वे कौन हैं. वर्षों के अंतराल में ये जातियां राजनैतिक और आर्थिक तौर पर ताकतवर हो गईं लेकिन शिक्षा और सरकारी नौकरियों से खुद को वंचित पाती हैं इसलिए आरक्षण की मांग कर रही हैं. मंडल आयोग के जाति आधारित आरक्षण को विभाजनकारी मानने वाली भाजपा ने अपने हिंदू वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए राम मंदिर आंदोलन छेड़ दिया.

इस बीच, मंडल के बाद के दौर में हरेक ओबीसी जाति केंद्रित राजनैतिक पार्टियों का उदय देखा गया. माना जाता है कि ओबीसी आबादी का करीब 52 फीसद हैं. यह आंकड़ा लंबे समय से जांचा-परखा नहीं गया है क्योंकि आखिरी जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी. यहां तक कि 1980 के मंडल आयोग ने भी 1931 के जनगणना के आंकड़ों को ही आधार बनाया.

मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के तीन दशक बाद ओबीसी फिर सुर्खियों में हैं. 2018 में केंद्र सरकार ने कहा कि वह हर दशक में एक बार जनगणना की प्रक्रिया में इस बार जाति की गणना भी करेगी. हालांकि इस जुलाई में वह मुकर गई और कहा कि जाति आधारित जनगणना नहीं करेगी.

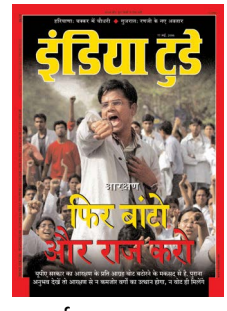

17 मई, 2006 का आवरण

इसकी वजहें जानना कोई मुश्किल नहीं है. राजनैतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव महज छह महीने दूर हैं. सरकार को डर है कि जाति-समीकरण में छेड़छाड़ से उसे ऊंची जातियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और सत्ता में वापसी की उसकी संभावना गड़बड़ा सकती है. इसके अलावा, जाति की संख्या में कोई ऊंच-नीच बर्र के छत्ते को छेड़ना जैसा है, जिससे न सिर्फ केंद्र और राज्यों में 90 लाख सरकारी नौकरियों में, बल्कि 23 लाख इंजीनियरिंग और तकरीबन 80,000 मेडिकल कॉलेजों की सीटों में भी आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज होगी.

विपक्षी पार्टियां, कुछ एनडीए की सहयोगी भी, जाति जनगणना चाहती हैं. उन्हें उसमें भाजपा की हिंदू वोट बैंक की गोलबंदी को तोड़ने और ओबीसी वोट को उससे अलग करने का मौका दिख रहा है. पिछले कुछ साल से भाजपा ने अपनी ओबीसी वोट हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई है. उसकी ओबीसी वोट हिस्सेदारी 2009 के आम चुनावों में 22 फीसद से बढ़कर 2019 में 44 फीसद हो गई. उत्तर प्रदेश में 32 फीसद भाजपा विधायक ओबीसी हैं, जो एक दशक पहले 20 फीसद थे.

जाति जनगणना की मांग 4 मार्च को महाराष्ट्र में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से तेज हो उठी. सर्वोच्च अदालत ने ओबीसी आंकड़ों के अभाव में राज्य के नगर निगमों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों के स्थानीय निकाय चुनावों में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया.

ओबीसी आरक्षण में किसी तरह के फेरबदल से कई पार्टियों के जाति समीकरण बुरी तरह गड़बड़ा सकते हैं. मसलन, इससे 27 फीसद ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की मांग उठ सकती है. इसी तरह कुछ जाति समूहों के बारे में कोई सरकारी स्पष्टता नहीं है. मसलन, जाट राजस्थान में तो ओबीसी सूची में हैं, लेकिन हरियाणा या केंद्रीय सूची में नहीं हैं. कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में ब्राह्मण ओबीसी सूची में हैं.

ओबीसी जातियों की संख्या भी बढ़ रही है. आजादी के दौरान 2,399 पिछड़ी जातियां थीं, लेकिन 2006 तक उनकी संख्या 5,013 हो गई और फिलहाल करीब 6,000 हैं.

इस जाति झमेले में अब यह भी जुड़ गया है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मराठा जैसी प्रभावशाली जातियां भी ओबीसी की तरह आरक्षण की मांग कर रही हैं. पहले निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी आरक्षण की मांग उठ चुकी है.

केंद्र राजनैतिक तौर पर इस गरम तवे को राज्यों के हवाले करने की उतावली में है. इस साल 127वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें किसी जाति समूह को ओबीसी घोषित करने की ताकत वापस राज्यों को दे दी गई. इसके बावजूद कई उलझी गांठें हैं. मसलन, 27 फीसद आरक्षण पर कैसे अमल हो रहा है, यह देखने के लिए 2018 में गठित रोहिणी आयोग ने पाया कि करीब 6,000 ओबीसी जातियों और समुदायों में सिर्फ 40 ही आरक्षण का 50 फीसद लाभ उठाती हैं. जाति समीकरण में फेरबदल की कोई भी कोशिश एक या दूसरी जाति को काफी नागवार लग सकती है.

हमारी आवरण कथा 'पिछड़ों की सियासत' ओबीसी वोटों की इस होड़ की पड़ताल करती है. इसे डिप्टी एडिटर कौशिक डेका ने लिखा है. जाति भारतीय समाज की तकरीबन 2,000 साल से अभिन्न अंग रही है. हालांकि इसमें कोई तुक नहीं है कि सरकारी नौकरियों या प्रोफेशनल शिक्षा के कोर्सों में दाखिले की इकलौती योग्यता महज किसी जाति या परिवार विशेष में जन्म होनी चाहिए. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण तो ऐतिहासिक वजहों से समझ में आता है. बावजूद इसके, अनंत काल तक जातियों को सीमित दायरे में रखने के लिए विधायी उपायों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, या उसे वोट बैंक की राजनीति के दोहन का औजार नहीं बनाया जाना चाहिए, जो सबसे बुरा है. अगर आरक्षण का इस्तेमाल असंतुलित विरासत को दुरुस्त करने के लिए किया जाना है तो वह समयबद्ध होना चाहिए, उसकी स्पष्ट समय-सीमा और हर कुछ साल में समीक्षा होनी चाहिए. अगर हमें आधुनिक समाज की तरह प्रगति करनी है तो हर सरकारी लाभ के लिए सामाजिक-आर्थिक हैसियत पर गौर किया जाना चाहिए, चाहे कोई किसी जाति का हो. व्यापक संदर्भ में देखें तो अर्थव्यवस्था में ऐसी तेज बढ़ोतरी हो, जहां निजी क्षेत्र में अकूत नौकरियां हों, सरकारी नौकरियों के लिए कोई भागमभाग न रहे और शिक्षा सुविधाएं प्रचूर हों तो सरकारी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए. आजादी के 75 साल बाद, हमें योग्यता आधारित होना चाहिए, न कि जाति आधारित.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

# इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

**चेयरमैन और प्रधान संपादक:** अरुण पुरी
**वाइस चेयरपर्सन:** कली पुरी
**ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर:** दिनेश भाटिया
**ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर:** राज चेंगप्पा
**चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर:** मनोज शर्मा
**एडिटर:** अंशुमान तिवारी
**सीनियर एडिटर:** मोहम्मद वक़ास
**एसोसिएट एडिटर:** शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर, आशीष मिश्र (लखनऊ)
**असिस्टेंट एडिटर:** मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
**राज्य ब्यूरो:**, अभिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
**ग्रुप क्रिएटिव एडिटर:** नीलांजन दास
**एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर:** चंद्रमोहन ज्योति
**असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर:** असित रॉय
**ग्रुप फोटो एडिटर:** बंदीप सिंह
**फोटो डिपार्टमेंट:** यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
**चीफ फोटो रिसर्चर:** प्रभाकर तिवारी
**प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर:** सलोनी वैद
**प्रोडक्शन चीफ:** अभिनव पुगला

**एसोसिएट पब्लिशर:** विद्या मेनन (इंपैक्ट)
**इंपैक्ट टीम**
**नेशनल हेड:** सुपर्णा कुमार (गवर्नमेंट ऐंड पीएसयू)
**सीनियर जनरल मैनेजर:** जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
**जनरल मैनेजर:** मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
**डिप्टी जनरल मैनेजर:** इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
**ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर:** विवेक मल्होत्रा
**सेल्स एवं ऑपरेशन**
**सीनियर जनरल मैनेजर:** दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
**जनरल मैनेजर:** विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
**डिप्टी जनरल मैनेजर:** राजीव गांधी (नॉर्थ)
**डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर:** योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
**डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर:** एस. परमशिवम (साउथ)
**सीनियर सेल्स मैनेजर:** पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 43; 16-22 सितंबर 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001


- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.


- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**
**संपादक: राज चेंगप्पा**


# भीतर


**सुर्खियां**
मूल्य वृद्धि: सब कुछ इतना महंगा क्यों हो गया?
**पेज 5**

अर्थात्: ये दाग़ दाग़ उजाला...
**पेज 15**

**फुरसत**
किताबें: समलैंगिक प्रेम की अनूठी दास्तान
**पेज 51**

सवाल-जवाब/संजीव अभ्यंकर: शिष्य हों संकल्प वाले
**पेज 52**

इलस्ट्रेशन: नीलांजन दास

आवरण कथा

## पिछड़ों के लिए संग्राम

ओबीसी वोटों की अहमियत को देखते हुए जाति जनगणना को लेकर विपक्षी दलों के ऊंचे हुए स्वर. लेकिन चुनावी गणित बिगड़ने और सवर्ण मतदाताओं का जनाधार खोने के डर से भाजपा बैकफुट पर


16

आइएसआइएस

**36 घर में बढ़ रहा खतरा**
केरल से 2016 से अब तक 50 लोग आइएस-के में भर्ती होने को अफगानिस्तान जा चुके

किसान आंदोलन

**26 भगवा दल को अन्नदाता की चुनौती**
किसान आंदोलन ने फिर पकड़ा जोर. यूपी में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा की मुश्किलें बढ़ीं

खास रपट

**30 खरे न उतरे तो खलबली**
नए मौजूं कोर्स न शुरू कर पाने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज अब बंद हो रहे



**इंडिया टुडे**

**इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?**
**9311409555 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.**
**या मेल करें: Moreinfo@intoday.com**
**हम आपसे संपर्क कर लेंगे.**


आवरण फोटो: विजय शंकर बाटे/एएनआइ

**पाठकों के लिए सूचना:** कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.


INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

बंगाल में भाजपा: पस्त हौसले से परेशान
पेज 8

उत्तराखंड: दरकने लगा पहाड़-दर-पहाड़
पेज 10

# सुर्खियां

भाजपा प्रभारी: संगठन पीछे, मंत्री आए आगे
पेज 12

मध्य प्रदेश: मालवा में सांप्रदायिक लावा
पेज 14

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

मूल्यवृद्धि

## आखिर सब कुछ इतना महंगा क्यों हो गया?

श्वेता पुंज

भारत धीरे-धीरे महामारी से हुए आर्थिक नुक्सान से उबर रहा है लेकिन महंगाई में लगातार उछाल से जंग जारी है. सीपीआइ (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसमें खाने-पीने की चीजें, आवास, कपड़े, परिवहन, इलाज, शिक्षा और ऐसे दूसरे खर्च शामिल हैं) पर आधारित महंगाई जून 2019 में 3.8 फीसद से करीब दोगुनी बढ़कर जून 2021 में 6.26 फीसद हो गई. यह लगातार दूसरा महीना था जब महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की 6 फीसद की सीमा से ऊपर थी. हालांकि यह जुलाई में कुछ कम होकर तीन माह के निचले स्तर 5.59 फीसद पर आ गई.

खाने-पीने की चीजों (खासकर दलहन और तेल) से लेकर ईंधन और बिजली तक सभी चीजों के दाम बढ़े. खाद्य महंगाई जून में 5.15 फीसद थी जो जुलाई में घटकर 3.96 फीसद पर आ गई, जबकि खाद्य तेलों और वसा की मंहगाई जून में 34.78 फीसद और जुलाई में 32.53 फीसद रही. (इस वर्ग की चीजें अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव से खासी प्रभावित होती हैं क्योंकि भारत खाद्य तेल की अपनी आधी जरूरत आयात से पूरी करता है.) ईंधन और बिजली की महंगाई जून में 12.68 फीसद से बहुत मामूली घटकर जुलाई में 12.38 फीसद पर आ गई. थोक महंगाई सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित महंगाई जुलाई में कुछ घटकर 11.16 फीसद रही, जो जुलाई 2020 में -0.25 फीसद थी.

भारत में महंगाई तेज मांग या बढ़ते वेतनों की वजह से नहीं बढ़ी. केंद्रीय उद्योग

और वाणिज्य मंत्रालय के बयान में कहा गया कि जुलाई 2021 में महंगाई की ऊंची दर मुख्यत: निचले आधार प्रभाव और कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के साथ खनिज तेल, बुनियादी धातुओं, खाद्य उत्पादों, कपड़ों, रसायनों और रासायनिक उत्पादों सहित दूसरी चीजों के दाम में बढ़ोतरी की वजह से थी.

ईवाइ इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी.के. श्रीवास्तव कहते हैं कि महंगाई को आग कई वजहों से लगी है. एक वजह आपूर्ति पक्ष की मुश्किलें हैं. दूसरी है कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें. भारत के भारी-भरकम अप्रत्यक्ष कर ढांचे ने इसे और पेचीदा बना दिया है. कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बीते डेढ़ साल में करीब दोगुनी हो गईं, हालांकि कच्चा तेल करीब 70 डॉलर प्रति बैरल से अगस्त 2020 तक 63.20 डॉलर पर आ गया था. उधर, केंद्र सरकार ने मार्च 2020 और मई 2020 के बीच पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 65 फीसद और डीजल पर 101 फीसद बढ़ा दिया.

बढ़ती कीमतों का दोहरा बोझ पड़ता है. उपभोक्ता अपनी खरीद क्षमता गंवा बैठता है जबकि निर्माता के लिए लागतें बढ़ जाती हैं. नतीजा फिर वही, और ज्यादा महंगाई. तेल की कीमतें बढ़ने से भंडारण और ढुलाई की लागत भी बढ़ जाती है. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ) के डायरेक्टर जनरल और सीईओ डॉ. अजय सहाय कहते हैं कि निर्यात क्षेत्र में काम करने वाले कई एमएसएमई पहले ही कह चुके हैं कि प्रतिस्पर्धी बने रहना मुश्किल हो गया है. वे कहते हैं, ''हमने टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और प्लास्टिक के उत्पादों में लगने वाली चीजों के आयात की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी है. इससे प्रतिस्पर्धा की क्षमता पर असर पड़ा है. कई सारी कंपनियों की आमदनी पर दबाव आ गया है.''

मसलन, टेक्सटाइल की घरेलू औद्योगिक इकाइयों को इन दिनों चीनी कपास के निर्यात पर पाबंदी के चलते महंगा कपास खरीदना पड़ रहा है. कपास और सूत की कीमतों में इस साल क्रमश: 100 फीसद और 63 फीसद का उछाल आया. जिंसों की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं. ऊर्जा जिंसों की कीमतें बीते छह महीने में 55.4 फीसद बढ़ी बताई जाती हैं जबकि गैर-ऊर्जा जिंसों के दाम 19.3 फीसद बढ़े. कृषि जिंसों के दाम 16 फीसद, उर्वरकों के 3.02 फीसद और धातुओं तथा खनिजों के 25.1 फीसद बढ़े. अनेक धातुओं की कीमतों में इजाफा हुआ. तांबा, एल्युमिनियम, टिन, निकल और जिंक के दाम क्रमश: 26.3 फीसद, 19.2 फीसद, 46.6 फीसद, 25.1 फीसद और 12.4 फीसद बढ़े. आगत लागतों में उछाल के चलते, खासकर जब ईंधन की कीमतों में तेजी से ढुलाई की लागत बढ़ गई हो, निर्माता को मांग में ठहराव के बावजूद कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं.

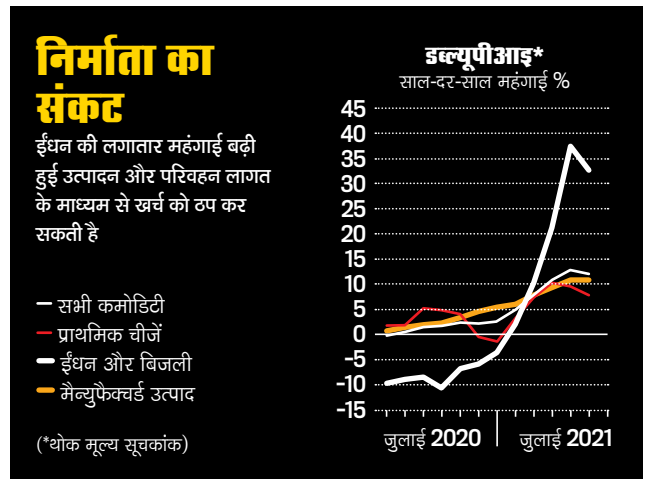


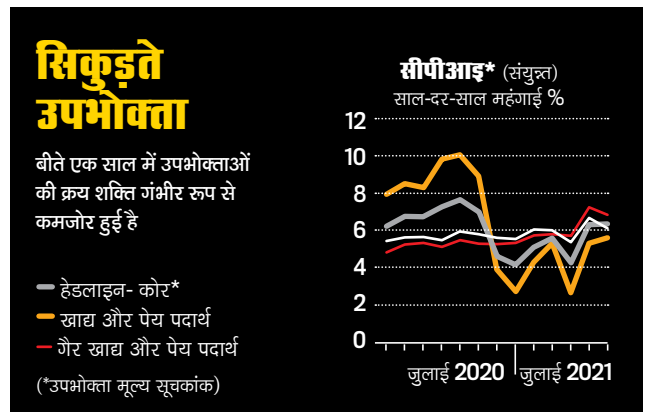


स्रोत: आरबीआइ डीबीआइई (डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी)

बड़ी एफएमसीजी फर्मों ने लागतें बढ़ने की वजह से सितंबर की तिमाही के लिए कीमतें पहले ही बढ़ा दी हैं. साबुन, औद्योगिक बेकिंग और कॉस्मेटिक्स में काम आने वाले पाम ऑयल की कीमतें इस साल नई ऊंचाई पर पहुंच गईं, जिसकी वजह से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड सहित कई कंपनियों को कीमतें बढ़ानी पड़ीं. सूत्रों का कहना है कि आगत लागतों में 25 फीसद का इजाफा हुआ है जबकि कंपनियों ने कीमतें औसतन 5 से 10 फीसद के बीच बढ़ाई हैं. घरेलू ढुलाई की लागत 8-9 फीसद बढ़ी जबकि वैश्विक ढुलाई के शुल्कों में करीब 20-30 फीसद इजाफा हुआ. इसी तरह स्टील, एल्युमिनियम, रबड़ और तांबे सरीखी प्रमुख आगत लागतें बढ़ने के चलते वाहन निर्माताओं को कीमतें बढ़ाने का सहारा लेना पड़ा.

आरबीआइ के एक हालिया सर्वे के मुताबिक, कंपनियां जब कीमतें बढ़ाने को मजबूर थीं, भारत के उपभोक्ता विश्वास में रिकॉर्ड कमी आई. सूचकांक मार्च के 53.1 से गिरकर मई में 48.5 पर आ गया. इसमें 100 आशा और निराशा को बांटने वाला स्तर है. सर्वे के मुताबिक, परिवार की खर्च की क्षमता कमजोर हुई और साथ ही अनिवार्य खर्चों में ''संयम के संकेत, जबकि गैर-जरूरी खर्चों में झिझक'' दिख रही थी.

आरबीआइ का अनुमान है कि महंगाई में एक फीसद कमी की कीमत करीब 1.5 से 2 फीसद जीडीपी वृद्धि से चुकानी पड़ती है. श्रीवास्तव कहते हैं, ''सरकार मंहगाई से चिंतित है और इस पर नजर रखे है ताकि पक्का कर सके कि यह 5-5.5 फीसद से ऊपर न जाए. मगर महंगाई से कर राजस्व भी बढ़ रहा है जिससे उसकी राजकोषीय ताकत बढ़ रही है. सरकार की राजस्व की स्थिति बहुत बुरी हालत में थी.''

महंगाई पर नियंत्रण के छोटे वक्त के उपाय के तौर पर सरकार ने जुलाई में मसूर दाल के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर शून्य किया और कृषि बुनियादी ढांचे के विकास पर लगने वाला सेस या उपकर भी इस पर आधा घटाकर 10 फीसद कर दिया. खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के लिए कच्चे पाम ऑयल पर सीमा शुल्क 35.75 फीसद से घटाकर 30.25 फीसद और रिफाइंड पाम ऑयल पर 49.5 फीसद से घटाकर 41.25 फीसद कर दिया. मगर ईंधन पर करों के मामले में केंद्र और राज्य दोनों ही जरा टस से मस नहीं हुए, जिससे ईंधन के दाम महंगाई को आग लगा रहे हैं. तेल के दाम कम हों तो कीमतों में गिरावट आ सकती है. सरकार को फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि महंगाई लगातार बढ़ते रहने की आशंका पुख्ता हो सकती है और इससे समग्रत: खर्च की सांस घुट सकती है. ■

# मुस्कुराइए आप GNT पर हैं

#GOODNEWSTODAY

www.gnttv.com

GNT

गुड न्यूज़ टुडे

नया हिंदी न्यूज़ चैनल

| dishtv | airtel digital | DD Free Dish | DEN | FASTWAY | GTPL | hathway | NXT DIGITAL | SITI NETWORKS | SUN DIRECT | TATA sky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | 322 | 13 | 310 | 188 | 240 | 212/219 | 309/312 | 311 | 585 | 525 |

बंगाल में भाजपा

# पस्त हौसले से परेशान

रोमिता दत्ता

एएनआइ

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने अपने काडर में नए सिरे से प्राण फूंकने के लिए अगस्त में पूरे महीने अभियान चलाया. *सेबायी संगठन* (संगठन का अर्थ है सेवा) नाम से चले इस अभियान का उद्देश्य सामाजिक कल्याण गतिविधियों के माध्यम से सद्भावना पैदा करना था, लेकिन पर्याप्त कार्यकर्ता न मिल पाने से अभियान सिरे न चढ़ पाया. भाजपा ने राज्य भर में करीब 1,60,000 बूथ स्तर कार्यकर्ताओं को इसमें लगाने की उम्मीद की थी पर आए बमुश्किल 3,000.

बीती 24-25 अगस्त को संगठनात्मक शक्ति की समीक्षा के लिए कोलकाता और दुर्गापुर में हुई बैठकों के दौरान पार्टी में मायूसी के मौजूदा माहौल के और भी सबूत सामने आए. राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) शिवप्रकाश की मौजूदगी में कई जिलों के मंडल अध्यक्षों ने स्वीकारा कि राज्यस्तरीय और केंद्रीय नेताओं को अपने बीच न पाने से काडर का मोहभंग हो गया है. दक्षिण 24 परगना के एक मंडल अध्यक्ष ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि ''हमारे लगभग एक-चौथाई कार्यकर्ता सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हैं. डर या हताशा के कारण तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. हमारे नेता उन्हें वापस लाने को कह रहे हैं पर यह बहुत मुश्किल लग रहा है.''

दरअसल, कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ कर जाने के बीच भाजपा बंगाल में अपना आधार बनाए रखने की लड़ाई लड़ रही है. 294 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी की ताकत 77 विधायकों से घटकर 72 हो गई है. तीन विधायक तृणमूल कांग्रेस में चले गए, जबकि दो लोकसभा सांसदों निशीथ प्रमाणिक और जगन्नाथ सरकार—ने संसद में बने रहने को विधानसभा सीटें छोड़ दीं. बड़ी चुनावी जीत की उम्मीद में भाजपा में शामिल हुए बहुत से तृणमूल नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है. सत्ताधारी दल पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए भी कई कार्यकर्ता भाजपा छोड़ रहे या निष्क्रिय हो गए हैं.

## संघ का अनुसरण करें

समर्थकों को फिर से पार्टी से जोड़ने का भाजपा का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामाजिक कल्याण वाली युक्ति से प्रेरित है. बंगाल के आदिवासियों के बीच पैठ बनाने के लिए संघ दशकों से समाज सेवा पर भरोसा करता रहा है. बंगाल में इसकी 1,600 शाखाएं हैं और यह शिक्षा तथा ग्रामीण विकास सहित लगभग 250 कार्यक्रमों का संचालन करता है. संघ के एक नेता बताते हैं, ''सेबायी संगठन ग्रामीण विकास के लिए संसाधन और आजीविका सृजन तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के संघ के मिशन पर आधारित घर-घर पहुंचने वाला अभियान है.'' संघ बंगाल में तीसरी कोविड लहर की आशंका में करीब 1,00,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित भी कर रहा है.

बंगाल में सात विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने हाल ही में राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप घोष के साथ बातचीत में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने की जरूरत पर जोर दिया. घोष कहते हैं, ''कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित करने के लिए उन्हें जन कल्याण में शामिल करने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है?'' कोविड प्रबंधन एक प्रमुख सेवा क्षेत्र है. ''हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवक अस्पताल में भर्ती होने या ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति में मदद करेंगे. सेबायी संगठन बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए कोविड टीकाकरण भी पक्का कर रहा है. अपने लोगों के लिए टीके उपलब्ध कराने को हमें जिलों में प्रखंड विकास कार्यालयों पर डेरा डालना पड़ा. तृणमूल के नियंत्रण वाली नगर पालिकाएं, निगम और स्वास्थ्य केंद्र उन्हें टीकों से वंचित रख रहे थे.''

अपनी उपस्थिति नए सिरे से जताने के लिए भाजपा ने 19 से 21 अगस्त के बीच कूचबिहार, अलीपुरदुआर, बांकुड़ा और उत्तर 24 परगना से 'लांग मार्च' निकाले. ये मुख्यत: वे क्षेत्र हैं जहां पार्टी को विधानसभा चुनावों में जीत हासिल हुई थी. इसके अलावा, 9 से 16 अगस्त तक राजनैतिक कार्यक्रमों की एक शृंखला आयोजित की गई. 16 अगस्त को 'पश्चिमबंग बंचाओ दिवस' का आयोजन करके उसी दिन ममता की पार्टी की ओर से आयोजित 'खेला होबे दिवस' का जवाब दिया

**दीदी पर नजर** ममता सरकार के खिलाफ शिकायतें लेकर 13 जुलाई को राज्यपाल धनखड़ से मिलने राजभवन पहुंचे भाजपा नेता

गया. भाजपा ने सड़कों के किनारे छोटी-छोटी बैठकें कीं और 'बंगाली हिंदुओं की मातृभूमि' के रूप में पश्चिम बंगाल के सृजन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान पर प्रकाश डाला. कुल 213 सीटों के साथ विधानसभा में तृणमूल की प्रभावशाली उपस्थिति है, लेकिन कुछ भाजपा नेताओं को विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का 2.28 करोड़ वोट हासिल करना सुखद लग रहा है. यह संख्या तृणमूल को मिले मतों की तुलना में लगभग 60 लाख ही कम है. उनका तर्क है कि यह अंतर राज्य के कुल 1,10,000 चुनाव बूथों में से प्रत्येक में औसतन सिर्फ 50 वोटों का अंतर है. घोष कहते हैं, ''पिछले विधानसभा चुनाव (2016) में केवल तीन सीटें जीतने के मद्देनजर यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है. लेकिन मीडिया केवल इस बारे में बात कर रहा है कि हमारा चुनावी पूर्वानुमान कितना गलत निकला. वे इस पर प्रकाश नहीं डाल रहे कि हम अपने कार्यकर्ताओं (चुनाव-पश्चात हिंसा के बाद) के साथ कैसे खड़े रहे हैं, उन्हें कानूनी सहायता, आश्रय और भोजन प्रदान किया है.''

### हिंसा पर राजनीति

भाजपा का दावा है कि तृणमूल के सत्ता में लौटने के बाद उसके 7,500 समर्थकों को झूठे मामलों में फंसाया गया है और पार्टी उनमें से 5,500 को कानूनी और वित्तीय सहायता दे रही है. ममता को घेरने के लिए भाजपा चुनाव बाद हुई ज्यादतियों के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से सरकार को दोषी ठहराने और कलकत्ता हाइ कोर्ट के बलात्कार तथा हत्या जैसे जघन्य मामलों की जांच सीबीआइ को सौंपने का उल्लेख कर रही है.

बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा पर जुलाई में आई मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में राज्य की तत्कालीन स्थितियों का उल्लेख 'कानून का शासन' के बजाए 'शासक का कानून' की स्थिति के रूप में किया गया है. हाइ कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ के सीबीआइ जांच के निर्देश देने को भाजपा अपने उस दावे की पुष्टि के रूप में देखती है जिसके अनुसार ममता प्रशासन ने हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी दिखाई. सीबीआइ ने इन मामलों की जांच के लिए अपने अधिकारियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के 50 कार्मिकों की मदद ले रही है.

इस मुद्दे पर जहां तृणमूल केंद्र के राजनैतिक प्रतिशोध का हल्ला मचा रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि सीबीआइ केवल अपना काम कर रही है. भाजपा प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य कहते हैं कि इसका उद्देश्य हिंसा पीड़ितों के निडर होकर शिकायत दर्ज कराने में मदद करना है. सीबीआइ अदालत के निर्देश पर काम कर रही है. पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं. सीबीआइ जांच शुरू होने के बाद से चुनाव-बाद हिंसा से संबंधित 31 नई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. इनमें चुनाव नतीजे घोषित किए जाने के दिन 2 मई को पूर्वी बर्दवान में एक वामपंथी मतदान एजेंट की हत्या का मामला शामिल है.

**भाजपा के भीतर हड़कंप-सा मचा हुआ है. उसके विधायकों की तादाद 77 से घटकर 72 रह गई है, कई अन्य भी पाला बदलने को तैयार दिखते हैं**

भाजपा के कुछ नेताओं को भरोसा है कि सीबीआइ जांच से कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा होगा. पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना और पूर्वी बर्दवान में बंद हुए पार्टी कार्यालय फिर से खुल गए हैं और स्थानीय नेताओं को उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी. हालांकि, राजनैतिक विश्लेषक इमानकल्याण लाहिड़ी का मानना है कि सीबीआइ जांच के निष्कर्षों का जनता की राय पर असर नहीं होगा. कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ाने वाले लाहिड़ी कहते हैं, ''कुछ भाजपा नेताओं के (चुनाव अभियान के दौरान) मुस्लिम विरोधी प्रचार और धर्म पर हमला करते हुए लोगों को उकसाने की घटनाओं को देखते हुए सामाजिक और स्थानीय प्रतिक्रिया तो होनी ही थी.''

करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले में पूछताछ के लिए ममता के भतीजे और तृणमूल में दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को प्रवर्तन निदेशालय के भेजे सम्मन को भी लोग ध्यान से देख रहे हैं. रुजिरा ने 1 सितंबर को महामारी का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए आने से मना कर दिया है जबकि अभिषेक से 6 सितंबर को घंटों पूछताछ की गई. लाहिड़ी सवाल उठाते हैं, ''आपको लगता है कि जो लोग राज्य सरकार से मिलने वाले 500 या 1,000 रुपए के अनुदान के लिए महामारी के बीच भी घंटों कतार में खड़े रहते हैं, उन्हें इस बात की परवाह है कि प्रवर्तन निदेशालय राज्य में सत्ताधारी दल के किसी नेता के पीछे पड़ा है?'' लाहिड़ी का मानना है कि ''ममता बनर्जी की सामाजिक कल्याण योजनाओं ने उनकी पार्टी से जुड़ी बहुत सारी नकारात्मक बातों और भ्रष्टाचार के आरोपों को बेमानी कर दिया है.''

इस बीच, भाजपा की मुश्किलों में इजाफे की वजह उसके भीतरी मतभेद हैं. ममता के संभावित चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में 30 सितंबर को होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर ताजा मतभेद हाल ही में सामने आए हैं. घोष के नेतृत्व वाला खेमा कानूनी सलाह ले रहा है कि जब राज्य चुनाव आयोग ने महामारी के कारण 142 नगर पालिकाओं में चुनाव से इनकार कर दिया, तब यह उपचुनाव कराने का औचित्य क्या है. लेकिन पार्टी का एक धड़ा उपचुनाव कराने और ममता को कड़ी टक्कर देने के पक्ष में है. भट्टाचार्य कहते हैं, ''भाजपा बंगाल में टिकने के लिए आई है, भागने के लिए नहीं.'' पर फिलहाल तो बेहतर होगा कि इसमें एकता के कुछ लक्षण दिखें. ■

रामेश्वर गौड़

उत्तराखंड

# दरकने लगा पहाड़-दर-पहाड़

**अखिलेश पांडेय**

उत्तराखंड में बारिश से भूस्खलन और पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा. इस बार उत्तराखंड में भारी बारिश ने कोई ऐसा जिला नहीं छोड़ा है, जहां भूस्खलन ने नुक्सान न पहुंचाया हो. कोरोना के चलते चार धाम यात्रा अब तक शुरू न होने से भले कारोबारी निराश हों लेकिन यह भी गौरतलब है कि यात्रा होती तो इस बार भूस्खलन जिस बड़े पैमाने पर हुआ, उससे तीर्थयात्री भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे. बारिश के कारण आम जान जीवन को पटरी पर लाना सरकारी विभागों के लिए भी चुनौती बना हुआ है. कहीं बिखरा टनों मलबा रोड को खोलने की राह में रोड़ा बना है तो कहीं सड़क पूरी तरह बह गई है इसलिए नई सड़क कटान का प्रपोजल स्वीकृत कराकर उसको नए सिरे से काटने की फौरी जिम्मेदारी विभाग पर आन पड़ी है.

इस साल हालांकि आपदा का सिलसिला राज्य में 7 फरवरी को रैणी गांव से ऊपर टूटे ग्लेशियर से शुरू हुआ. उसके बाद बारिश के दिनों में तो पूरा रैणी गांव ही भूस्खलन की चपेट में आता चला गया. हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि इस रैणी गांव में चिपको नेत्री गौरा देवी की लगी प्रतिमा सहित उनके संग्रहालय को भी खाली कराना पड़ा. भूस्खलन से सहमे पूरे गांववासियों को तो कई दिनों तक जंगली गुफाओं में शरण लेनी पड़ी.

राज्य की चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए बनाई जा रही निर्माणाधीन हर मौसम सड़क के लिए कटाई के चलते खिसकते पहाड़ों ने तो पूरे क्षेत्र में तबाही मचा रखी है. टिहरी जिले में नागनी के पास पूरा पहाड़ दरककर सड़क पर आ गिरा. इससे ऋषिकेश गंगोत्री हाइवे लंबे वक्त तक बाधित रहा. इस भूस्खलन से टनों मलबा और बोल्डर सड़क पर आ

अमित साह

गए. एनएच 94 पर बरसात के इस मौसम में कहीं न कहीं भूस्खलन होता ही रहा. यही हाल ऋषिकेश-बदरीनाथ मार्ग का भी रहा. पिथौरागढ़ जिले में थल से मुनस्यारी को जोड़ने वाली सड़क भूस्खलन के चलते बंद है इसलिए लोगों को मदकोट होते हुए 150 किलोमीटर का फेरा लगाकर मुनस्यारी पहुंचना पड़ रहा है. पिथौरागढ़ जिले कि चीन सीमा से लगे लगभग सौ गांवों का बाकी दुनिया से संपर्क भूस्खलन के चलते सड़कों के बह जाने से कटा हुआ है. इससे क्षेत्र

**बाएं से: ऋषिकेश गंगोत्री** मार्ग में जगह-जगह दरक रहे पहाड़ से बाधित सड़क, धारचुला क्षेत्र में बारिश से नेस्तोनाबूद जुम्मा गांव, नीचे: धारचुला में काली नदी पार नेपाल की तरफ के पहाड़ी गांव के गधेरे में बारिश से हुए भूस्खलन के बाद आए मलबे ने कुछ क्षण काली के प्रवाह को रोक दिया

की लगभग तीस हजार से अधिक की आबादी देश और दुनिया से अलग-थलग पड़ी हुई है. इस वजह से सीमा पर स्थापित अग्रिम सैन्य चौकियों तक आवश्यक सामान की आपूर्ति भी प्रभावित हो गई. पिथौरागढ़ जिले से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार भी कोरोना के चलते निरस्त कर दी गई इसलिए सीमांत की सड़कों के बहने से हो सकने वाली अत्यंत परेशानियों से लोग बच गए.

चमोली जिले की नीती घाटी में हेलिकॉप्टर से अग्रिम चौकियों तक सामान की आपूर्ति करनी पड़ी. यही हाल पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों की चीन सीमा का भी रहा. पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल सीमा से लगी सीमांत की तहसील धारचुला के जुम्मा गांव में 30 अगस्त की बारिश ने कोहराम मचा दिया. भारत-नेपाल की सीमा बनाने वाली काली नदी के उस पार नेपाल में भी भारी वर्षा ने एक गांव नेस्तोनाबूद कर दिया. नतीजा यह हुआ कि काली नदी में आए मलबे ने नदी का प्रवाह रोककर धारचुला के लिए भारी खतरा पैदा कर डाला लेकिन किसी तरह इससे पानी डिस्चार्ज होने से ये खतरा टल सका. धारचुला की एनएचपीसी कंपनी के आवास और कंपनी का मुख्यालय भूस्खलन और अतिवृष्टि की चपेट में आने से तबाह हो गए. जुम्मा गांव और उसके दो तोकों में सात लोग लापता हो गए, जिनमें पांच के मृत शरीर मलबे के ढेर से बरामद हुए जबकि दो लोगों का अब भी कोई पता नहीं चल सका. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के बाद गांव के दौरे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उनको पांच लाख रुपए देने का ऐलान किया.

मुख्यमंत्री के दौरे के बाद प्रभावित गांव जुम्मा का भूगर्भ विशेषज्ञों ने भी दौरा किया था. इन विशेषज्ञों ने जिलाधिकारी को जुम्मा और आसपास के गांव के लोगों को वहां से हटाने को कहा है. इसके अलावा भू-वैज्ञानिकों ने यह भी शंका व्यक्त की कि इस आपदाग्रस्त गांव के समीप जोलढूंगा का स्लाइडिंग जोन भी सक्रिय हो सकता है.

पर्यटक नगरी नैनीताल में बलिया नाले के भूस्खलन और नैनापीक में आई दरार से अभी निजात नहीं मिला था कि ठंडी सड़क के किनारे आयारपाटा पहाड़ी में स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के केपी और एसआर गर्ल्स

**इस साल बरसात में कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा, जहां भूस्खलन से तबाही नहीं हुई. विशेषज्ञ इसकी वजह अंधाधुंध असंतुलित विकास को बता रहे हैं**

## सुर्खियां

छात्रावास के ठीक तलहटी में हो रहे भूस्खलन ने विस्फोटक रूप ले लिया है. राजभवन रोड कई स्थानों में धंस रहा है. माल रोड अस्थाई तौर पर किसी तरह चालू किया जा सका है.

इसी तरह मसूरी में भी देहरादून से मसूरी को जाने वाले मुख्य मार्ग में निरंतर भूस्खलन सिरदर्द बना रहा. गलोगी पावर हाउस के पास मसूरी-देहरादून मार्ग पर हो रहे भूस्खलन से पर्यटकों की आवाजाही तो प्रभावित रही ही, खुद मुख्यमंत्री भी इस मार्ग पर फंस गए. इस तरह चाहे पर्यटन स्थल नैनीताल हो, या मसूरी या मुनस्यारी सभी भूस्खलन के चलते समस्या से जूझ रहे हैं.

नेपाल से लगे सीमांत जिले चंपावत के मुख्यालय को टनकपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला के पास हुए भूस्खलन से चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों का संपर्क भी टूट गया. देहरादून से ऋषिकेश को जोड़ने वाले मार्ग में जाखन नदी पर बना रानीपोखरी पुल टूटकर बिखर गया. यह राजनैतिक विवाद का विषय भी बन गया है. आरोप है कि खनन के लिए हुई बेतरतीब खुदाई से इसके खंभों की जमीन खोखली हो गई तो पुल बैठ गया. पुल का जायजा लेने कांग्रेस के नेता हरीश रावत पहुंचे तो मुख्यमंत्री को भी दौरा करना पड़ा. आप पार्टी के नेता भी सरकार पर हमलावर दिखे. हरीश रावत ने इस पुल के टूटने की घटना को अवैध खनन का परिणाम बताया और कहा कि गौला नदी पर बना पुल भी अवैध खनन का शिकार हुआ था लेकिन सरकार ने कोई सबक नहीं लिया.

भारी बारिश से रानीपोखरी पुल टूटने के बाद अब प्रदेश के बी ग्रेड के सभी पुलों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने एक कमेटी का गठन किया है. प्रदेश में 664 पुल बी ग्रेड के हैं, जिनका निर्माण 1960 से 1970 के बीच हुआ था. तब इन पुलों को 16 टन की भार क्षमता के अनुरूप बनाया गया था. जबकि इन दिनों बन रहे बी ग्रेड के पुलों की अब भार क्षमता 70 टन कर दी गई है.

जाहिर है, हिमालय की दुर्दशा की बड़ी वजह अंधाधुंध विकास भी है. लेकिन सरकार इस ओर ध्यान देने के बदले उन परियोजनाओं को भी मंजूरी देने का फैसला कर चुकी है, जिन पर 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. अगर संतुलित विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपदाएं यकीनन इंतजार कर रही हैं. इस साल के भूस्खलन तो यही संदेश दे रहे हैं. ■

भाजपा प्रभारी

# संगठन पीछे, मंत्री आए आगे

सुजीत ठाकुर

**क्रीम पर भरोसा**
**1.** केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मणिपुर **2.** केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश **3.**केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब, और **4.** केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को उत्तराखंड की मिली चुनावी जिम्मेदारी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों और सह-प्रभारियों की पिछले हफ्ते बुधवार को घोषणा की तो उन्हें जीत के लिए सरकार के मंत्री ही ज्यादा भरोसेमंद लगे. संगठन के पदाधिकारी पीछे छूट गए. कुल 21 नामों में सिर्फ दो ही पार्टी संगठन से जगह बना पाए. चुनाव वाले पांचों राज्यों में से चार (उत्तर प्रदेश, उतराखंड, गोवा और मणिपुर) में सरकार बचाने और एक (पंजाब) में सरकार बनाने की चुनौती है.

चुनौती से निपटने में शायद नड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों को ही ज्यादा मुफीद समझा. पार्टी संगठन के जिन दो लोगों पर भरोसा किया गया, उनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस को गोवा का चुनाव प्रभारी और दूसरे, पार्टी के प्रवक्ता सरदार आर.पी. सिंह को उत्तराखंड का सह-प्रभारी बनाया गया है.

पांचों राज्यों के लिए कुल 21 प्रभारियों और सह-प्रभारियों में केंद्र और राज्य सरकारों के14 मंत्री हैं. उनके अलावा, पांच सांसद और पूर्व विधायक हैं लेकिन पार्टी संगठन में किसी पद पर नहीं हैं. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है. उनके साथ चार सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा करंदलजे और अन्नपूर्णा देवी हैं. ये सभी केंद्र में मंत्री हैं. इनके अलावा, राज्यसभा के दो सदस्य विवेक ठाकुर और सरोज पांडे तथा हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी सह-प्रभारी हैं.

मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, तो सह-प्रभारी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक और असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल हैं. उत्तराखंड का चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को बनाया गया है. यहां सह-प्रभारी के रूप में संगठन से सिर्फ आर.पी. सिंह को लिया गया है. दूसरी सह-प्रभारी सांसद लॉकेट चटर्जी हैं. पंजाब का प्रभार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है. उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मीनाक्षी लेखी तथा सांसद विनोद चावड़ा सह-प्रभारी बनाए गए हैं. संगठन के लिहाज से सिर्फ गोवा में ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस को चुनाव प्रभारी बनाया गया है. उनके साथ दो केंद्रीय मंत्रियों जी. किशन रेड्डी और दर्शना जर्दोश को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है.

कोरोना की दूसरी लहर की तबाही, लोगों के जर्जर माली हालात, महंगाई और तीव्र किसान आंदोलन के बीच होने वाले इन पांच राज्यों के चुनावों को मोदी-2 सरकार की अग्निपरीक्षा के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में क्या वजह है कि चुनाव प्रभारी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठन की जगह सरकार के मंत्रियों को दी गई है? भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, ''1999 में बेंगलूरू में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी यह सवाल उठा था. अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे. उन्होंने तब कहा था कि भाजपा में दो महाजन हैं. प्रमोद महाजन और सुमित्रा महाजन. लेकिन सरकार में सिर्फ एक महाजन इसलिए हैं क्योंकि सरकार में क्रीम चाहिए जो मैंने (वाजपेयी) ले लिया.'' निहितार्थ यह है कि संगठन के ज्यादातर क्रीम सरकार में मंत्री बन गए तो उन्हें ही चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है.

**भाजपा ने अगले साल पांच राज्यों के चुनावों के प्रभारी केंद्रीय मंत्रियों को ही बनाया. पार्टी संगठन को मामूली मौका ही मिला**

हालांकि मौजूदा दौर में पहले के चुनावों में पार्टी के महासचिव, उपाध्यक्ष या सचिव रहे भूपेंद्र यादव, अनिल जैन, सरोज पांडे, अरुण सिंह वगैरह को चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी. यह शायद पहली बार है कि पार्टी के किसी महासचिव या सचिव को जिम्मेदारी नहीं मिली. यही नहीं, फडणवीस के सिवा किसी और उपाध्यक्ष को भी यह मौका नहीं मिला.

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की सफाई है, ''केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव प्रभारी बनने से संगठन को ताकत मिलेगी. संगठन और सरकार दोनों के लोग मिलकर मेहनत करेंगे और परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे.'' लेकिन हकीकत यही है कि कमान केंद्रीय मंत्रियों के हाथों में होगी तो चुनाव नतीजों की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी क्योंकि संगठन पीछे छूट गया है. ■

तेलंगाना

# रेड्डी परिवार में छिड़ी रार

अमरनाथ के. मेनन

एएनआइ

**पिता की दुलारी**
हैदराबाद में वाइएसआरटीपी की पत्रकार वार्ता के दौरान दिवंगत वाइएसआर को श्रद्धांजलि देतीं वाइ.एस. शर्मिला

अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाइ.एस. राजशेखर रेड्डी की 2 सितंबर को 12वीं पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी विजयम्मा ने हैदराबाद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जो अब तेलंगाना की राजधानी है. हालांकि वाइएसआर के बेटे तथा आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री वाइ.एस. जगनमोहन रेड्डी उससे दूर रहे, जिससे रेड्डी परिवार में कलह की अटकलों की पुष्टि हो गई. दरअसल, जगन बहन वाइ.एस. शर्मिला के तेलंगाना में अपने पिता से 'प्रेरित' नई राजनैतिक पार्टी शुरू करने के फैसले के खिलाफ हैं, क्योंकि यह उनकी युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस (वाइएसआरसी) को टक्कर दे सकती है, जिसका बगल के तेलुगु भाषी राज्य में राज है.

विजयम्मा ने बेटी के साथ एकजुटता दिखाई है, शायद इसलिए कि उन्हें एहसास है कि दिवंगत वाइएसआर के प्रति अब भी उनके लोकलुभावन कल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण तेलुगु भाषी लोगों के बड़े वर्ग में सहानुभूति है. शर्मिला की वाइएसआर तेलंगाना पार्टी (वाइएसआरटीपी) का उद्घाटन 8 जुलाई को वाइएसआर की जयंती पर किया गया था. जगन का मानना है कि तेलंगाना में शर्मिला की पार्टी के लिए उनकी मां का समर्थन जुटाना उनके लिए नुक्सानदेह होगा, खासकर जब दोनों राज्य कृष्णा और गोदावरी नदी के जल बंटवारे को लेकर आमने-सामने हैं.

उद्घाटन की धूमधाम और शर्मिला की कुछ रैलियों के अलावा, नई-नवेली वाइएसआरटीपी को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली. उद्घाटन के अवसर पर मौजूद रहीं विजयम्मा वाइएसआरटीपी की जमीन तैयार करने के लिए अपने पति के पूर्व कैबिनेट सहयोगियों और अन्य शुभचिंतकों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि श्रद्धांजलि सभा में कोई प्रभावशाली नेता नहीं आया.

लेकिन शर्मिला का हौसला बुलंद है. उन्होंने कहा, ''मैं तेलंगाना के लिए लड़ूंगी... मैं वाइएसआर की सच्ची अनुयायी बनूंगी और 'राजन्न राज्यम्' (वाइएसआर के स्वर्णिम शासन) को वापस लाऊंगी.'' दिवंगत वाइएसआर की 'संतुष्टि' रणनीति (कल्याणकारी कार्यक्रमों का समूह, जिसमें राज्य के हर परिवार को किसी न किसी योजना के तहत कवर किया गया था) ने तब लोगों को मोह लिया था. लोग उनके समर्थन में खड़े थे, बावजूद इसके कि वे जानते थे कि वाइएसआर अलग तेलंगाना राज्य के खिलाफ थे.

**तेलंगाना में शर्मिला के राजनैतिक अभियान को उनकी मां विजयम्मा का आशीर्वाद प्राप्त, मगर उनके भाई, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सख्त खिलाफ**

अब अपने पिता के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके शर्मिला उनकी राजनैतिक विरासत का एक हिस्सा हथियाने की कोशिश कर रही हैं. वे कहती हैं कि मैं राज्य में मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के 'अत्याचार' से लड़ने के लिए दृढ़ हूं. जानकारों को इसमें संदेह है. राजनैतिक टिप्पणीकार के. नागेश्वर कहते हैं, ''वाइएसआर की कल्याणकारी नीतियों से उनके समर्थकों की तादाद बढ़ी थी. लेकिन राज्य के पुनर्गठन के बाद बदले हुए राजनैतिक संदर्भ में, शर्मिला का 'राजन्ना राज्यम्' का आख्यान तेलंगाना के नए राजनैतिक मुहावरे में असंगत हो सकता है. ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है, क्योंकि वाइएसआर अलग तेलंगाना राज्य के खिलाफ थे.'' वे यह भी बताते हैं कि तेलंगाना में पहले ही राजनैतिक क्षेत्र में नेताओं का जमावड़ा है.

इस बीच, कांग्रेस भी घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुई है. पार्टी ने राज्य के नेताओं को श्रद्धांजलि बैठक में शामिल होने को लेकर आगाह कर दिया था. 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए-दो सरकार के आंध्र प्रदेश को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के फैसले के बाद पार्टी को अपना अस्तित्व बचाने के लिए गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, और बड़े पैमाने पर पार्टी के लोग जगन रेड्डी के वाइएसआरसी में चले गए. तेलंगाना में कई लोग सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति में चले गए. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रचार समिति के अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस सांसद मधु यास्की बताते हैं, ''जगन और उनका परिवार कांग्रेस की डाल काटने की कोशिश कर रहा है, जिसने उन्हें राजनैतिक जीवन दिया.'' ■

मध्य प्रदेश

# मालवा में सांप्रदायिक लावा

राहुल नरोन्हा

पवन भंवर

**माहौल गर्म** इंदौर क्षेत्र के हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करते हुए

एक के बाद एक कई सांप्रदायिक घटनाओं ने मध्य प्रदेश के समृद्ध पश्चिमी भाग मालवा को हिलाकर रख दिया है. लोग आशंकित हैं कि न जाने कब क्या हो जाए?

सांप्रदायिक घटनाओं का हालिया दौर इंदौर के बॉम्बे बाजार की एक घटना के साथ शुरू हुआ, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है. मुस्लिम लड़कियों के लिबास में दो लड़कियां बॉम्बे बाजार में एक आदमी के साथ देखी गईं. कुछ लोगों ने उन्हें रोका और उनसे पहचान पत्र दिखाने की मांग की. पहचान पत्र देखने पर पता चला कि वे लड़कियां हिंदू थीं, उनके साथ का पुरुष भी हिंदू था. इस बात को लेकर हंगामा हो गया. पुलिस सूत्रों ने कहा कि घटना एक और घटना से जुड़ी है जो हाल के दिनों में हुई थी. एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ भाग गई थी और इस घटना को सोशल मीडिया पर बड़े जोरदार ढंग से शेयर किया गया था. मुस्लिम समुदाय को यह बहुत नागवार गुजरा.

इसके पहले एक चूड़ी बेचने वाले को लेकर विवाद भड़क उठा था. यह सिलसिला इधर लंबे समय से चल रहा है. सितंबर 2020 से अब तक मालवा क्षेत्र के जिलों में कुल 12 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गई हैं.

प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिव तथा पत्रकार विनीत तिवारी कहते हैं, ''दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में, मालवा में सांप्रदायिक घटनाओं में तेजी आई. अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के दौरान कई जगहों पर मुसलमानों को उकसाया गया था. उस समय मध्य प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव होने थे.'' दिसंबर और जनवरी में सांप्रदायिक हिंसा के कारणों का पता लगाने के लिए बने तथ्यान्वेषी दल का हिस्सा रहे तिवारी कहते हैं कि वैसे तो सांप्रदायिक मुद्दे बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हुआ करते थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सांप्रदायिक तनाव गांवों और कस्बों में समान रूप से फैल गया है. तिवारी कहते हैं, ''लॉकडाउन हटने के बाद से लोगों ने छोटे आंदोलनों या विरोध के माध्यम से सरकार की विफलताओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. सांप्रदायिक घटनाएं लोगों को उलझाए रखने का एक अच्छा तरीका हैं, ताकि वे सरकार की चूक पर सवाल ही न उठा सकें.''

कुछ लोग इन घटनाओं के पीछे 2023 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में मालवा क्षेत्र में फिर झंडा गाड़ने के लिए भाजपा की आतुरता को देखते हैं. 2018 के चुनावों में भाजपा को मालवा क्षेत्र की 66 में से 28 सीटें ही मिलीं, जो 2013 में पार्टी को मिली 65 सीटों से बहुत कम थी. हालांकि नवंबर 2020 में हुए उपचुनाव के बाद भाजपा की सीटें बढ़कर 34 हो गईं लेकिन उसे अभी अपनी स्थिति को और मजबूत करने की जरूरत है. अभी जोबट सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव और खंडवा के लिए लोकसभा उपचुनाव होने शेष हैं. दोनों ही मालवा क्षेत्र में आते हैं.

कुछ लोग इन घटनाओं पीछे राजनैतिक कारणों के अलावा, आर्थिक कारण भी देखते हैं. इंदौर के देपालपुर में एक चाट विक्रेता को अपनी दुकान का हिंदू नाम रखने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी. इंदौर में स्थानीय निवासी राजवाड़ा के पास अटाला मार्केट क्षेत्र में चल रहे एक विवाद की ओर इशारा करते हैं. अटाला मार्केट में मुख्य रूप से मुसलमानों की दुकानें हैं जो कपड़े और कृत्रिम गहने बेचते हैं. इसे ज्यादा खर्च करने में असमर्थ लोगों के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है. हिंदुओं के वर्चस्व वाले अन्य व्यापारिक संघ बाजार को बंद कराने की मांग कर रहे हैं.

ऐसी ही कुछ शंका उज्जैन में भी जाहिर की जा रही है. प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के करीब स्थित बेगम बाग क्षेत्र में अधिकांश व्यवसाय मुसलमानों के स्वामित्व में हैं, लेकिन चाहे रेस्तरां हों या मेडिकल स्टोर, सभी महाकाल के नाम पर हैं. इस क्षेत्र को भी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए सिरे से बसाने के लिए चुना गया है और इस क्षेत्र को खाली कराने की बातें भी चल रही हैं.

सरकारी सूत्रों को सांप्रदायिक माहौल में तेजी की कुछ और वजहें लगती हैं. एक शीर्ष पुलिस अधिकारी कहते हैं, ''अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी तत्वों में जोश है.'' उज्जैन में तालिबान समर्थक नारे लगाने के आरोप लग रहे हैं और पुलिस इसे पाकिस्तान समर्थक बता रही है, जबकि कुछ इसे 'काजी साहब' के समर्थन का नारा बता रहे हैं.

पिछले कुछ वर्षों में उभरे हिंदू दक्षिणपंथी संगठन बहुत मुखर हो गए हैं और सांप्रदायिक घटनाओं में जांच और कार्रवाई को प्रभावित करने के प्रयास कर रहे हैं. चूड़ी विक्रेता से जुड़ी इंदौर की घटना में, उसकी पिटाई करने वाले आरोपी ने यह भी तय किया कि चूड़ी विक्रेता पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ''जब भी कोई सांप्रदायिक घटना होती है, तो पुलिस पर हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों की राय पर विचार करने का दबाव होता है.''

जब तक प्रशासन निष्पक्ष नहीं दिखता और एक समूह के इशारे पर कार्रवाई करना बंद नहीं करता, मालवा एक अनजानी आशंका से भरा रहेगा. फिलहाल तो सांप्रदायिक सद्भाव की दिशा में कोई पहल नहीं दिखती. ■

अर्थात्

# ये दाग़ दाग़ उजाला

अंशुमान तिवारी

दिसंबर 2019 में संदीप के पास तीन टैक्सी थीं, दो पर ड्राइवर रखे थे, एक खुद चलाते थे. लॉकडाउन के बाद जून 2020 में तीनों कारें कर्जदारों ने उठा ली. अब वे दिहाड़ी पर कार चलाने के लिए अपना मोबाइल नंबर बताते हुए मिल जाते हैं. स्कूल टीचर सुधा की नौकरी गई और दो महीने की तनख्वाह भी. कोविड के डर से ट्यूशन भी मुश्किल हो गया. सुमित की फाइनेंस कंपनी ने तो हिसाब भी नहीं किया, बस नौकरी से निकाल दिया. गुड़गांव की बड़ी मॉल के सामने पार्किंग चलाने वाला रवि अब मध्य प्रदेश के दतिया में रिक्शा चला रहा है.

क्या भारत में कोविड पूर्व के दिन लौट आए हैं? क्या जीडीपी का ताजे आंकड़े (अप्रैल-जून 2021 में 20.1 फीसद की विकास दर बनाम -24.4 फीसद की सिकुड़न) की बधाई में संदीप, सुधा, सुमित और रवि के चेहरे नजर आते हैं?

मंदी होती ही है ऐसी. डूबते सब एक साथ हैं लेकिन एक साथ उबरते नहीं हैं. मंदी आंकड़ों की समझ को सिकोड़ देती है. इसलिए प्रतिशत ग्रोथ के बजाए उत्पादन की ठोस कीमत को पढ़ना चाहिए. कोविड से पहले अप्रैल-जून 2019 में अर्थव्यवस्था उत्पादन 35.8 5 लाख करोड़ रुपए था जो 2020 में इसी दौरान टूट रु. 26.95 लाख करोड़ रुपए रह गया. इस साल यह 32.38 लाख करोड़ रुपए रहा है. 2019-20 की पहली तिमाही में छह साल की सबसे कमजोर विकास दर दर्ज हुई थी. यानी कि कोविड से पहले का स्तर अभी नहीं आया जो तब छह साल की सबसे खराब विकास दर दर्ज हुई थी.

तो सुमित, सुधा या रवि जैसे लाखों लोगों की मंदी का अपडेट कहां मिलेगी? इन्हें तलाशने के लिए कुछ दूसरी संख्याएं खंगालनी होंगी.

अप्रैल-जून 2021 की 'शानदार' तिमाही में मन्नपूरम फाइनेंस ने 1,500 करोड़ रुपए के जेवरात नीलाम किए जो इसके पास गिरवी रखे थे. इससे पहले के तीन माह में 404 करोड़ रुपए के गहने बिके थे. 2020 के पहले नौ माह में यह नीलामी केवल 8 करोड़ रुपए रही थी. देश की प्रमुख गोल्ड लोन मन्नपुरम फाइनेंस के पास गिरवी यह संपत्ति निम्न आय वालों की थी, कारोबार-रोजगार टूटने की वजह से वे कर्ज नहीं चुका सके.

सोना ही नहीं बैंकों ने लोन के बदले गिरवी रखे मकानों की भी नीलामी की. तिमाही के नतीजों के दौरान स्टेट बैंक ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बकाया होने और डिफॉल्ट बढ़ने की सूचना दी थी. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक, बैंकों में ऑटो डेबिट अस्वीकृत होने का औसत वित्त वर्ष 2021 में 39 फीसद हो गया जो 2019 में 23.3 फीसद था.

**मंदी आंकड़ों की समझ सिकोड़ देती है. सो, प्रतिशत ग्रोथ के बजाए उत्पादन की ठोस कीमत को पढ़ना चाहिए**

जीडीपी की छलांग के साये में छिपा एक आंकड़ा सच के करीब ले जाता है. अप्रैल-जून 2021 में निजी उपभोग खपत केवल 18 लाख करोड़ रुपए रही. यह स्तर 2019 की इसी तिमाही से लगभग 12 फीसद कम है. भारत की 60 फीसद जीडीपी इसी से बनती है. इसके डूबने का मतलब निवेश और रोजगार की उम्मीद टूटना.

रिजर्व बैंक के ओबिकस सर्वे (2020-21) ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अभी उत्पादन क्षमता का 70 फीसद प्रयोग भी नहीं कर पाई हैं. तो नया निवेश कहां से होगा? तभी तो जब अगस्त के महीने में मंदी दूर होने का जश्न मन रहा था, उसी महीने में करीब 15 लाख रोजगार गंवाए गए. अगस्त में बेकारी दर 8.32 फीसद हो गई जो जुलाई में 6.95 फीसद थी.

ऑटो उद्योग की मंदी खासतौर पर दुपहिया वाहनों की बिक्री दर और रिजर्व बैंक व सीएमआइई के उपभोक्ता विश्वास व उम्मीद के सूचकांक भी, कोविड से पहले का माहौल लौटने की गवाही नहीं दे रहे हैं.

अगर कोविड वाली मंदी न आई होती और अर्थव्यवस्था केवल पांच फीसद की दर से बढ़ रही होती तो वित्त वर्ष 2022 में अर्थव्यवस्था का आकार 160.59 लाख करोड़ रुपए होता. अब इसे हासिल करने के लिए इस पूरे 2022 में करीब 20 फीसद की विकास दर चाहिए, केवल एक तिमाही में नहीं.

अक्सर आंकड़े सब कुछ नहीं समेट पाते. रॉबर्ट मैकनमारा (वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्री) संख्याओं के महारथी थे, उद्योगपति हेनरी फोर्ड द्वितीय के साथ काम कर चुके थे. मैकनमारा ने वियतनाम युद्ध में अमेरिका की जीत की संभावनाओं का आकलन चार्ट एडवर्ड लैंसडेल को दिखाया, जो पेंटागन के स्पेशल ऑपरेशंस प्रमुख थे.

लैंसडेल ने कहा कि इसमें कुछ कमी है.

मैकनमारा ने पूछा, क्या?

लैंसडेल ने कहा कि वियतनाम के लोगों के भावनाएं कहां हैं, उन्हें आंकड़ों में कैसे बांधेंगे.

युद्ध का नतीजा सबको पता है.

भारत में जीडीपी सच बताता नहीं, छिपाता है. यहां ग्रोथ की पैमाइश उत्पादन बढ़ने से होती है, लोगों की कमाई में बढ़त से नहीं, इसलिए मंदी ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया है. बड़ी कंपनियां पहले वर्ग में हैं, जिनके वित्तीय नतीजे बताते हैं कि वे टैक्स कटौती, रोजगारों की छंटनी या कीमत बढ़ाकर अपने नुक्सान वसूल रही हैं जबकि दूसरी तरफ सुधा, रवि, सुमित जैसों लाखों लोगों के लिए जीडीपी टूटा नहीं, डूब गया है. मंदी से जीतने के इनका उबरना जरूरी है.

@anshuman1tiwari

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

आवरण कथा
**ओबीसी**

# पिछड़ों के लिए संग्राम

एएनआइ

इस साल जून में ओबीसी आरक्षण के लिए थाणे में भाजपा समर्थकों का चक्का जाम आंदोलन

# जद

**(यू) प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार** ने 23 अगस्त को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ एक असहज गठजोड़ किया. तेजस्वी राज्य विधानसभा में विपक्ष के भी नेता हैं. इन दोनों ने बिहार की 10 दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर जाति आधारित जनगणना की मांग की, हालांकि केंद्र सरकार ने जुलाई में ही संसद में कह दिया था कि ''नीतिगत मामले के तहत'' जाति जनगणना 2021 की जनगणना का हिस्सा नहीं होगी.

दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों को एकजुट कर देने वाली जाति जनगणना की जोरदार मांग का मुख्य उद्देश्य ओबीसी (अन्य पिछड़ी जातियों) की संख्या तय करना है, जो हाल में चुनावी राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभावशाली मतदाता समूह के रूप में उभरे हैं. हालांकि इसका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है लेकिन धारणा है कि कुल आबादी में ओबीसी का हिस्सा 52 फीसद है (चार दशक पहले मंडल आयोग 1931 में की गई आखिरी जाति जनगणना के आधार पर इतना ही अनुमान लगाया था). लिहाजा उन्हें 27 फीसद आरक्षण मिलना चाहिए. अगर जाति जनगणना में इस धारणा की पुष्टि हो गई तो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की पुरजोर मांग उठ सकती है.

इसमें दांव पर होंगे देशभर में केंद्र और राज्यों की 90 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां और 23 लाख इंजीनियरिंग सीटों और 80,000 से ज्यादा मेडिकल सीटों समेत शैक्षिक संस्थाओं

**हर पार्टी के लिए ओबीसी वोट महत्वपूर्ण है, इसीलिए विपक्षी पार्टियां जाति जनगणना की जोरदार मांग कर रही हैं. सत्ताधारी भाजपा को अंदेशा है कि इससे उसकी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति बिगड़ जाएगी और अगड़ी जाति का मुख्य जनाधार बिखर जाएगा**

कौशिक डेका

में दाखिले. भाजपा नीत केंद्र सरकार दूसरे जाति समूहों, खासकर अगड़ी जातियों की नाराजगी मोल लेने के डर से यथास्थिति बदलने से हिचक रही है. लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश में अगले छह महीने के अंदर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है, जहां भाजपा दूसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है.

इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद ओबीसी समुदाय से हैं, के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट सहयोगी राजनाथ सिंह के 2018 में किए वादे से मुकर गई है. राजनाथ सिंह ने वादा किया था कि 2021 की जनगणना में ओबीसी की संख्या जुटाई जाएगी. इस बीच दूसरी राजनैतिक पार्टियां इस मांग के जरिए न केवल ओबीसी को रिझाना चाहती हैं बल्कि भाजपा को उसके चुनावी शस्त्रागार के कुछ महत्वपूर्ण हथियारों से वंचित कर देना चाहती हैं.

विकासशील समाज अध्ययन केंद्र (सीएसडीएस) ने पाया कि भाजपा का ओबीसी वोट प्रतिशत 2009 में 22 फीसद से बढ़कर 2019 में 44 फीसद हो गया. 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 312 सीटें जीतीं और उसका ओबीसी वोट प्रतिशत 47 फीसद था. फिलहाल राज्य में उसके 32 फीसद विधायक ओबीसी समुदाय के हैं जो 10 साल पहले के मुकाबले 20 फीसद ज्यादा हैं.

लेकिन दूसरी पार्टियां ओबीसी वोट के लिए भाजपा को चुनौती देना चाहती हैं. जाति जनगणना की मांग सिर्फ बिहार के नेताओं ने ही नहीं की है, बल्कि कांग्रेस, एनसीपी, द्रमुक, सपा और बसपा समेत लगभग सभी दूसरी गैर-भाजपाई राजनैतिक पार्टियों ने की है. भगवा पार्टी के ऐसा कराने से इनकार के कारण विपक्षी दलों को मोदी सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ नया हथियार मिल गया है. समाजवादियों और कांग्रेस ने ओबीसी सम्मेलनों का आयोजन शुरू कर दिया है और बसपा भी हंगामा कर रही है. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर संसद की संयुक्त समिति के सदस्य और बसपा के सांसद शिरोमणि वर्मा का कहना है, ''हमने हमेशा कहा है कि ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए और इसके लिए उन्हें आबादी में अपना हिस्सा मालूम होना चाहिए.''

मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी की एक बात और है कि जद (यू) और अपना दल जैसे गठबंधन सहयोगियों ने भी यही राग अलापना शुरू कर दिया है. यहां तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने भी इस विचार पर मुहर लगाई है. आयोग के चेयरमैन डॉ. भगवान लाल सहनी का कहना है, ''आयोग का मानना है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए. अब सरकार के काम करने की बारी है.''

मुश्किल में फंस चुकी भाजपा का अब कहना है कि पार्टी ''सिद्धांतत:'' इस विचार के विरुद्ध नहीं है लेकिन इस मुद्दे पर ''व्यापक सहमति'' चाहती है. पार्टी के भीतर भी विरोधाभास हैं. पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा में यह मांग उठाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री व ओबीसी नेता

## ओबीसी आबादी के अनेक आंकड़े

पिछले चार दशकों में ओबीसी की जनसंख्या

| | |
|---|---|
| मंडल आयोग 1980 | 52% |
| 1999-2000* | 35% |
| 2004-05* | 41% |
| 2011-2012** | 44% |
| 2015-16# | 43.4% |
| 2019-20## | 43.8% |

*स्रोतः *नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन; **एम्प्लायमेंट ऐंड अनएम्प्लायमेंट सिचुएशन एमंग सोशल ग्रुप्स, 2011-12 ; # नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16; ## पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20*

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

चंद्रदीप कुमार

# राज्यवार आरक्षण व्यवस्था

अपनी ओबीसी आबादी के लिए देश के विभिन्न राज्यों ने आरक्षण का कितना कोटा तय किया है

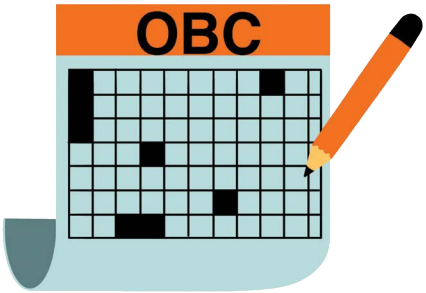


● ओबीसी आबादी की हिस्सेदारी (%)
● ओबीसी आरक्षण (%)

** आंकड़े अविभाजित आंध्र प्रदेश के #तेलंगाना सरकार की वेबसाइट से राज्य सरकार के आंकड़े*
*स्रोतः नेशनल सैंपल सर्वे 2011-12*

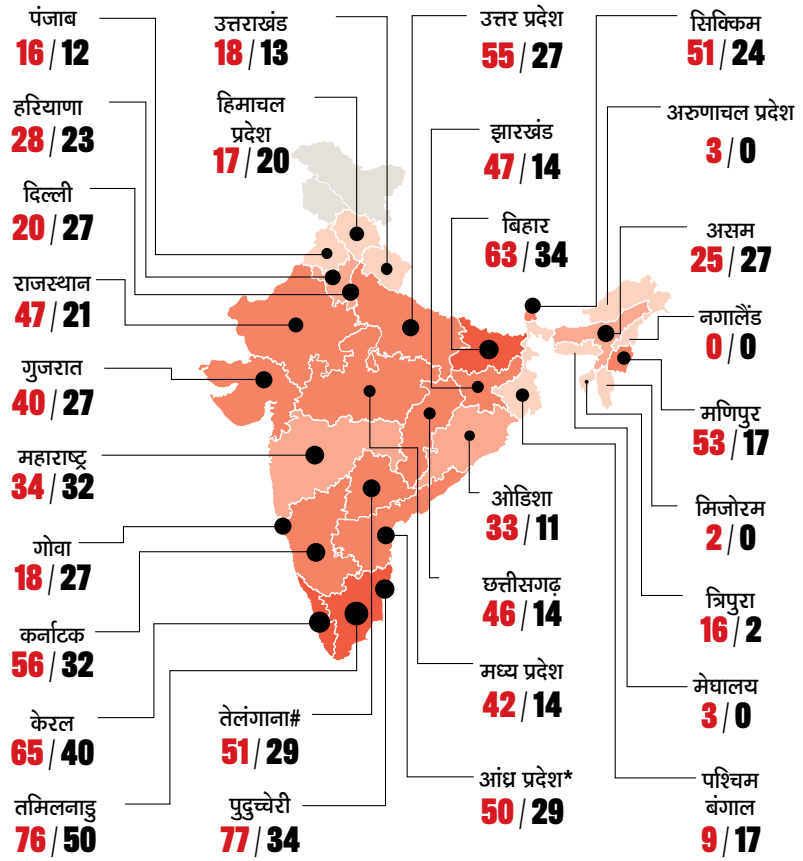

जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य के अन्य नेता

धर्मेंद्र प्रधान ने जाति आधारित जनगणना को ''क्रांतिकारी प्रक्रिया'' करार दिया. ओबीसी संसदीय संयुक्त समिति के सदस्य और भाजपा सांसद राजेश वर्मा का कहना है, ''प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं. हमने इस विचार को खारिज नहीं किया है लेकिन इस मुद्दे पर संसद में पहले बहस होनी चाहिए.''

## जाति जनगणना की अचानक मांग क्यों

जाति जनगणना की मांग में तेजी 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद शुरू हुई, जिसमें अदालत ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में 27 फीसद ओबीसी कोटे को समुदायों के पिछड़ेपन के प्रायोगिक आंकड़ों की कमी की वजह से खारिज कर दिया था. लेखक, पुणे विश्वविद्यालय में महात्मा फुले चेयर के प्रमुख और ओबीसी एक्टिविस्ट प्रो. हरि नरके कहते हैं, ''राज्य जाति जनगणना इसलिए चाहते हैं क्योंकि 9,00,0000 ओबीसी प्रतिनिधि देश में अपना पद गंवा सकते हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र में 56,000 हैं.''

देश की जनगणना में एससी/एसटी की गणना होती है जबकि दूसरी जातियों—'सामान्य' (मुख्यत: अगड़ी जातियां) और ओबीसी—की गणना नहीं की जाती. एससी/एसटी को कुल आबादी में उनकी संख्या क्रमश:—15 और 7.5 फीसद—के अनुपात में सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण

## राजनैतिक ताकत

### लोकसभा में ओबीसी सांसद

पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा की व्यापक विजय ऊंची जाति के सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ हुई जबकि ओबीसी का हिस्सा भी बढ़ा

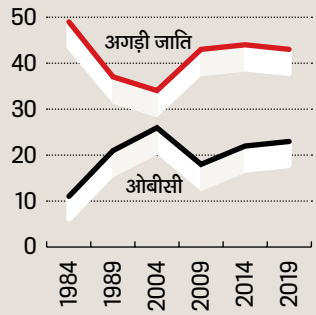


स्रोतः सीएसडीएस और लोकसभा के आंकड़े

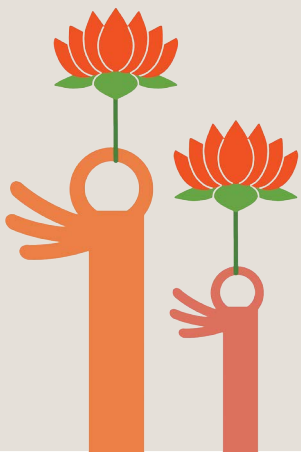

### लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोटों का रुख

पिछले 10 सालों में भाजपा के लिए ओबीसी वोटों का समर्थन दोगुना हो गया है जबकि कांग्रेस और अन्य दलों के प्रति समर्थन में भारी गिरावट आई है

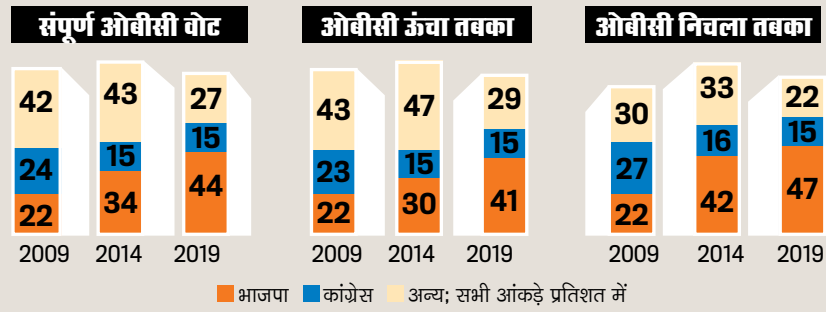


### यूपी-बिहार में क्यों अहम हैं ओबीसी वोट

उत्तर प्रदेश में भाजपा ने ओबीसी वोटों का बड़ा हिस्सा हथिया लिया जबकि बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोट राजद को चले गए

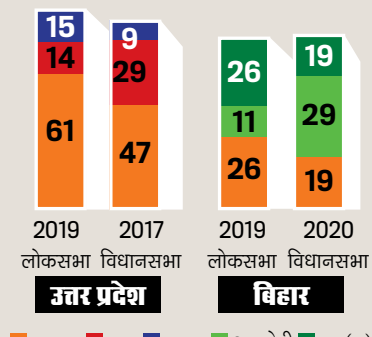


सभी आंकड़े प्रतिशत में

### यादवों की चुनौती

ओबीसी में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले यादव उत्तर प्रदेश और बिहार में सपा और राजद के प्रति वफादार रहे

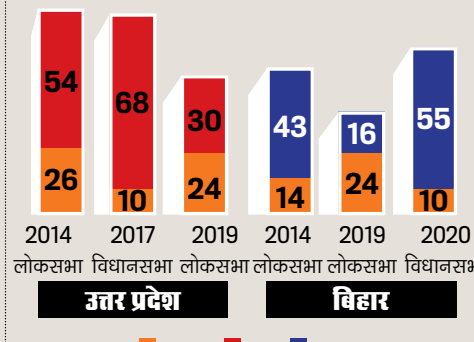


सभी आंकड़े प्रतिशत में

दिया गया है.

सरकार कानूनी बाधा के कारण अपनी मर्जी से ओबीसी आरक्षण में इजाफा नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में फैसला सुनाया था कि नौकरियों में 50 फीसद से ज्यादा आरक्षण जाति पर आधारित नहीं हो सकता. आरक्षण में एससी और एसटी का हिस्सा 23 फीसद होने की वजह से ओबीसी का हिस्सा बढ़ाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है. प्रायोगिक आंकड़े जाति आधारित जनगणना से ही मिल सकते हैं, लिहाजा इसकी मांग बढ़ गई; इसी से चुनावी उद्देश्य भी सध जाएगा. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं, ''भाजपा सांसद और सहयोगी दलों समेत राजनैतिक फलक के ज्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया और जाति जनगणना की मांग की है.''

ओबीसी मुद्दे उठाने की बेसब्री इन समुदायों के चुनावी महत्व की वजह से अचानक उभरी है. पिछले तीन दशकों में यह समुदाय—या इसके घटक—सपा, राजद और जद (यू) जैसी जाति आधारित पार्टियों की रीढ़ रहे और वे दो राष्ट्रीय पार्टियों—भाजपा और कांग्रेस—के बदलते भाग्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं. इसकी भव्य एकता संसद से ज्यादा कहीं और नहीं दिखती. हाल में संपन्न संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने पेगासस जासूसी प्रकरण में सरकार की भूमिका का विरोध करते हुए किसी बहस में हिस्सा नहीं लिया. लेकिन जब राज्यों को किसी भी जाति समूह को ओबीसी घोषित करने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक आया तो सभी पार्टियों ने न केवल बहस में हिस्सा लिया बल्कि एक साथ इस विधेयक के पक्ष में वोट भी कर दिया.

### ओबीसी जनगणना के प्रति भाजपा की अनिच्छा

कई राजनैतिक विश्लेषकों का कहना है कि जाति आधारित जनगणना से भाजपा और उसके पारंपरिक जातीय समीकरण के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति खड़ी हो सकती है. हालांकि भाजपा की मातृ संस्था आरएसएस के सह-सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अगस्त में दोहराया कि

## अब तक का सफर

# हाथ आया कम हिस्सा

ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में रिक्तियां इशारा करती हैं कि कोटे का लाभ निचले स्तर के लाभार्थी तक नहीं पहुंचा

### केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 50 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली हैं

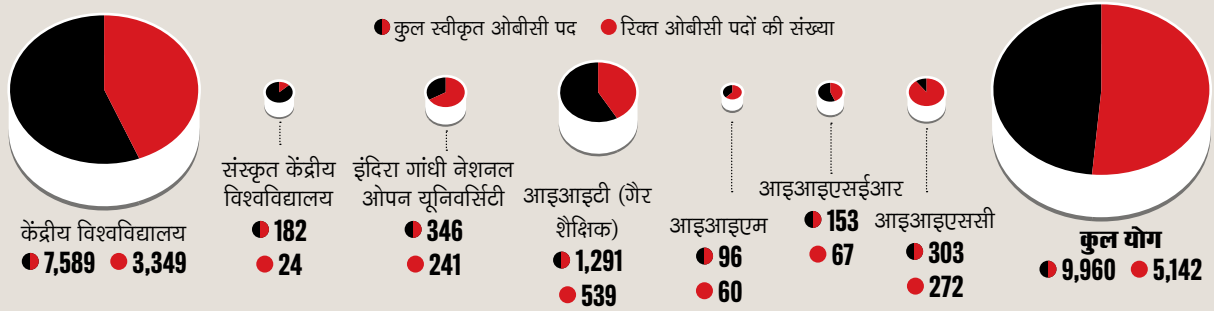


*स्रोतः संसद के आंकड़े, 15 मार्च, 2021*

### केंद्र सरकार के विभागों में ओबीसी रिक्तियां

ओबीसी के लिए आरक्षित पद जो नहीं भरे गए

केंद्र सरकार के मंत्रालयों में ओबीसी का हिस्सा

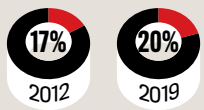


*स्रोतः संसद के आंकड़े, 15 मार्च, 2021*

### काम में नहीं रहे उतने पिछड़े

ओबीसी की श्रमिक बल हिस्सेदारी दर–1,000 लोगों के श्रम बल में उनकी संख्या–राष्ट्रीय औसत के बराबर है

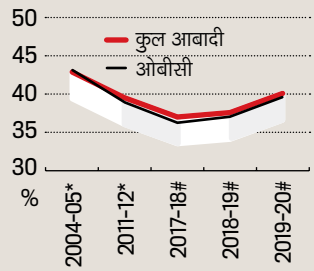


*स्रोतः एम्प्लायमेंट ऐंड अनम्प्लायमेंट सिचुएशन एमंग सोशल ग्रुप्स, 2011-12 ; #पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे*

### पढ़ाई-लिखाई का हाल

साक्षरता दर कुल आबादी के समकक्ष है लेकिन उच्च शिक्षा में हिस्सेदारी चिंता का विषय

**साक्षरता दर**

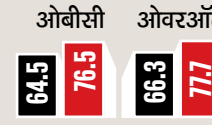


*स्रोतः *एम्प्लायमेंट ऐंड अनम्प्लायमेंट सिचुएशन एमंग सोशल ग्रुप्स, 2011-12 ; #पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे*

(आंकड़े % में)

### ओबीसी विद्यार्थियों की हिस्सेदारी

**प्राथमिक शिक्षा**

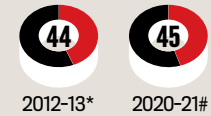


*स्रोतः *स्टेटिस्टिकल ईयर बुक ऑफ इंडिया 2012-13; #द यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, 2021*

**उच्च शिक्षा**

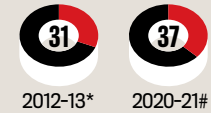


*स्रोतः ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे*

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

> **राज्य जाति जनगणना इसलिए चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में 9,00,0000 ओबीसी प्रतिनिधि अपना पद गंवा सकते हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र में 56,000 हैं**
>
> **प्रो. हरि नारके**
> *प्रमुख, महात्मा फुले चेयर, पुणे यूनिवर्सिटी*

संघ आरक्षण का पुरजोर समर्थन करता है लेकिन संघ जाति जनगणना के बारे में कुछ भी कहने से बच रहा है. इस विषय पर आरएसएस की समझ को, होसबले के पूर्ववर्ती सुरेश भैयाजी जोशी ने 2011 में रखा था. उन्होंने कहा था कि जाति आधारित जनगणना बाबा साहेब आंबेडकर जैसे नेताओं की तरफ से परिकल्पित जातिविहीन समाज के विचार के खिलाफ थी.

लेकिन, बात बस इतनी भर नहीं है. भाजपा पहले दो अगड़ी जाति समूहों—ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी के रूप में उभरी थी लेकिन इसने बाद में समझ लिया कि केवल अगड़ी जाति के वोटों के बूते राजनीति में कामयाबी की ऊंची सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा सकतीं. खासकर तब, जब वी.पी. सिंह के मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद ओबीसी जातियों ने महत्वपूर्ण राजनैतिक जमीन प्राप्त कर ली हो. इसके बाद पार्टी ने 'मंडल' की राजनीति के जवाब में 'हिंदुत्व' पर ध्यान केंद्रित कर राजनैतिक आधार को व्यापक बनाया. उसने एक

ऐसा विस्तृत दायरा तैयार किया जिसमें सभी हिंदू शामिल थे, चाहे वे किसी भी जाति से आते हों. यही वजह है कि भाजपा ने 1985 में अपनी भोपाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंडल आयोग को लागू करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन बाद में अपना रुख बदल लिया और मंडल मुद्दे पर वी.पी. सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और अयोध्या राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया, जिसने उसे ओबीसी और दलितों को हिंदू के रूप में एकजुट करने में मदद की.

विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा को डर है कि जाति जनगणना हिंदू वोटों को विभाजित कर देगी. इससे उसे ओबीसी के बीच अपनी पैठ मजबूत करने में मदद तो मिल सकती है, लेकिन सवर्णों की तीखी प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ सकता है. सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार कहते हैं, ''अगर हमारे पास वास्तविक आंकड़े होंगे तो जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियां ओबीसी आरक्षण की 27 फीसद की सीमा को हटाने की मांग उठा सकती हैं.''

आरक्षण ढांचे में बदलाव की कोई भी मांग सामाजिक अशांति और सवर्णों की ओर से तीव्र विरोध को फिर से जन्म दे सकती है जैसा कि मंडल आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद देखा गया था. और भाजपा अपने मूल मतदाता आधार, सवर्णों को ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकती. पटना में एक भाजपा नेता कहते हैं, ''भाजपा के पास अल्पसंख्यक वोटों का सहारा नहीं है. हो सकता है कि ओबीसी के बीच हमारा प्रभाव थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन इसका असली फायदा तो क्षेत्रीय दलों को होगा. जाति जनगणना में जोखिम-फायदे का अनुपात हमारे पक्ष में नहीं दिखता है.''

वास्तव में, ओबीसी वोट बैंक को लुभाने की कोशिशों के बीच पार्टी हमेशा इस बात को लेकर चौकन्नी रही है कि सवर्णों के हितों को चोट न पहुंचे. 2019 में, मोदी सरकार ने सामाजिक ढांचे में ऊंची जगह रखने वाले समूहों, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यू) सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की. समाज विज्ञानी सुधा पई कहती हैं, ''कोई भी सरकार सवर्णों की नाराजगी को लेकर चिंतित होगी. हालांकि यह ओबीसी के हितों की हिमायती होने का दावा करती है लेकिन भाजपा, आखिरकार सवर्णों की ही पार्टी है. इसलिए, उसकी चिंता बड़ी है.''

कई **विश्लेषक इस विश्लेषण** को नहीं स्वीकारते कि भाजपा को सवर्णों के विरोध का डर सता रहा होगा. अशोक यूनिवर्सिटी में आर्थिक डेटा और विश्लेषण के निदेशक अश्विनी देशपांडे कहते हैं, ''धर्म के इर्द-गिर्द बहुत संघर्ष और हिंसा है, लेकिन यहां केवल एक धर्म के लोगों की गिनती की जा रही है. गिनती से विवाद नहीं होता है. संघर्ष का वातावरण तो ध्रुवीकरण के एजेंडे वाले समूहों की तरफ से बनाया जाता है.'' लखनऊ में गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर प्रशांत के. त्रिवेदी पिछले तीन दशकों में आकर्षक कॉर्पोरेट नौकरियों के अवसर बनने के साथ देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखते हैं. वे कहते हैं, ''सरकारी नौकरियों को लेकर पुरानी सोच में बहुत बदलाव आ गया है. अब इसके लिए करो या मरो वाली पुरानी स्थिति नहीं रही.''

लेकिन कुछ अन्य आशंकाएं भी हैं जिसके कारण भाजपा जाति जनगणना से हिचकिचा रही है. गुजरात में पाटीदार, महाराष्ट्र में

## ऐसे शुरू हुआ जाति जनगणना का फेर

**पिछड़ी जातियों की आबादी की गिनती से इनकार करने वाली मोदी सरकार पहली नहीं. आजादी के बाद एक के बाद एक सरकारें इससे कतराती रही हैं**

**1953** ओबीसी के लिए बने पहले केलकर आयोग ने 1961 की जनगणना में आबादी की जातिवार गिनती करने की वकालत की थी

**1980** मंडल आयोग ने उसी सुझाव को दोहराया; (फोटो में) बी.पी. मंडल अपनी रिपोर्ट तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को सौंपते हुए

> **कोई भी सरकार सवर्णों की नाराजगी को लेकर चिंतित होगी. हालांकि भाजपा ओबीसी के हितों की हिमायती होने का दावा करती है लेकिन वह, आखिरकार सवर्णों की ही पार्टी है इसलिए उसकी चिंता बड़ी है**
>
> **सुधा पई**
> *समाजशास्त्री*

**1995** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2001 की जनगणना में जाति/समुदाय व्यापी आबादी के आंकड़े जुटाने की सिफारिश की

**2006** भाजपा नेता सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने ओबीसी जनगणना की सिफारिश की

**2008** योजना आयोग ने 2011 की जनगणना में ओबीसी की गिनती शामिल करने की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव पारित किया (तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होने के नाते इस पर दस्तखत किए थे)

**2010** नासिक से सांसद समीर भुजबल ने लोकसभा में ओबीसी जनगणना पर निजी प्रश्न उठाया. नतीजतन, सदन में भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे, कांग्रेस के मंत्री वीरप्पा मोइली, जद (यू) नेता शरद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और रालोद के अध्यक्ष अजित सिंह सहित 100 सांसदों के समर्थन से लाए गए प्रस्ताव का नतीजा 2011 में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के रूप में सामने आया

**2015** जाति के आंकड़ों में विसंगतियां बताते हुए मोदी सरकार ने जातियों के नामों की श्रेणियां और वर्ग बनाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की. इस कवायद का अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया

**2016** केंद्र ने जातिगत गणना वाला हिस्सा छोड़कर एसईसीसी के बाकी आंकड़े प्रकाशित किए

**2020** भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने जाति जनगणना के प्रस्ताव पर फिर जोर दिया

**2021** अप्रैल में एनसीबीसी ने एक मामले में ओबीसी की गणना का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने की सलाह दी. शीर्ष अदालत जाति जनगणना की मांग करने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही है

मराठा और हरियाणा में जाट जैसे कई प्रमुख जाति समूह ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर अक्सर हिंसक आंदोलन करते रहे हैं. इन विवादास्पद मांगों को हल किए बिना जातियों की कोई भी गिनती केंद्र के लिए बहुत संकटपूर्ण स्थिति बना सकती है. कुछ जाति समूहों के आधिकारिक वर्गीकरण पर भी कोई स्पष्टता नहीं है. उदाहरण के लिए, जाटों को राजस्थान में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है लेकिन हरियाणा या केंद्रीय सूची में नहीं. कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में ब्राह्मणों को भी ओबीसी सूची में जगह मिली है. भाजपा के ओबीसी विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. लक्ष्मण कहते हैं, ''कई व्यावहारिक मुद्दे हैं, जिन्हें पहले हल करने की जरूरत है. अन्यथा, यह 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) की तरह ही खामियों भरी कसरत साबित होगी.''

सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक और ओबीसी के उप-वर्गीकरण पर गठित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के सदस्य जे.के. बजाज इस बात से सहमत हैं कि एसईसीसी में विसंगतियां थीं, लेकिन उन्हें लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गणनाकर्ताओं के पास जातियों की सूची नहीं थी. बजाज कहते हैं, ''कर्नाटक ने हाल के वर्षों में वास्तविक गणना से पहले सभी जातियों की एक व्यापक सूची के आधार पर एक राज्य स्तरीय जाति जनगणना की है.'' वे आगाह करते हैं कि यह लंबी कवायद होगी, जिसमें समय लग सकता है और यह वर्तमान जनगणना में संभव नहीं हो सकता. कोविड महामारी के कारण पहले ही इसमें काफी देर हो चुकी है.

भाजपा नेता अब बड़ी चतुराई से गेंद राज्य सरकारों के पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा सांसद और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण पर संसदीय समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश सिंह का कहना है कि ''केंद्र ओबीसी की गिनती करे या न करे, लेकिन राज्यों को अपने दम पर यह कवायद शुरू करनी चाहिए.'' भाजपा का अनुमान है कि कोई भी राज्य इसका जोखिम नहीं लेना चाहेगा क्योंकि परिणाम राजनैतिक और सामाजिक संतुलन को गंभीर रूप से बिगाड़ सकते हैं. 2015 में, कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक 'सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण' किया था, जहां जाति का भी अलग जिक्र किया गया था लेकिन इसके परिणाम न तो कांग्रेस सरकार ने और न ही उसके बाद भाजपा की सरकार ने जारी किए. लीक हुए निष्कर्षों में अनुमान लगाया गया है कि राज्य के सबसे प्रभावशाली जाति समूहों में से एक लिंगायतों की आबादी 10 प्रतिशत (18 प्रतिशत के पहले के दावों के विपरीत) से भी कम है. राज्य के दो प्रमुख जाति समूहों—लिंगायतों और वोक्कालिगाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने इस सर्वेक्षण के परिणामों को सार्वजनिक किए जाने पर विरोध की धमकी भी दी थी.

भाजपा को लगता है कि राज्य इस तरह की कवायद से इस डर से कन्नी काटेंगे क्योंकि उन्हें आरक्षण का दायरा फिर से तय करना होगा. उदाहरण के लिए, कर्नाटक ओबीसी को 32 प्रतिशत आरक्षण देता है.

2015 की जाति गणना में कथित तौर पर पाया गया कि कुल आबादी में 24 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति का है, जो उन्हें सबसे बड़ा समूह बनाता है. इससे वे अभी तक प्राप्त 15 प्रतिशत से अधिक आरक्षण कोटे की मांग कर सकते हैं.

## क्या भारत को जाति जनगणना की जरूरत है?

अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि जातिगत पहचान भारत के सामाजिक-राजनैतिक अस्तित्व की वास्तविकता है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज के प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पूछते हैं, ''जब संवैधानिक रूप से ओबीसी नामक एक श्रेणी बनाई गई है तो इस समूह की गिनती के सवाल पर बहस क्यों होनी चाहिए?''

भाजपा के प्रतिद्वंद्वियों का तर्क है कि जाति की गिनती से सरकार को बेहतर नीतियां और कल्याणकारी कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी. राजद के राज्यसभा सांसद और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के प्रोफेसर मनोज के. झा कहते हैं, ''जाति जनगणना का उद्देश्य केवल पिछड़ी जातियों की संख्या की जानकारी प्राप्त करना नहीं है. यह एक बड़ी आबादी को सामाजिक-आर्थिक सोपान में उसकी वास्तविक स्थिति का आईना दिखाएगा. भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में नीति-निर्माण और सामाजिक संतुलन के लिए, एक जनगणना अनिवार्य है.'' जद (यू) के एक शीर्ष नेता का कहना है कि पार्टी समझती है कि जाति जनगणना से राज्य को ओबीसी में उन वर्गों की पहचान करने में मदद मिलेगी जो अभी भी समाज कल्याण की जद से बाहर हैं.

संसद में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में करीब 21 फीसद कार्यबल ओबीसी समुदाय से है. जहां प्राथमिक शिक्षा में ओबीसी की हिस्सेदारी 45 फीसद है, वहीं उच्च शिक्षा में उनका हिस्सा घटकर 37 फीसद रह गया है. भाजपा के लक्ष्मण का तर्क है कि गणना पर जोर के बजाए, कई राज्यों को आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है क्योंकि 15,000 अधिसूचित ओबीसी समुदायों में से 9,500 को इसका लाभ भी नहीं मिलता है. नारके का कहना है कि सरकार को ओबीसी के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर और अधिक खर्च करने की जरूरत है और इसके लिए गिनती जरूरी है. उनका दावा है, ''इस साल के बजट में केंद्र ने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए प्रति ओबीसी व्यक्ति सिर्फ 18 रुपए आवंटित किए.'' गणेश सिंह स्वीकारते हैं कि आंकड़ों की कमी, ओबीसी बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने में बाधक बने हैं. उनका कहना है, ''इसीलिए मैंने ओबीसी के लिए एक अलग फंड का सुझाव दिया.''

## भाजपा इस चक्रव्यूह से निकलने को क्या कर रही है

जहां केंद्र ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है, वहीं भाजपा ने पहले ही विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रामक शुरुआत कर दी है. 4 मार्च के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद भगवा पार्टी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया, जिसमें आरोप लगाए गए कि ठाकरे सरकार स्थानीय निकायों में ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित कराने में विफल रही है. पार्टी ने यह भी घोषणा की कि अगर आरक्षण

10 अगस्त को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ अन्य कांग्रेसी नेता ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए

बहाल नहीं किया गया, तो वह आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में केवल ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी. ठाकरे सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार से ओबीसी पर 2011 के एसईसीसी डेटा की मांग की ताकि वह इसे अदालत में अनुभवजन्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सके. विडंबना यह है कि पिछली देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली भाजपा-शिवसेना सरकार ने भी केंद्र से इसी तरह की अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.

भाजपा का ध्यान जवाबी कार्रवाई के अलावा अपनी छवि को सही करने पर भी है. मोदी मंत्रिपरिषद में ओबीसी सदस्यों की हिस्सेदारी मई 2019 के 13 से बढ़कर अब 27 हो गई है. और पार्टी चाहती है कि मतदाता इस पर ध्यान दें. पार्टी ने 27 ओबीसी मंत्रियों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया. 127वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद, भाजपा अन्य बातों के अलावा ओबीसी को सशक्त बनाने के लिए केंद्र की ओर से किए गए कामों को प्रदर्शित करने के लिए देश भर में 70 'मोदी समर्थन सम्मेलन' आयोजित करने की योजना बना रही है.

जुलाई में केंद्र ने अखिल भारतीय कोटे के तहत चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ओबीसी छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की. ओबीसी के क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा भी 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है (जो कि एनसीबीसी की सिफारिश के अनुसार 16 लाख रुपए तक भी जा सकती है). एनसीबीसी को मोदी सरकार में ही संवैधानिक दर्जा मिला. वहीं, भाजपा ओबीसी वोटों पर जाति आधारित पार्टियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए भी लगातार काम कर रही है. भाजपा ने विभिन्न राज्यों में हाशिए पर पड़े ओबीसी समुदायों को रिझाने के बीच यह चर्चा शुरू कराई है कि क्षेत्रीय दल केवल प्रभावशाली ओबीसी जातियों की मदद करते हैं और इस तरह पूरे ओबीसी समुदाय के हिस्से का लाभ सिर्फ कुछ जातियां हथिया लेती हैं. सीएसडीएस के प्रो. कुमार कहते हैं, ''हर राज्य में प्रमुख ओबीसी जातियां एक विशेष पार्टी का समर्थन करती हैं. मसलन, ओबीसी यादव बिहार में राजद और उत्तर प्रदेश में सपा का

एएनआइ

> **जाति जनगणना का उद्देश्य केवल पिछड़ी जातियों की संख्या की जानकारी प्राप्त करना नहीं है. यह एक बड़ी आबादी को सामाजिक-आर्थिक सोपान में उसकी वास्तविक स्थिति का आईना दिखाएगा**

**मनोज के. झा**
*राजद के राज्यसभा सांसद और प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क*

समर्थन करते हैं, लिंगायत कर्नाटक में जद (एस) का समर्थन करते हैं और कुर्मी बिहार में जद (यू) के लिए मतदान करते हैं. जहां ये क्षेत्रीय दल अपनी मूल समर्थन जाति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने बुद्धिमानी से अन्य ओबीसी जातियों को संगठित करने की कोशिश की है जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है.''

यादवों के खिलाफ भाजपा का अभियान उत्तर प्रदेश में फायदेमंद रहा क्योंकि पार्टी ने पिछले दो लोकसभा चुनावों और 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर-यादव ओबीसी वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल किया. दूसरी ओर, कुर्मी बहुल अपना दल, राजभर बहुल एसबीएसपी और निषाद पार्टी जैसी गैर-यादव ओबीसी पार्टियों से भाजपा का गठबंधन बहुत कारगर रहा.

**आलोचक अब मान रहे हैं** कि मोदी सरकार गैर-प्रमुख ओबीसी जातियों के बीच अपना आधार मजबूत करने के लिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट का उपयोग कर सकती है. उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में 2017 में गठित चार सदस्यीय आयोग ने इस बात की जांच की है कि ओबीसी को मिला 27 प्रतिशत आरक्षण किस प्रकार लागू किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, आयोग ने पाया कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए दिए गए आरक्षण लाभ का 50 प्रतिशत, ओबीसी में शामिल करीब 6,000 जातियों और समुदायों में से केवल 40 जातियों ने हथिया लिया था. 27 फीसद ओबीसी आरक्षण कोटे के एक-चौथाई हिस्से पर सिर्फ 10 जातियों का एकाधिकार है. यह भी पाया गया कि ओबीसी समुदायों के करीब 20 प्रतिशत लोगों को 2014 से 2018 तक आरक्षण कोटे का कोई लाभ नहीं मिला. समिति आरक्षण लाभ के समान वितरण के लिए केंद्रीय ओबीसी सूची में 2,633 ओबीसी उप-जातियों को चार समूहों में विभाजित करने की सिफारिश कर सकती है.

विशेषज्ञ उप-वर्गीकरण की इस कवायद को सही नहीं मान रहे, खासकर जाति गणना के अभाव में. प्रो देशपांडे पूछते हैं, ''सरकार की ओर से नियुक्त आयोग उप-वर्गीकरण के बारे में बात करता है, पर जब तक हमारे पास जातिवार आंकड़े नहीं होंगे, हम कैसे जानेंगे कि समान वितरण हुआ या नहीं?'' फिर भी, ओबीसी जातियों का उप-वर्गीकरण कोई नई अवधारणा नहीं है. पहले से ही 11 राज्यों—पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और पुदुच्चेरी—में ऐसी व्यवस्था है.

दलितों के उप-वर्गीकरण की व्यवस्था, जिसमें कई उपेक्षित दलित जातियों के महादलित के रूप में वर्गीकरण किया गया, से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अतीत में बहुत फायदे हुए हैं. इस तरह के प्रयोग को दोहराने के मकसद से आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए मई 2018 में एक सामाजिक न्याय समिति बनाई. समिति ने ओबीसी को तीन वर्गों—पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा और सबसे पिछड़ा वर्ग—में विभाजित करने की सिफारिश की लेकिन उनकी सरकार इन सिफारिशों को लागू करने में टालमटोल करती आई है. इस ढुलमुल रवैये के साथ जाति जनगणना कराने से इनकार के कारण भाजपा के कुछ सहयोगी दल उससे छिटक गए हैं. भाजपा के सहयोगी रहे—एसबीएसपी और मौर्य समुदाय के प्रभुत्व वाला महान दल—दोनों दल अब सपा से घनिष्ठता बढ़ा रहे हैं.

आगे और नुक्सान से बचने के लिए, भाजपा को ओबीसी समूहों को एक छत के नीचे मजबूती से खड़ा करने के लिए एक नया फॉर्मूला खोजना होगा. इसने अतीत में ऐसा सफलतापूर्वक किया है जब भाजपा उत्तर प्रदेश में विपक्ष में थी. लेकिन केंद्र में सत्ताधारी दल के रूप में सात साल (और यूपी में चार साल) में पार्टी को अपने वादों और उन वादों को पूरा करने के बीच, बिल्कुल वैसा ही संतुलन बनाना पड़ा है जैसा रस्सी पर चलने के दौरान जरूरी होता है.■

—साथ में **अमिताभ श्रीवास्तव** और **अनिलेश एस. महाजन**

# भगवा दल को अन्नदाता की चुनौती

कृषि कानूनों के विरोध में आयोजित महापंचायत में किसान नेताओं ने भाजपा विरोधी सुर फूंका. काश्तकारों के मोहभंग के मद्देनजर अगले साल विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के लिए मुश्किलें आने का अंदेशा

**आशीष मिश्र**

मनीष अग्निहोत्री

**ताकत का प्रदर्शन**
मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में डायस के पास खड़े राकेश टिकैत

पश्चिमी यूपी के जिले मुजफ्फरनगर में 2013 के सांप्रदायिक दंगों के आठ साल बाद पहला मौका था जब पूरे जिले में सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम थे. कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पिछले नौ महीने से पश्चिमी यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर अपने आंदोलन को विस्तार दे रहे थे. संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान आयोजित किसान महापंचायत के आयोजन स्थल मुजफ्फरनगर राजकीय इंटरमीडिएट कालेज (जीआइसी) की ओर जाने वाली सभी सड़कों के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात था. सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी महापंचायत में भाग लेने वाले किसानों का उत्साह कम नहीं कर पाए. 5 सितंबर की सुबह 10 बजे महापंचायत शुरू होने से पहले जीआइसी ग्राउंड यूपी समेत देश के करीब 13 प्रदेशों से आए करीब डेढ़ लाख किसानों से भर गया था. जीआइसी ग्राउंड में जगह न होने से डेढ़ लाख के करीब किसान मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जमा थे. संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में पहली बार देश भर के 40 किसान संगठन एकसाथ मंच पर मौजूद थे.

महापंचायत उस वक्त अपने चरम पर पहुंची जब दोपहर एक बजे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे. टिकैत ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी, किसानों को एमएसपी की गारंटी, गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग उठाने के साथ 27 सितंबर को ''भारत बंद'' करने की घोषणा की. महापंचायत के जरिए ''मिशन यूपी'' की शुरुआत कर रहे टिकैत ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाहरी बताते हुए इन्हें यूपी से भगाने का आह्वान भी किया. मौजूद किसानों की सहानुभूति बटोरने के लिए राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्र की भाजपा सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक वे अपने घर नहीं जाएंगे, चाहे आंदोलन स्थल पर ही बलिदान क्यों न हो जाए. राजनैतिक दलों से दूरी बनाने वाली महापंचायत में यूपी-उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने का जिस तरह आह्वान किया गया, उससे किसान आंदोलन की राजनैतिक महत्वकांक्षा भी सामने आई.

किसान आंदोलन के नेताओं को यह एहसास था कि उनकी राजनैतिक महत्वकांक्षा हिंदू-मुस्लिम एकता के बगैर पूरी नहीं हो सकती है. इसीलिए छह घंटे चली महापंचायत में बात खेती और किसानों की हो रही थी लेकिन मंच से बोलने वाला हर वक्ता 2013 को हुए मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए अमन का संदेश भी दे रहा था. किसान महापंचायत के अंत में राकेश टिकैत ने कहा ''अब भाजपा को दंगे नहीं करने देंगे. वे लोगों को तोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे. अब पहले की तरह किसानों के मंच से अल्लाह हो अकबर और हर-हर महादेव के नारे गूंजेंगे.''

यूपी में 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पश्चिमी यूपी के जिले मुजफ्फरनगर में राजनीति करवट ले रही है. पश्चिमी यूपी प्रदेश की राजनीति के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के चरणों की शुरुआत यहीं से होती है.

शुरुआती चरणों के चुनाव से ही भाजपा को चुनौती देने के लिए पश्चिमी यूपी किसान आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण हो गया है. इसीलिए किसान आंदोलन के जरिए पश्चिमी यूपी में कृषि से जुड़े दो प्रमुख समुदाय जाट और मुस्लिम में एकता का प्रयास हो रहा है. ''ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन'' के मुजफ्फरनगर जिले के संयोजक हरीश त्यागी कहते हैं, ''किसानों से जुड़ी समस्याओं पर भाजपा सरकारों के अड़ियल रवैये के चलते जाट और मुस्लिम समुदाय एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी से भाजपा की सीटों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी.'' किसान नेताओं का दावा है कि महापंचायत को मिले किसानों के भारी समर्थन को देखकर वे किसान भी सामने आएंगे जो भाजपा सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों की संख्या 3.27 करोड़ है लेकिन अगर इनमें गैर पंजीकृत किसान और खेतिहर मजदूर को भी जोड़ लें तो यह संख्या छह करोड़ से अधिक बैठती है. 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किसान यूपी की राजनैतिक का केंद्र बनते जा रहे हैं.

वर्ष 1931 की जनणना के अनुसार, पश्चिमी यूपी के छह मंडलों में जाट समाज की जनसंख्या का 99 फीसद केंद्रित है. सामाजिक न्याय समिति-2001 की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी की पिछड़ी जातियों में जाट का प्रतिशत 3.60 है. हालांकि पश्चिमी यूपी के इन छह मंडलों में इनका प्रतिशत 18 से 20 प्रतिशत है. पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में 49 ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम आबादी 30 फीसद या इससे अधिक है. करीब दो दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट और मुस्लिम मिलकर 50 फीसद से अधिक बैठते हैं. पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा का प्रमुख घटक भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जाट समुदाय की खाप पंचायतों का समर्थन बटोरने में लगे हैं. बालियान खाप से ताल्लुक रखने वाले नरेश टिकैत यूपी के सभी खापों का समूह ''सर्वखाप पंचायत'' के मुखिया भी हैं. किसान महापंचायत को पश्चिमी यूपी की प्रमुख खाप पंचायत देशखाप, गठवाला, बालियान, लाटियान, अहलावत खाप पंचायतों ने अपना समर्थन दिया था.

किसान आंदोलन से अभी तक अलग रही गठवाला खाप को महापंचायत में सबसे ज्यादा तरजीह दी गई. गठवाला खाप के थांबेदार (मुखिया) श्याम सिंह को महापंचायत की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई. मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग के पूर्व एचओडी कलम सिंह बताते हैं, ''पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन को राजनैतिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए भाकियू को जाट-मुस्लिम एकता के अलावा त्यागी, सैनी, कश्यप, गुर्जर जैसी जातियों को भी अपने साथ जोड़ना होगा. अगड़ी जातियों के साथ ये जातियां जुड़कर पश्चिमी यूपी की 60 विधानसभा सीटों पर प्रभावी साबित होती हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव में यही जातियां भाजपा के पक्ष में लामबंद हो गई थीं.'' 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में भाजपा ने रिकार्ड 102 सीटें जीती थीं.

भाजपा सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को तेज करने के लिए भाकियू प्रदेश से लेकर गांव तक के संगठन को सक्रिय

बातचीतः **नरेश टिकैत**

# ''यूपी के हर गांव में किसान आंदोलन शुरू होगा''

*किसान महापंचायत के अगले दिन 6 सितंबर की दोपहर 12 बजे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने इंडिया टुडे के एसोसिएट एडिटर आशीष मिश्र से आगे की रणनीति पर चर्चा की. बातचीत के मुख्य अंश.*

**● मुजफ्फरनगर महापंचायत के सफल आयोजन के बाद भारतीय किसान यूनियन की आगे की रणनीति क्या है?**

किसान की कोई रणनीति नहीं है. यूपी के हर गांव का किसान परेशान है. महापंचायत के बाद किसानों को अपनी शाक्ति का एहसास हुआ है. अब यूपी के हर गांव में किसान अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन करेगा.

**● किसानों आंदोलन की आड़ में भाजपा विरोधी दल अपने लिए माहौल बना रहे हैं?**

किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है. मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में आने वाले किसानों की दो दिन मजदूरी, आने-जाने का खर्च जोड़ लें तो कुल 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ है. किसानों के 35 लाख रुपए तो महापंचायत स्थल पर व्यवस्था करने में खर्च हुए हैं. भाजपा सरकार पाकिस्तान, चीन के साथ शांतिवार्ता कर सकती है लेकिन अपने देश के किसानों के साथ बैठक नहीं कर सकती. बातचीत हो, दो कदम सरकार पीछे हटे तो एक-आधा कदम किसान भी पीछे हट जाएंगे.

**● भारतीय किसान यूनियन पर हाइवे को टोल फ्री करवाने जैसी गलत मांगों पर दबाव बनाकर किसानों का समर्थन जुटाने का आरोप लग रहा है?**

हर वह मुद्दा जो किसानों को बेवजह परेशान कर रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं.

**● किसान महापंचायत के मंच से हिंदू-मुस्लिम एकता की बात पर काफी जोर दिया गया?**

भाजपा जब कमजोर पड़ती है तो वह दंगे करवाती है. 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद हिंदू-मुस्लिम एकता टूट गई थी. भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों ने हिंदू, मुस्लिम के साथ समाज के हर तबके को एक किया है. इस एकता को तोड़ने के लिए भाजपा फिर दंगे कराने की फिराक में है.

**● मुस्लिम विरोधी मतों को एकजुट करने के लिए भाजपा सरकार हिंदुत्व कार्ड खेल रही है?**

धार्मिक स्थलों का विकास तो होना चाहिए. भाजपा की मंशा को जनता बखूबी समझ रही है. हम राम के असली वंशज हैं. हमारा गोत्र रघुवंशी है. राम मंदिर निर्माण में सरकार को हम किसानों भी सहयोग लेना चाहिए था.

**●मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया?**

हमने मोदी जी के साथ योगी जी को वोट दिया है. इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी किसान विरोधी नीतियों को हम सहते रहेंगे. योगी जी का हम सम्मान करते हैं. योगी जी को भी किसानों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए.

**● क्या भाजपा को हराने के लिए भारतीय किसान यूनियन यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगा?**

किसान यूनियन चुनाव से दूर रहती है. मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा. अन्य किसान भी अपने विवेक से भाजपा के खिलाफ दूसरी राजनैतिक पार्टियों को वोट करने को स्वतंत्र हैं.

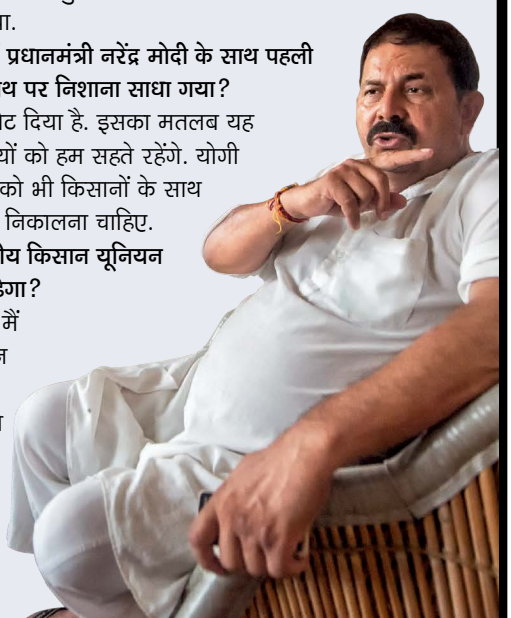

मनीष अग्निहोत्री

**''मोदी और योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों से किसानों को भटकाने के लिए भाकियू नेता कृषि कानूनों का अकारण विरोध कर रहे हैं. किसान इनकी राजनैतिक महत्वकांक्षा को विधानसभा चुनाव में सफल नहीं होने देगा''**

डॉ. चंद्रमोहन, सहारनपुर जिला प्रभारी और प्रदेश मंत्री, भाजपा

किया है. जालौन निवासी राजबीर जादौन को भाकियू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. इनकी सहायता के लिए चार उपाध्यक्ष तैनात किए गए हैं. प्रदेश के हर मंडल (कमिशनरी) में मंडल अध्यक्ष, हर जिले मे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक पर ब्लॉक अध्यक्ष और प्रत्येक गांव में गांव अध्यक्ष की तैनाती की गई है. भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष (लखनऊ) हरनाम सिंह वर्मा बताते हैं, '' हर महीने की पहली तारीख

**लंबी लड़ाई की तैयारी**
मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत में विभिन्न राज्यों के किसानों और उनके संगठनों ने हिस्सा लिया

को भाकियू की गांव की कमेटी की बैठक होती है. इसमें प्रस्ताव पारित करके किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाता है. उसके बाद इन्हीं मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा तय होती है.'' नरेश टिकैत गांव की कमेटी से मिली जानकारियों के आधार पर स्थानीय स्तर पर किसान आंदोलन की रूपरेखा तय करते हैं. इसी फीडबैक के आधार पर भाकियू ने ''अपना गांव, अपना कट'' अभियान की शुरुआत की है. इसमें हाइवे और एक्सप्रेसवे के किनारे बसे गांव के लोगों को सड़क के दूसरी ओर जाने की व्यवस्था करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है. मुजफ्फरनगर में जाट बाहुल्य सिसौली कस्बे में पिछले 43 वर्षों क्लिनिक चला रहे डॉ. बाबूराम मलिक कहते हैं ''यूपी में भाजपा विरोधी राजनैतिक दलों की निष्क्रियता ने भाजपा के विरोध में खड़ी भाकियू के लिए जगह बनाई है. भाजपा विरोधी मतदाता टिकैत बंधुओं के साथ लामबंद हो रहा है. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राजनैतिक पार्टियों से दूरी बनाने वाले टिकैत अपने समर्थकों को कैसे भाजपा विरोधी राजनैतिक पार्टियों को वोट देने को राजी कर पाते हैं?''

पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा गन्ने के दाम से जुड़ा है. यूपी में 45 लाख गन्ना किसान हैं जो पिछले तीन वर्षों से गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. मार्च, 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य अस्वीकृत, सामान्य और अगैती प्रजाति के लिए क्रमश: 310 रुपए, 315 रुपए और 325 रुपए घोषित किया था. अब किसान आंदोलन की तपिश को कम करने के लिए योगी सरकार जल्द ही गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है.

किसानों को भाजपा के विरोध में लामबंद होने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने आ रहे हैं. योगी हर महीने किसानों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं. 26 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर प्रगतिशील किसानों के साथ बैठक करके सरकार के कामकाज की जानकारी ली. किसानों से मिले फीडबैक के आधार पर योगी ने पराली जलाने पर किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा की थी. पश्चिमी यूपी के जिलों में योगी सरकार ने करीब दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की शुरुआत की है.

## इसलिए परेशान हैं किसान

- **उपज का उचित मूल्य नहीं:** बड़े किसान और अधिकारियों के गठजोड़ से फसल की सरकार खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार. छोटे किसानों को एमएसपी से काफी कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी. खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी करने पर पिछले एक साल में 50 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई
- **बढ़ी बिजली की कीमत:** 2017 में 10 हार्स पावर का नलकूप चलाने पर बिजली का रेट 900 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति माह कर दिया गया. हर महीने बिल न जमा करने पर सरचार्ज और पेनाल्टी भी वसूली जाने लगी. इससे उपज की लागत बढ़ी और किसानों को घाटा हुआ
- **मनमाना बिजली बिल:** पिछले चार वर्षों में ग्रामीण इलाकों की बिजली दरों में 40 प्रतिशत का इजाफा हो चुक है. किसानों की सबसे बड़ी समस्या मनमाने ढंग से अधिक आने वाले बिजली बिल को लेकर है. पश्चिमी यूपी के आधे से अधिक जिलों में मनमाने बिजली बिल को लेकर किसान प्रदर्शन कर चुके हैं
- **भूमि मुआवजा पर असंतोष:** यूपी में बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कार्यों के लिए किसानों की जमीन खरीदी जा रही है. शामली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बरेली समेत कई जिलों में किसान निर्धारित भूमि मुआवजे से कम मुआवजा देने का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं
- **किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी:** यूपी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले साढ़े सात लाख लोग ऐसे हैं जो लघु और सीमांत किसान नहीं हैं. प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने के साथ रकम की रिकवरी करने के आदेश दिए हैं
- **फसल बीमा का लाभ नहीं:** यूपी के दो दर्जन बाढ़ ग्रस्त जिलों के किसान फसल के नुक्सान के आकलन के लिए कराए गए सर्वे से असंतुष्ट हैं. किसानों का आरोप है कि फसल बीमा का लाभ न देने के लिए 50 फीसद से कम फसल का बाढ़ से नुक्सान सर्वे रिपोर्ट में अंकित किया जा रहा है

मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है. किसानों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने तीर्थस्थलों के विकास पर खास ध्यान दिया है. मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शुकधाम का सुंदरीकरण किया जा रहा है. सहारनपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से 19 किलोमीटर लंबे फोरलेन बाइपास रोड के निर्माण का निर्णय लिया गया है. इसके बन जाने सहारनपुर में हिंदुओं के तीर्थ स्थल शाकुंबरी देवी के मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाएगा.

योगी आदित्यनाथ ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शाकुंबरी देवी के मंदिर में पूजा करके अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी. वे एक बार फिर शाकुंबरी देवी के मंदिर से ही 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे. देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी विधानसभा चुनाव में भाजपा को किसान आंदोलन की तपिश से कितना बचा पाते हैं? ■

# खरे न उतरे तो मची खलबली

**नए दौर के रुझानों के अनुरूप और उद्योग के नजरिए से प्रासंगिक बने रहने की खातिर संघर्षरत इंजीनियरिंग संस्थान अब छात्रों के लिए पहले जैसे आकर्षक नहीं रहे. अब वे या तो बंद हो रहे या फिर सीटें कम कर रहे हैं. क्या तकनीकी शिक्षा नियामक इस रुझान को रोक पाएगा?**

अमरनाथ के. मेनन

साल 2014-15 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थानों में लगभग 32 लाख सीटें हुआ करती थीं जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है. उस ऊंचाई से फिसलते हुए स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की कुल संख्या दशक के सबसे निचले स्तर, लगभग 23.20 लाख पर आ गई है. एआइसीटीई के अध्यक्ष अनिल दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे देश में इंजीनियरिंग शिक्षा के संकट में भी एक अवसर देखते हैं. भारत के तकनीकी शिक्षा नियामक के शीर्ष पद पर अपने सातवें वर्ष में चल रहे सहस्त्रबुद्धे कहते हैं, ''इंजीनियरिंग संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी जिससे उनके पास क्षमता से अधिक सीटें हो गईं और रिक्त सीटों की संख्या भी बढ़ गई थी. इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करने या फिर सीटें कम करने की हालिया प्रवृत्ति से स्थिरता आएगी और आने वाले वर्षों में गुणवत्ता की निरंतरता सुनिश्चित होगी.''

2019-20 में एआइसीटीई ने जहां 153 नए इंजीनियरिंग संस्थानों को मंजूरी दी, वहीं 53 अन्य कॉलेजों का बंद करने का अनुरोध भी स्वीकारा. 2020-21 में कोविड-जनित व्यवधान आने से पहले ही 2015-16 से हर शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 50 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं. एआइसीटीई ने इस साल 63 कॉलेजों का संचालन बंद करने की मंजूरी दी है (देखें: खुले और बंद). इन कॉलेजों के बंद होने और छात्रों के कम दाखिले से इंजीनियरिंग सीटों की संख्या में 1,46,000 की कमी आएगी.

एआइसीटीई ने 2020 में फैसला किया कि 2022 तक किसी भी नए इंजीनियरिंग कॉलेज की अनुमति नहीं दी जाएगी और कॉलेजों की नई क्षमता के निर्माण की हर दो साल में समीक्षा की जाएगी. यह आइआइटी-हैदराबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष बी.वी.आर. मोहन रेड्डी की अध्यक्षता वाली एक सरकारी समिति की सिफारिशों के अनुरूप था. पैनल ने यह भी सुझाव दिया कि संस्थान मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे इंजीनियरिंग के पारंपरिक विषयों की सीटों को नई उभरती प्रौद्योगिकियों में बदलने पर विचार करें. अब, एआइसीटीई केवल उन नए इंजीनियरिंग कॉलेजों को मंजूरी दे रही है जो या

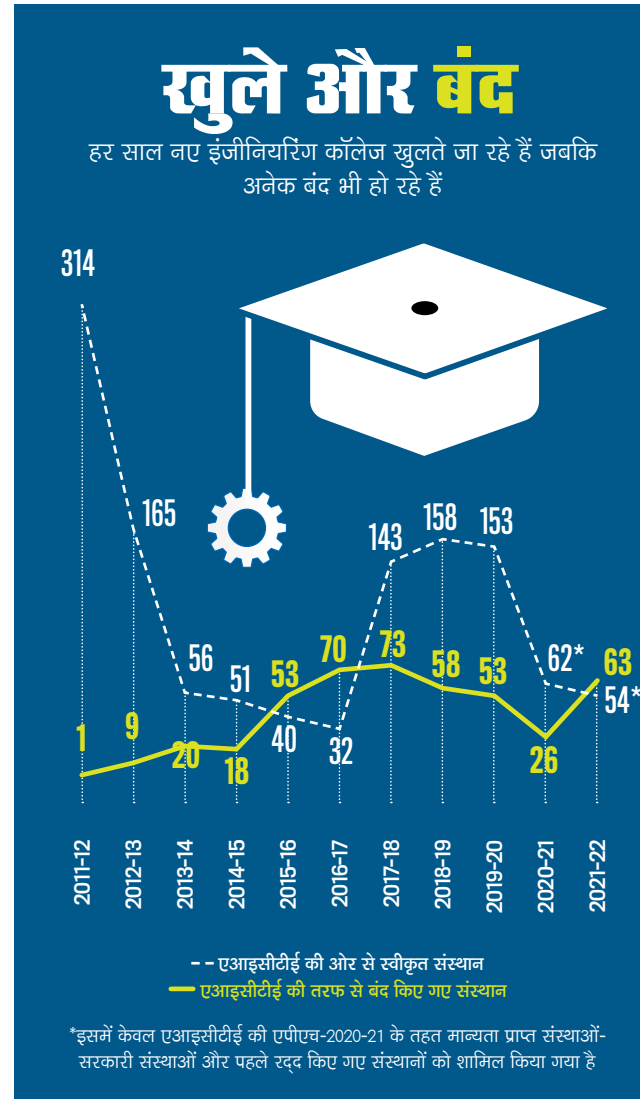


*स्रोतः एआइसीटीई*

**टेक्नोलॉजी का प्रयोग**
ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की वर्कशॉप

केवल प्रतीकात्मक तस्वीर

एम. झाजो

तो उदीयमान प्रौद्योगिकी विषयों पर फोकस करते हों या फिर पिछड़े क्षेत्रों में खोले जा रहे हों. इसने राज्यों को ''अत्यधिक रोजगारपरक व्यावसायिक विषयों'' में बीटेक कोर्स शुरू करने की अनुमति दी है.

एक अनुमान के मुताबिक, भारत में तकनीकी शिक्षा की सीटों में करीब 80 फीसद हिस्सा इंजीनियरिंग का है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें आ रहे छात्रों की संख्या में कमी देखी जा रही है. 2019 के बाद से करीब 5,63,000 सीटें खत्म हो गई हैं. इनमें से 98,476 सीटों को एआइसीटीई ने और बाकी को कॉलेजों ने खाली सीटों और भविष्य में मांग में संभावित गिरावट को ध्यान में रखकर रद्द कर दिया था. 2012-13 में जहां इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों के लिए स्वीकृत संख्या 15.4 लाख (3,363 संस्थानों में) थी वह 2020-21 में गिरकर 12.8 लाख (2,978 संस्थानों में) हो गई है. 2020-21 में कुल नामांकन 7,06,533 था.

सहस्त्रबुद्धे का कहना है कि एआइसीटीई ने इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने और इंजीनियरिंग स्नातकों की रोजगार क्षमता में सुधार करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. रोजगारयोग्य क्षमता का मूल्यांकन करने वाली फर्म एस्पायरिंग माइंड्स के 2019

## घटता आकर्षण

सीट क्षमता और दाखिलों के बीच का अंतर

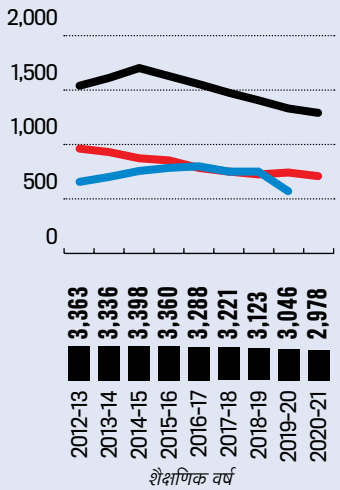


स्रोतः एआइसीटीई

के एक अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 80 प्रतिशत भारतीय इंजीनियरिंग स्नातक नॉलेज इकोनॉमी (ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास उपलब्ध संसाधनों पर नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है) में नौकरियों के लिए अयोग्य थे. सहस्त्रबुद्धे इसके लिए निगरानी और नियमन के मोर्चे पर कई खामियों को जिम्मेदार मानते हैं, जिसने भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया, बुनियादी ढांचे की समस्या खड़ी हुई, शिक्षकों की गुणवत्ता गिरी और कॉलेजों तथा उद्योगों के बीच वैसा जुड़ाव न हो सका. एआइसीटीई परीक्षा प्रणाली में सुधारों, विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप और इंडक्शन प्रोग्राम, कोर्स में लगातार संशोधन और शिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से इन खामियों को दूर करने के लिए जूझ रहा है.

### कॉलेजों के सामने चुनौतियां

इंजीनियरिंग कॉलेजों के सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें निबटना होगा. वे तेजी से महसूस कर रहे हैं कि विद्यार्थियों की पारंपरिक इंजीनियरिंग विषयों में रुचि खत्म हो रही है. साथ ही, नए मानदंडों और एआइसीटीई की तरफ से कड़ी निगरानी का मतलब है कि कई कॉलेज मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) जैसे कोर्स शुरू ही नहीं

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

बातचीत

# “हम विद्यार्थियों को उन योग्यताओं पर परख रहे हैं जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत है”

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) के चेयरमैन **अनिल दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे** ने इंजीनियरिंग शिक्षा में चल रहे सुधार पर **अमरनाथ के. मेनन** से बात की. चुनिंदा अंशः

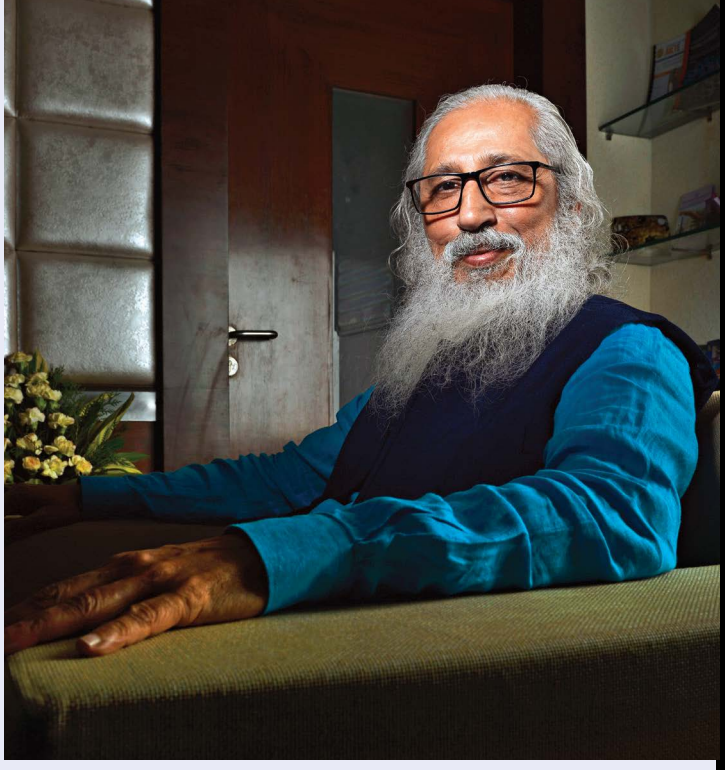

राजवंत रावत

**प्र. इंजीनियरिंग की शिक्षा को लेकर एआइसीटीई के सामने कैसी चुनौतियां आ रही हैं?**

भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के योग्य छात्रों का निर्माण करने की है क्योंकि कोर्स उद्योग या समाज की जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं. लंबे समय तक हमने ब्रिटिश विरासत को कायम रखा. इसने कुछ भी नया करने में योगदान नहीं दिया और इसलिए अब हमारे यहां नई शिक्षा नीति (एनईपी) है. मगर इंजीनियरिंग की शिक्षा में कायापलट एनईपी से पहले ही शुरू हो गया था. हमें दो चुनौतियां पेश आईं. 1980 के दशक के मध्य से 2015 तक इंजीनियरिंग संस्थाओं की संख्या कई गुना बढ़ी. क्षमता जरूरत से ज्यादा बढ़ गई और भारी संख्या में सीटें खाली हैं. इंजीनियरिंग कॉलेजों के बंद होने या सीटें कम करने का हालिया रुझान आने वाले सालों में मजबूती की तरफ ले जाएगा और लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा.

**● और क्या बदलाव लाए गए हैं?**

तीन साल से इंजीनियरिंग छात्रों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य है. कॉलेज उद्योगों के साथ सहमति पत्रों पर दस्तखत कर रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव और इंटर्नशिप के मौके हर हाल में मिल सकें. हमने इंटर्नशिप पोर्टल बनाया है जहां विद्यार्थी विकल्पों में से चुन सकते हैं कि इंटर्नशिप कहां से करें. इंटर्नशिप प्रदाता (उद्योग) और विद्यार्थी दोनों एआइसीटीई के इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म पर हैं. इससे विद्यार्थियों को एआइ-आधारित मैचमैकिंग के जरिए इंटर्नशिप मिलना मुमकिन हो पाता है.

हमने फैकल्टी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया है. चेन्नै, चंडीगढ़, भोपाल और कोलकाता के राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के पारंगत अध्येताओं की मदद से आठ मॉड्यूल बनाए हैं. इन कोर्स मॉड्यूल को पूरा करना संकाय नियुक्तियों को नियमित करने की पूर्वशर्त है.

> **अब इंटर्नशिप अनिवार्य है. हमने एआइसीटीई के प्लेटफॉर्म के जरिए उद्योगों और विद्यार्थियों के बीच संपर्क स्थापित कराया है**

फिर हमने कोर्स अपडेट करने के कई क्षेत्रों की पहचान की है. मसलन, एआइ, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनॉलिटिक्स, ऑग्मेंटेड रिएलिटी/वर्चुअल रिएलिटी और साइबर सुरक्षा. यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. हमारे यहां इन उभरते क्षेत्रों में संकाय विकास के विशेष कार्यक्रम हैं, क्योंकि 15 या और ज्यादा साल पहले हमारे अधिकांश शिक्षक ये उभरते कोर्स पढ़ नहीं पाए थे. इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम उन्हें तैयार और उत्साहित कर रहे हैं. परीक्षा सुधार पर भी फोकस है. तोतारटंत पढ़ाई से छुटकारा पाना है. हम छात्रों की विश्लेषण क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रयोग और नवाचार का परीक्षण करते हैं, जो उद्योग चाहता है. इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई से पहले अलग-अलग भाषाओं में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बराबरी के मैदान बनाने होते हैं. सभी संस्थानों को अगले दो सालों में इन मामलों में मान्यता हासिल करनी होगी. आत्मविश्वास पाने के लिए हैकेथॉन में भाग लेने में हम छात्रों की मदद कर रहे हैं.

**● इंजीनियरिंग शिक्षा को प्रासंगिक बनाने और उद्योगों से बेहतर जोड़ने के लिए कौन-से नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं?**

हमने कहा है कि हर संस्थान कम से कम पांच उद्योगों के साथ करार करे. कुछ कॉलेजों ने 20-25 उद्योगों के साथ ऐसा किया है जबकि कई कॉलेज दूरदराज होने के कारण बिल्कुल नहीं कर पाए हैं. यह लंबा सफर है, पर एआइसीटीई ने इंटर्नशिप कार्यक्रमों को सहारा देने के लिए नैसकॉम, फिक्की और सीआइआइ सरीखे औद्योगिक निकायों से बात की है.

**● आप एआइसीटीई के कार्यकाल की तुलना अपने पिछले कामों से कैसे करते हैं?**

असल में तुलना नहीं की जा सकती. एआइसीटीई में मैं भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म कर पाया और इस संस्था को महज नियामक होने के बजाए फैसिलिटेटर बना सका हूं.

कर पाएंगे जिनकी बहुत मांग है. तमिलनाडु के स्व-वित्तपोषित प्रोफेशनल, आर्ट्स और साइंस कॉलेजों के कंसोर्शियम के सचिव पी. सेल्वराज कहते हैं, ''डिजिटल दुनिया ने डेटा साइंस, एआइ और मशीन लर्निंग में कुशल व्यक्तियों की बड़ी मांग पैदा कर दी है. लेकिन हम उनकी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हैं क्योंकि एआइसीटीई ने उन कॉलेजों में नए कोर्स शुरू करने की अनुमति नहीं देने फैसला किया है जो पिछले वर्ष में अपनी 50 प्रतिशत सीटें नहीं भर सके.'' राज्य में 554 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं.

इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता को भी नुक्सान हुआ क्योंकि बेधड़क खुल रहे कॉलेजों ने प्रशिक्षित और अच्छे वेतन वाले शिक्षकों की भर्ती नहीं की. महामारी के कारण कई निजी कॉलेजों को शिक्षकों की छंटनी करनी पड़ी और उनके विषयों को संकाय के बचे सदस्यों को दे दिया गया, भले ही उनके पास अपेक्षित योग्यता हो, न हो. 1 अक्तूबर से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक वर्ष से पहले कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन शिक्षकों को फिर से नियुक्त करने के इच्छुक हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा ने व्यावहारिक कक्षाओं की आवश्यकता को काफी हद तक दूर कर दिया है.

एआइसीटीई ने इंजीनियरिंग कॉलेजों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने शिक्षकों को बर्खास्त करना नहीं रोका और फैकल्टी की संख्या नहीं बढ़ाई तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उसने कॉलेजों से कहा है कि वे महामारी के दौरान पूरे साल की फीस के एकमुश्त भुगतान पर जोर न दें और सामान्य स्थिति आने तक तीन या चार समान किस्तों में फीस जमा करने की सुविधा दें. यह भी सिफारिश की है कि संस्थान आस-पास के जिन कॉलेजों में इंटरनेट बैंडविड्थ की व्यवस्था नहीं है, उनके छात्रों को अपनी सुविधाओं के इस्तेमाल की अनुमति दें. कोविड लॉकडाउन के चलते कॉलेज में हाजिरी के मौजूदा नियमों में भी ढील दी जा सकती है.

## लेटरल एंट्री पर विवाद

कठिन हालात में कठोर उपायों की जरूरत होती है. एआइसीटीई ने हाल ही में जारी एक सर्कुलर में कॉलेजों से कहा था कि वे बीई/बीटेक डिग्री वाले विद्यार्थियों को किसी अन्य इंजीनियरिंग विषय में बीई/बीटेक डिग्री में लेटरल एंट्री की अनुमति दें. परिषद का कहना है कि ''मूल विषय में क्रेडिट आवश्यकताओं से समझौता किए बिना और नए प्रोग्राम में दक्षता प्राप्ति के लिए'' विद्यार्थी दो या तीन वर्षों में अतिरिक्त डिग्री पूरी कर सकते हैं. विश्वविद्यालयों को सलाह दी गई है कि वे अपने नियम-कानूनों में आवश्यक बदलाव करके इसकी व्यवस्था करें.

हालांकि कॉलेजों के प्रबंधन ऊहापोह में हैं. उन्हें लगता है कि लेटरल एंट्री बस भ्रमित करने का तरीका है और इससे विद्यार्थियों को कोई फायदा नहीं होगा. कुछ लोगों को लगता है कि कहीं ये निर्णय कॉलेजों में खाली सीटों को भरने के उद्देश्य से तो नहीं बनाए गए हैं. तंजावुर के सस्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति एस. वैद्यसुब्रह्मण्यम कहते हैं, ''स्नातक स्तर पर दो इंजीनियरिंग डिग्री की अनुमति, जो कृत्रिम रूप से प्रचारित मांग को जन्म दे सकती है, देने के बजाए मौजूदा स्नातक डिग्री को अधिक अंतर्विषयक बनाया जाना चाहिए और सिस्टम एनालिसिस ऐंड डिजाइन जैसे बहुग्राही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.''

सहस्त्रबुद्धे कहते हैं कि विद्यार्थी एक अतिरिक्त विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने की मांग कर रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालयों में इसके लिए आवश्यक प्रावधान नहीं थे. यह इंगित करते हुए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में रुचि रखते थे और धातु विज्ञान (मेटलर्जी) में स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए उत्सुक थे, वे कहते हैं, ''ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती है, पर जो ऐसा चाहते हैं उन्हें अवसर क्यों न दिया जाए?''

वैद्यसुब्रह्मण्यम सुझाते हैं कि सिस्टम डिजाइन ऐंड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस इंटेलिजेंस में स्नातक तटस्थ सामान्य पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री शुरू की जा सकती है. उनका मानना है कि इससे कारोबारों में बदलावों से बेअसर बेहतर करियर विकल्प मिल सकेंगे. साथ ही छोटी दो साल की डिग्री (एमटेक कोर्स) दूसरी बीटेक डिग्री के मुकाबले ज्यादा काम आएगी.

**कॉलेज प्रबंधन मानते हैं कि एआइसीटीई के नए लेटरल एंट्री मानक भ्रमित करने के लिए हैं और इससे विद्यार्थियों को कोई फायदा नहीं**

प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही है इसलिए कंपनियां बहु-विषयक कौशल वाले इंजीनियरों को लेना चाहती हैं. तमिलनाडु के सलेम स्थित विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी के उद्योग और अकादमिक संबंध विभाग के निदेशक के. मणिवन्नन कहते हैं, ''रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का एक संयोजन है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है. डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग ज्ञान शामिल है जबकि 3डी प्रिंटिंग का मेडिसिन में तेजी से उपयोग किया जा रहा है.'' एक उदाहरण का हवाला देते हुए, वे कहते हैं: ''आइसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) के पास कोविड से जुड़े 48 करोड़ डेटा हैं. उसे ऐसे पेशेवरों की जरूरत होगी जो डेटा को एकीकृत कर सकें और उसके विश्लेषण के बाद पूर्वानुमान दे सकें. इन कार्यों के लिए एआइ और डेटा इंटेलिजेंस के उपयोग की आवश्यकता होती है.''

## दोहरी भूमिका

सहस्त्रबुद्धे मानते हैं कि यदि इंजीनियरिंग शिक्षा को उद्योग के हिसाब से प्रासंगिक और रोजगारपरक रहना है तो उसे बदलना होगा. वे कहते हैं, ''पिछले छह वर्षों में एआइसीटीई का प्रयास रहा है कि वह नियामक के साथ एक सहयोगी की भूमिका भी निभाए.'' जिन क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, पाठ्यक्रमों की अवधि में संशोधन उनमें से एक है. सहस्त्रबुद्धे कहते हैं, ''मजबूत शैक्षणिक प्रणाली बनाने के लिए एआइसीटीई राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और उद्योग दोनों से इनपुट लेकर हर तीन से चार साल में एक मॉडल पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है. साथ ही, विश्वविद्यालयों को अलग-अलग इलाके से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चयन की स्वायत्तता भी है. कई पाठ्यक्रमों में हर साल संशोधन की जरूरत होती है.''

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, एआइसीटीई क्षेत्रीय भाषाओं

# आखिर कहां हैं पढ़ाने वाले?

सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआइसीटीई के अनुमान के आधार पर 'नियमित' संकाय सदस्यों* की कमी ( % में)

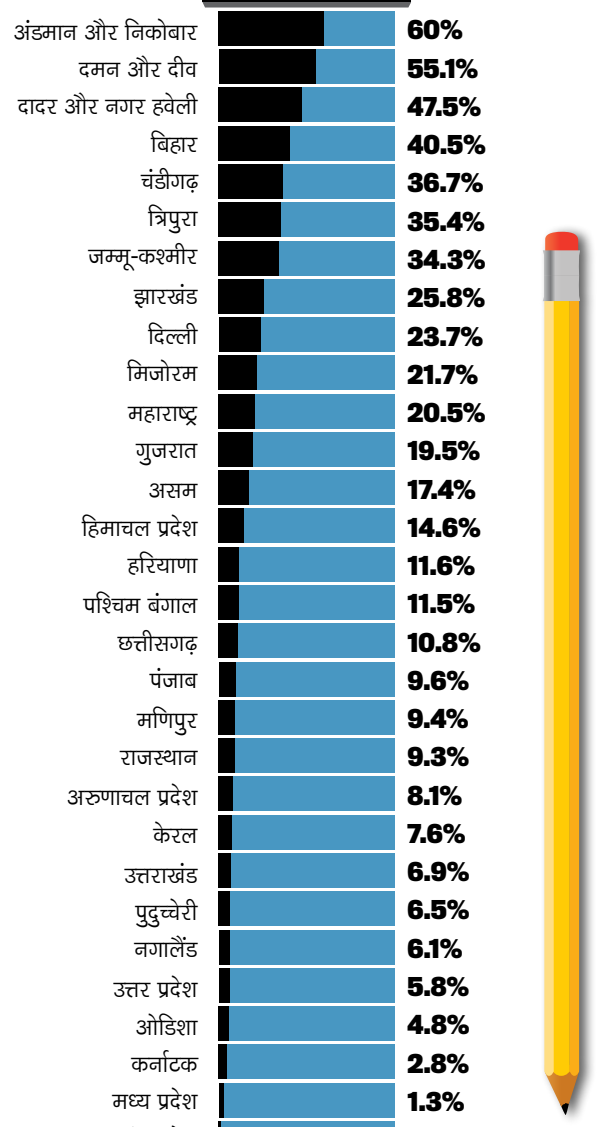


(*'अस्थाई' और/या 'संविदा' शिक्षक इसमें शामिल नहीं)

*2021 के आंकड़े; स्रोतः एआइसीटीई*

में इंजीनियरिंग कोर्स सुविधाजनक बनाने के कार्य को प्राथमिकता दे रहा है. इसने 12 भाषाओं में कोर्स सामग्री का अनुवाद करने के लिए एआइ टूल बनाया है. सहस्त्रबुद्धे कहते हैं, ''यह कदम उन लोगों को सशक्त बनाएगा जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में पूरी की है. दुनिया भर में ऐसा पाया गया है कि जो लोग मातृभाषा में सीखते हैं, उनकी सोचने की प्रक्रिया बेहतर होती है और वे चीजों को तेजी से ग्रहण करते हैं.'' 2021-22 के सत्र से 13 कॉलेज पांच भाषाओं—बांग्ला, तमिल, तेलुगू, मराठी और हिंदी में मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और आइटी इंजीनियरिंग कोर्स की पेशकश करेंगे. हालांकि, तकनीकी शब्दों का अनुवाद नहीं किया जाएगा. अभ्यास के लिए शिक्षकों, अनुवादकों और पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता होगी. पिछले साल, इंजीनियरिंग छात्रों के बीच एआइसीटीई के एक सर्वेक्षण में 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मातृभाषा को सीखने के माध्यम के रूप में पसंद किया, जिसमें तमिल भाषा शीर्ष पर थी.

एआइसीटीई इंटर्नशिप के माध्यम से विद्यार्थियों का उद्योग के साथ अनुभव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसने मातहत सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसे अनिवार्य कर दिया है. काउंसिल की ओर से स्थापित एआइ-आधारित एक इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों को इंटर्नशिप देने वाली कंपनियों से जोड़ता है. बी.वी.आर. मोहन रेड्डी, जो प्रौद्योगिकी फर्म साइएंट के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, कहते हैं, ''इस तरह का हस्तक्षेप और इंटर्नशिप धीरे-धीरे छात्रों और कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं. इस आधार पर अनुमान लगाना बड़ी बात नहीं कि इससे सालाना 2,00,000-3,00,000 नई नौकरियां पैदा होंगी. अभी बमुश्किल 3,00,000 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को ही हर साल अच्छी नौकरी मिल पाती है. इंटर्नशिप में इस आंकड़े को करीब दोगुना करने की क्षमता है. यह संख्या और बढ़ने वाली है.'' इंटर्नशिप से कौशल में अंतर को पाटने में मदद मिलने की भी उम्मीद है. एस्पायरिंग माइंड्स के 2019 के रोजगार सर्वे में पाया गया कि 95 प्रतिशत भारतीय इंजीनियर सही ढंग से कोड नहीं कर सके. यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि इनमें से बड़ा हिस्सा आइटी क्षेत्र में काम करता है.

छोटी और मध्यम अवधि में इंजीनियरिंग शिक्षा को बेहतर बनाने को एआइसीटीई के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती टुकड़ों में और आहिस्ता-आहिस्ता किए गए उपायों से परे जाने की है. कंपनियां अब ऐसे इंजीनियरिंग शोधकर्ताओं और स्नातकों को चाहती हैं जो जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं को समझने और उसका समाधान प्रदान करने की क्षमता रखते हों. इसलिए भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा को वैश्विक प्रवृत्ति के साथ कदमताल करने वाली बनाना जरूरी है. एआइसीटीई के पूर्व अध्यक्ष एस.एस. मंथा कहते हैं, ''इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सही मायने में गुणवत्ता को पक्का करने वाले एक स्वायत्त निकाय की जरूरत है जिसे उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित लोग संचालित करें और जो सरकार से दूरी भी बनाए रख सके.'' ■

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

यूपी की धान खरीद व्यवस्था में कई छेद
लालफीताशाही के शिकंजे में कारोबार
सरना: पुराने धर्म पर नई बहस
इंडिया टुडे
कोविड-19 वैक्सीन
कितनी सुरक्षित? कितनी कारगर?
बाजार में आने के लिए तैयार नई वैक्सीन से जुड़े सारे अहम सवालों के जवाब

राम मंदिर को माना गया मोदी की प्रमुख उपलब्धि
अनुच्छेद 370 हटाने को मिला जोरदार समर्थन
बेरोजगारी मानी गई सबसे बड़ी समस्या
इंडिया टुडे
देश का मिजाज सर्वेक्षण
मोदी और हिंदुत्व का बोलबाला
देशव्यापी छमाही सर्वेक्षण से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर बरकरार हैं और संघ परिवार के एजेंडे को मिली जबरदस्त बढ़त

# सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

## सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

### हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)**

| टिक करें | अवधि | कुल अंक | कवर प्राइस (₹) | ऑफर प्राइस (₹) | डिस्काउंट |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2 वर्ष | 104 | ~~5200~~ | 4099 | 21% |
| ☐ | 1 वर्ष | 52 | ~~2600~~ | 2199 | 15% |

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक..... को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ..... (बैंक का नाम).....रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम..... पता.....

..... शहर..... राज्य..... पिन.....

मोबाइल..... ईमेल.....

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

**खौफनाक**
काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त के आत्मघाती हमले के बाद वहां पहरा देता तालिबान लड़ाका

गेट्टी इमेजेज

# आइएसआइएल-के का नया खतरा

**भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उन भारतीय नागरिकों की वापसी को लेकर चिंतित हो गई हैं जो आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान चले गए थे**

**जीमॉन जैकब**

अफगानिस्तान स्थित आतंकी संगठन **इस्लामिक स्टेट**–ऑफ इराक ऐंड लेवांत–खुरासान प्रोविंस (आइएसआइएल-के) के पांच सदस्यों ने, जो 2016 में केरल से गए थे, अपने परिवारों से संपर्क करके कहा है कि वे घर वापस आना चाहते हैं. 30 अगस्त को आए आखिरी संदेश में उन्होंने कहा कि हालात खराब हैं, खाने की आपूर्ति सीमित है और आइएसआइएल-के का केरल धड़ा बिखरा हुआ है.

यह गैरमामूली घटना है क्योंकि मई और अगस्त 2016 के बीच केरल से अफगानिस्तान गए 36 में से ज्यादातर लोगों को मृत मान लिया गया था (अनुमान है कि ये पांचों उसी सेल का हिस्सा हैं). केंद्रीय खुफिया सूत्रों का कहना है कि जिन्हें अब भी जिंदा माना जाता है, उनमें मूलत: कारसगोड जिले का रहने वाला मोहम्मद साजिद, जो 2016 में गायब होने से पहले इस्लामिक बैंक, शारजाह में काम करता था; कारसगोड का ही रहने वाला 34 वर्षीय शिहास अब्दुल रहमान, जो कोझिकोड के पीस फाउंडेशन में काम करता था; और कोझिकोड का 31 वर्षीय रियास अहमद, जो 2015 में आइएसआइएल-के से जुड़ने से पहले सऊदी अरब में कार्यरत था.

तालिबान का एक कट्टर धड़ा 2014 में अलग होकर आइएसआइएल-के बना. सीरिया और इराक स्थित आतंकी संगठन के प्रति वफादारी की कसमें खाते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में एक के बाद एक आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया. संगठन ने 2020 में काबुल के गुरुद्वारे पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 25 लोग मारे गए थे (आत्मघाती हमलावरों में एक केरल का मोहम्मद मोहसिन था). उसने 27 अगस्त को काबुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए ताजा हमले की जिम्मेदारी भी ली, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों के अलावा रिपोर्टों के मुताबिक 169 अफगान नागरिक और 28 तालिबान लड़ाके भी मारे गए थे. रहस्यमयी अबू बकर अल बगदादी की अगुआई में आइएसआइएल ने अपने अच्छे दिनों में अफ्रीका और एशिया में 'फ्रेंचाइज' बनाई थीं, जिनमें आइएसआइएल-के सबसे प्रमुख था.

सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आइएसआइएल-के के केरल वाले लड़ाके वापस आकर भारत में आतंकी हमले कर सकते हैं. इसी वजह से पिछले महीने के अंत में एयरपोर्ट, सीपोर्ट और जमीनी क्रॉसिंग पर अलर्ट जारी किया गया ताकि अफगानिस्तान से लौटने की फिराक में जुटे

INDIA TODAY

# BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

# केरल से आइएसआइएल का कनेक्शन

राज्य के इस्लामी कट्टरपंथियों में आइएसआइएल के प्रति आसक्ति साल 2015 में शुरू हुई

**आइएसआइएल-के के हमले**

काबुल
गुरुद्वारा
25 मार्च, 2020
**25 लोगों की मौत**

हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट
26 अगस्त, 2021
**182 लोगों की मौत**

## आइएसआइएल-के केरल निवासी गुर्गे जिनके अभी जीवित होने का संदेह है

**रियास अहमद**
कोझीकोड निवासी यह शख्स 2015 में आइएसआइएल में शामिल होने से पहले सऊदी अरब में काम करता था

**मोहम्मद साजिद**
कारसगोड का यह लड़का 2016 में गायब होने से पहले शारजाह के इस्लामिक बैंक में काम करता था

**मोहम्मद मनशाद**
काबुल की फ्लाइट में सवार होने से पहले कासरगोड से बी.कॉम कर चुका यह युवक बंगलूरू में काम करता था

**सिहास अब्दुल रहीमन**
कासरगोड से बीबीए कर चुका यह युवक कोझीकोड के पीस फाउंडेशन के साथ काम करता था

आइएसआइएल-के के 25 आतंकियों पर नजर रखी जा सके. ये अलर्ट तालिबान के सत्ता संभालने के बाद जारी किया गया. काबुल में घुसने के दो दिन बाद 17 अगस्त को तालिबान ने अल कायदा और आइएसआइएल-के के लड़ाकों समेत हजारों कैदियों को राजधानी के पुल-ए-चरखी जेल से छोड़ दिया.

आतंक से जुड़े मामलों की जांच करने वाले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) आइएसआइएल-के में शामिल होने वाले भारतीय रंगरूटों के कई मामलों की जांच कर रही है. इसने 1 अप्रैल, 2020 को एक मामला दर्ज किया, जो मार्च 2020 में काबुल के गुरुद्वारे पर हुए हमले से जुड़ा था. हमले में आइएसआइएल-के के तीन आतंकवादी अफगान राजधानी के गुरुद्वारा हर राय साहिब में दनदनाते घुस गए थे. आइएसआइएल ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि हमला अबू खालिद अल-हिंदी (मूलत: कारसगोड के रहने वाले मोहसिन) की अगुआई में 'कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचारों का बदला लेने के लिए' किया गया. हमले के दौरान अफगान सुरक्षा बलों ने उसे मार डाला.

आइएसआइएल-के का कट्टरता के सांचे में ढालने वाला तंत्र जस का तस कायम है. इस साल मार्च में एनआइए ने कहा कि उसने केरल स्थित आइएसआइएस के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके देश भर से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. नई दिल्ली में 3 मार्च को दर्ज एफआइआर में तीन लोगों का नाम था, जो टेलीग्राम, हूप और इंस्टाग्राम पर आइएसआइएस के प्रोपेगैंडा चैनल चला रहे थे. एफआइआर कहती है कि गुट ने जेऐंडके में हिजरत (धार्मिक प्रवास) और आतंकी कार्रवाइयां करने की साजिश रची थी.

केरल पुलिस की खुफिया शाखा आइएसआइएल-के सदस्यों और राज्य में उनके परिवारों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान पर नजर रखे है. एक बड़े खुफिया अफसर कहते हैं कि उनमें से कइयों की मौत की तस्दीक हो चुकी है. अजीब बात यह है कि मृतकों के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट अब भी सक्रिय हैं. पिछले साल नांगरहार और कुनार प्रांतों में आइएसआइएल-के के नेस्तोनाबूद हो जाने के बाद केरल के रंगरूटों की कम से कम चार विधवाओं—निमिषा फातिमा, रफाला, सोनिया सेबास्टियन और मेरिन जैकब—को गिरफ्तार करके काबुल की जेल में डाल दिया गया था. अब जब तालिबान ने ज्यादातर कैदियों को आजाद कर दिया है, अधिकारियों का कहना है कि इन विधवाओं और उनके बच्चों की मौजूदा स्थिति के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है.

केरल के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पहले रुपए-पैसे और वैचारिक सहायता के लिए पाकिस्तान या सऊदी अरब के साथ जाने का विकल्प चुना था. सबसे शुरुआती उदाहरण आपातकाल के बाद 1977 में स्थापित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का था, जिसके कुछ तबकों ने बाद में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) सरीखे धड़ों में चोला बदल लिया. कट्टरता के सांचे में ढाल दिए गए नौजवानों पर आइएसआइएस ने 2015 में अपनी नजरें गड़ाईं. उससे एक साल पहले वे खिलाफत कायम करने के लिए सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों का नियंत्रण अपने हाथ में ले चुके थे. 2016 की घटना के बाद केरल पुलिस की एक जांच में पता चला कि खाड़ी में काम कर चुके कई नौजवान आइएस के कब्जे वाले प्रांतों में चले गए हैं. ये केरल के उस जत्थे के अलावा थे, जिसके कुछ सदस्य बेंगलूरू से हवाई रास्ते से पहले ईरान गए और फिर वहां से सरहद पार करके अफगानिस्तान में दाखिल हुए थे और अन्य सदस्य सीधी उड़ान पकड़कर काबुल पहुंचे थे.

कारसगोड से अचानक गायब हो जाने वाले 23 वर्षीय मोहम्मद मारवान ने 17 जुलाई, 2016 को परिवार को संदेश भेजकर बताया था कि वह आतंकवादी बन गया है. मारवान ने अपने संदेश में कहा, ''लोग भले मुझे आतंकवादी कहते हों. अगर अल्लाह के रास्ते के लिए लड़ना आतंकवाद है, तो हां, मैं आतंकवादी हूं.'' मारवान छह माह बाद अमेरिकी फौजों की कार्रवाई में मारा गया.

उधर, केंद्रीय एजेंसियों की मदद से केरल पुलिस की एक संयुक्त जांच वायरटैप, पूछताछ और सोशल मीडिया पर डाले गए संदेशों के जरिए करीब 450 आइएस संदिग्धों से

**खतरा** (सबसे बाएं) < तालिबान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और जैश प्रमुख मसूद अजहर

# तालिबान का असर जेऐंडके पर पड़ेगा?

भारत की चिंता यह है कि पाकिस्तान के आतंकी धड़ों को हक्कानी नेटवर्क के ताकतवर सरपरस्त मिल जाएंगे

**मोअज्जम मोहम्मद**

अफगानिस्तान पर कब्जे के तीन हफ्ते बाद 7 सितंबर को तालिबान ने नई सरकार के नामों का ऐलान किया. 33 सदस्यीय मंत्रिमंडल में पाकिस्तान स्थित हक्कानी नेटवर्क की प्रमुखता से मौजूदगी भारत के लिए चिंता की बात है. मूलतः उत्तरी वजीरिस्तान के हक्कानियों का अल कायदा और पाकिस्तान के डीप स्टेट से गहरा रिश्ता है. इन्होंने जुलाई 2008 में अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती हमला किया था. इसका नेता सिराजुद्दीन हक्कानी अब तालिबान की सरकार में गृह मंत्री है.

अफगानिस्तान के भारत-विरोधी आतंकी गतिविधियों का अड्डा बनने की आशंका के साथ कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल 31 अगस्त को दोहा में तालिबान के राजनैतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्तानेकजई से मिले. तालिबान के नुमाइंदों ने भरोसा दिलाया कि भारत की चिंताओं का ख्याल रखा जाएगा. मगर आशंकाएं कायम हैं, खासकर इन खबरों के मद्देनजर कि जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) का सरगना मसूद अजहर काबुल के पतन के कुछ ही दिन बाद तालिबान के सह-संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मिला था.

यह आशंका है कि लड़ाके अफगानिस्तान से पाकिस्तान होकर कश्मीर में लड़ने चले आएं.

भारत ने एलओसी और सरहदों पर सुरक्षा बढ़ा दी है. उत्तर कश्मीर के तीन जिलों—बारामुला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा—में विदेशी उग्रवादियों के जमा होने की खबरें हैं. कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह कहते हैं कि ''चिंता की बात नहीं, सब ठीक है.'' छह आतंकी गुट तालिबान के उभार का कश्मीर में फायदा उठा सकते हैं:

**जेईएम:** दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के अपहृत विमान (आइसी-814) में सवार बंधकों के बदले छोड़े जाने के बाद मसूद अजहर ने स्थापित किया. कई आतंकी हमले किए. 2019 का पुलवामा हमला इसी की कारस्तानी बताया जाता है. मौजूदा स्थितिः सक्रिय

**लश्कर-ए-तैयबा:** हाफिज सईद ने अफगानिस्तान में स्थापना की. कहा जाता है कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले सहित भारत में कुछ भीषण हमलों को अंजाम दिया. मौजूदा स्थितिः सक्रिय

**अल कायदा:** भारत में मौजूदगी की पुष्टि नहीं. सरगना अल-जवाहिरी ने 31 अगस्त को तालिबान को बधाई दी और कश्मीर को 'इस्लाम के दुश्मनों' से आजाद कराने की अपील की. मौजूदा स्थितिः अफगान-पाक में सक्रिय

**हिज्बुल मुजाहिदीन:** कश्मीर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठनों में से एक, 1980 के दशक के आखिरी वर्षों से सक्रिय. मौजूदा स्थितिः सक्रिय

**अल बदर:** अफगानी लड़ाके गुलबुद्दीन हिकमतयार के संगठन हिज्ब-ए-इस्लामी से करीबी रिश्ते हैं. कश्मीर में विदेशी काडर भेजता है. मौजूदा स्थितिः सक्रिय

**इस्लामिक स्टेट:** 'भारत केंद्रित' कार्रवाइयों के लिए 2019 में विलायत अल-हिंद (भारत का -प्रशासनिक-विभाग) ने बनाया. ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के बावजूद छोटा-मोटा खिलाड़ी. मौजूदा स्थितिः सक्रिय

निकाली गई बेशकीमती खुफिया जानकारियों की छानबीन कर रही थी. काट-छांट के बाद संदिग्धों की सूची में आखिरकार 60 नाम बचे.

अधिकारी आंकते हैं कि केरल से आइएस के इलाकों की तरफ कूच करने वालों में सजीर अब्दुल्ला मंगलसेरी नौजवानों को कट्टर बनाने में मुख्य प्रेरक था. कोझिकोड के राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान (एनआइटी) से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट सजीर 2016 में जाने वाले सलफी गुट का एक तरह से 'केरल अमीर' था. वह 2017 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया. वह केरल के 36 सदस्यों के गुट की अगुआई करने वाले आइटी इंजीनियर रशीद अब्दुल्ला का मार्गदर्शक भी था. खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि मौत से पहले सजीर उत्तर केरल में आइएसआइएल-के के कई स्लीपर सेल चलाता था.

**मोहम्मद मोहसिन (चित्र में) 2020 के काबुल में हुए गुरुद्वारे पर हमले में शामिल आत्मघाती हमलावरों में से एक था**

ज्यूरिख स्थित सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के वरिष्ठ विश्लेषक प्रेम महादेवन अलबत्ता आइएसआइएल-के को ज्यादा सीधे खतरे के तौर पर देखते हैं. वे कहते हैं, ''मेरी चिंता यह है कि आइएसआइ इस मत को सामने रखने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है कि भारत में 'स्वदेशी आंतकवादी' हैं.''

इस बीच जांच तेज होने के साथ पता चला कि केरल से गए आइएसआइएस के रंगरूटों की तादाद शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा थी. 154 रंगरूट शामिल हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर खाड़ी के देशों में नौकरी करते थे. इनमें से करीब 100 ने सीरिया और इराक जाने और लड़ने का विकल्प चुना था, जबकि दूसरे अफगानिस्तान गए. केरल पुलिस की खुफिया शाखा के एक बड़े अफसर कहते हैं, ''बाद में हमें पता चला कि आइएस स्लीपर सेल तमाम उत्तरी जिलों में सक्रिय थे.''

यह अफसर याद करते हैं, ''स्लीपर सेल को लेकर पहली कामयाबी 30 जुलाई, 2016 को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यास्मीन मोहम्मद जाहिद (बिहार की रहने वाली) की गिरफ्तारी के बाद मिली. एनआइए की अदालत ने मार्च 2018 में यास्मीन को सात साल कैद की सजा सुनाई. केरल और उसके बाहर भी स्लीपर सेलों की जांच जारी है. इस बीच, देश में हाइ अलर्ट है, खासकर जब उत्तर कश्मीर की सरहद पर विदेशी आतंकियों के जमा होने की खबरें आ रही हैं. यह इत्तेफाक है या अनहोनी की पूर्वसूचना? जवाब जो भी हो, वह आने वाले महीनों में मिलेगा. ■

खेल

TOKYO 2020
PARALYMPIC GAMES

# जीतने की जिद

**तोक्यो 2021 पैरालंपिक में भारत की ऐतिहासिक सफलता ने साबित किया कि संस्थागत समर्थन मिले तो जीत एक आदत में तब्दील हो सकती है**

बोरिया मजूमदार

एपी

तोक्यो में कृष्ण नागर ने पैरालंपिक में भारत के लिए पांचवां स्वर्ण पदक जीता और भारत के खाते में कुल 19 मेडल हो गए. खेल में भाग ले रहे 54 एथलीटों का 5 स्वर्ण सहित 19 पदक वाला प्रदर्शन अपने आप में रोमांचक था. पैरालंपिक में भारत के तोक्यो से पहले के सफर पर नजर डालें, तो पदक तालिका कहीं अधिक सुखद दिखने लगती है. भारत ने 1968 में पहली बार पैरालंपिक में भाग लिया था. तब से लेकर 2016 तक भारत को कुल 12 पदक ही मिले थे जिसमें से चार अकेले 2016 के थे. हालांकि तोक्यो की कामयाबी भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआइ) की अध्यक्ष दीपा मलिक के लिए अपने साथ एक सुखद दुविधा भी लेकर आई है लेकिन वे इस प्रदर्शन से बहुत खुश नजर आती हैं. मलिक कहती हैं, ''पीसीआइ बहुत समृद्ध संगठन नहीं है पर हम अपने एथलीटों को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमने अपने हर पदक विजेता के प्रति कृतज्ञता और स्नेह के प्रतीक के रूप में सोने के 15 कंगनों (ब्रेस्लेट) के ऑर्डर दिए थे. अब मेरे सामने संख्या बढ़ाने की एक सुखद समस्या है!'' भारत के खेल इतिहास में पहली बार इस स्तर पर नतीजा उम्मीद से ज्यादा रहा है. हालांकि, इसे अचानक मिली सफलता कहना ठीक न होगा. 2004 में पैरालंपिक में प्रदर्शन को मजबूती देने की व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसका रंग अब चढ़ना शुरू हुआ है.

भारत के सबसे सफल पैरालंपिक एथलीट देवेंद्र झांझरिया 2004 में जब एथेंस गेम्स के लिए जा रहे थे, तो हवाई अड्डे पर उनके साथ सिर्फ उनके पिता थे. न कोई नेता, न नौकरशाह, न मीडिया. पिता ने उनसे कहा, ''तुम जीत के आए तो बदलाव आएगा, वरना कुछ न होने वाला.'' आज उनके पिता नहीं रहे, पर वह ''बदलाव'' जरूर आ गया है. 2004 में देवेंद्र के स्वर्ण पदक जीतने के साथ भारत सरकार ने पहली बार पीसीआइ को मान्यता दी. ओलंपिक में देवेंद्र के तीसरे पदक समेत 2021 में 19 पदकों के साथ बदलाव सही मायने में और धूम-धड़ाके से आया है.

इसमें दो बातों की निर्णायक भूमिका रही है. पहला, भारतीय एथलीटों का नजरिया. तीन स्वर्ण पदक विजेता इसकी सबसे अच्छी मिसाल हैं. निशानेबाजी में दो पदक (एक स्वर्ण और एक कांस्य) जीतने वाली 19 वर्षीय अवनि लेखरा का कहना है कि वे अपने प्रदर्शन से खुश नहीं. मुस्कराते हुए वे कहती हैं, ''मैं एक परफेक्शनिस्ट हूं. मैंने जिस मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता उसमें आखिरी शॉट में मैं और बेहतर कर सकती थी. और अगर स्वर्ण पदक से खुश नहीं हूं तो कांस्य से कैसे खुश हो सकती हूं?'' हालांकि इस प्रदर्शन के बाद मिल रहे मान-सम्मान और चर्चाओं से वे काफी उत्साहित हैं, लेकिन उन्होंने एकाग्रता नहीं खोई है. अवनि कहती हैं, ''अभी बहुत कुछ करना बाकी है. अगर मेरे स्वर्ण और कांस्य पदक से लोग प्रोत्साहित होते हैं और हम 2024 में पेरिस के आयोजन में पदकों की संख्या दोगुनी कर पाते हैं, तो यह वास्तव में कहीं ज्यादा रोमांचित करने वाली बात होगी.''

तोक्यो पैरालंपिक में 45 मिनट में तीन बार भाला फेंककर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले सुमित आंतिल भी अपने से संतुष्ट नहीं. वे कहते हैं, ''वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हुआ पर सच कहूं तो मुझे 80 मीटर से ज्यादा भाला फेंकना है. नीरज (चोपड़ा) ने 87 मीटर फेंका. मुझे लगता है मैं भी 80-82 मीटर तक तो फेंक ही सकता हूं.'' और प्रमोद भगत के रूप में

एएफपी

गेट्टी इमेजेज

*(बाएं से क्रमशः)*

**देवेंद्र झांझरिया**
रजत पदक, पुरुषों की
भाला फेंक स्पर्धा (एफ 46)

**निषाद कुमार**
रजत पदक, पुरुष,
ऊंची कूद (टी 47)

**कृष्ण नागर**
स्वर्ण पदक, बैडमिंटन,
पुरुष एकल (एसएच 6)

भारत के पास एक ऐसा स्वर्ण पदक विजेता है जो सिर्फ जीतते रहना चाहता है. तोक्यो के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था, ''हम पिछले कुछ समय से विश्व चैंपियनशिप जीत रहे हैं. फिर भी ज्यादा पहचान नहीं थी. इसलिए हमने तय कर लिया था कि पैरालंपिक गोल्ड चाहिए. देश तभी हमें पहचानेगा.'' खिलाड़ियों की इस मानसिकता ने पुरस्कारों में बड़ा फर्क डाला है. भारत को पैरालंपिक में एक-दो पदक मिले होते तो न मीडिया चीजों को प्रचारित करता, न राष्ट्रव्यापी उत्सव होता और मुख्यधारा के पैरा खेलों के लिए भारत में सम्मान एक सपना ही बना रहता.

जीत की यही मानसिकता तोक्यो में भारत के पैरालंपिक अभियान को परिभाषित करती है. लंदन 2012 में भारतीय दल को इस बात का बहुत कम अंदाजा था कि क्या चल रहा है और बहुत कम लोग समझ पा रहे थे कि चैंपियन बनाने के लिए क्या कुछ आवश्यक है. एचएन गिरीशा ने उस वर्ष एक रजत पदक जीता था और वह विशुद्ध रूप से उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा का परिणाम था. रियो 2016 में चीजें थोड़ी बेहतर हुई थीं—19 एथलीटों के दल ने चार पदक जीते. लेकिन भारत के 10 या अधिक पदक जीत सकने की बात अभी भी सपना थी. पिछले पांच वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है. अब हमारे पास ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में और कई पैरा विश्व चैंपियनशिप में भी जीत हासिल की है. वे अपने खेल के शिखर पर हैं, उन्होंने शीर्ष पांच में जगह बनाई है. वे अब विश्व मंच से भयभीत नहीं हैं. वे अब वहां सिर्फ भाग लेने के लिए नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा करने और जीतने के लिए होते हैं.

दूसरा और पिछले पांच वर्षों में शायद सबसे अहम बदलाव सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का बढ़ता समर्थन है. लोकसभा में दिए एक बयान के मुताबिक, 2019 से 2021 के बीच सरकार ने पैरा स्पोर्ट्स सुविधाओं में 8.2 करोड़ रु. का निवेश किया. हालांकि अन्य ओलंपिक

TOKYO 2020
PARALYMPIC GAMES

**सुमित अंतिल**
स्वर्ण,
पुरुष जेवलिन थ्रो
(एफ46)

**कृष्णा नागर**
स्वर्ण, बैडमिंटन
पुरुष एकल
(एसएचजी)

**मनीष नरवाल**
स्वर्ण, मिक्स्ड 50 मी.
पिस्टल (एसएच1)

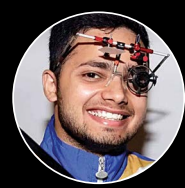

**प्रमोद भगत**
स्वर्ण,
बैडमिंटन, पुरुष एकल
(एसएल3)

**अवनि लेखड़ा**
स्वर्ण, महिला 10मी.
एयर राइफल
स्टैंडिंग (एसएच1)

> **तोक्यो में मिले पदक एक ऐसे उम्दा अवसर की तरह हैं जिसके तहत जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सके तथा और लोगों को खेलने के लिए प्रेरित किया जा सके''**
>
> —दीपा मलिक
> रजत विजेता, 2016 पैरालंपिक और अध्यक्ष, पीसीआइ

खेलों में सरकार के निवेश की तुलना में यह बहुत मामूली है, फिर भी यह एक बड़ी वृद्धि है. पदक विजेता एथलीटों को सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम (टॉप) योजना का लाभ मिला है. सरकार ने आंतिल के कृत्रिम पैर पर केवल 7 लाख रुपये ही खर्च नहीं किए, बल्कि उन्हें नीरज चोपड़ा जैसे सक्षम एथलीटों के साथ प्रशिक्षण लेने और उसी टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने का हर मौका दिया गया. आंतिल ने फिनलैंड और ट्यूनीशिया में हफ्तों प्रशिक्षण लिया और उन्हें 2024 के पेरिस खेलों के लिए पहले से ही अच्छी तरह तैयार होने का भरोसा है. आंतिल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि नीरज के साथ स्पर्धा करने से उनकी तैयारी में बड़ा फर्क पड़ा. इसी तरह, तोक्यो में भारत की पहली पदक विजेता भावना पटेल के लिए टॉप योजना एक गेम चेंजर साबित हुई. टेबल टेनिस खेलने वाली व्हीलचेयर पैरालंपियन भावना हमेशा से फंडिंग के लिए संघर्ष करती रही हैं. कटलरी की छोटी दुकान चलाने वाले पिता की बेटी भावना को अगर सरकार की मदद न मिली होती तो अभ्यास भागीदार के रूप में जरूरी रोबोट उन्हें कभी न मिल पाता. वे बताती हैं, ''मेरा सब कुछ बदल गया. मुझे यह भी लगा कि हम भी कुछ अहमियत रखते हैं.''

अवनि को सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों से समर्थन मिला है. सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण ने उनके प्रशिक्षण के लिए धन दिया, वहीं गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने सुमा शिरूर के रूप में उनके निजी कोच का खर्च उठाया. अवनि स्वीकारती हैं, ''सरकारी मदद न मिली होती, तो उपकरण खरीदना और पैरालंपिक के लिए जरूरी प्रशिक्षण ले पाना मुश्किल होता.''

चाहे वह दो पदक जीतने वाले सिंहराज हों या 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाले मनीष, टॉप योजना से खेलों में जाने वाले लगभग हर एथलीट को फायदा हुआ. राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना कहते हैं, ''पैरा बैडमिंटन के लिए एक समर्पित अकादमी होने से बहुत फर्क पड़ता है.'' सभी पदक विजेता—प्रमोद भगत, कृष्ण नागर, मनोज सरकार और सुहास यतिराज—लखनऊ में उनकी अकादमी में प्रशिक्षण लेते हैं. सबसे चर्चित भारतीय कोचों में से एक खन्ना कहते हैं, ''इसमें वह सब कुछ है जो एक विश्वस्तरीय एथलीट तैयार करने को जरूरी है. लॉकडाउन के दौरान, हम प्रशिक्षण जारी रख सकते थे क्योंकि हमारे पास एक अपना सेंटर था.''

हालांकि, तोक्यो की पदक तालिका अभी शुरुआत भर है. हमें अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप सफलता हासिल करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. मलिक कहती हैं, ''यह हमारे लिए अब तक का सबसे अच्छा अवसर रहा. हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जमीनी स्तर की प्रतिभाओं का दोहन करने के लिए सिस्टम विकसित करें और अधिक से अधिक लोगों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें.'' भारत ने तोक्यो में 22 खेलों में से सिर्फ नौ में भाग लिया. यह इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी क्षमता का काफी हद तक दोहन ही नहीं कर पाए हैं. उचित संरचनात्मक समर्थन के साथ हम पेरिस में 40 पदक जीत सकते हैं.

तोक्यो के लिए पीसीआइ का सबसे बढ़िया काम था खेलों के एक क्लस्टर में निवेश करना. यह जांचा-परखा ब्रिटिश मॉडल था. 1996 में अटलांटा में सिर्फ एक स्वर्ण जीतने वाले ब्रिटेन ने इस मॉडल की बदौलत लंदन में 29 और रियो में 30 स्वर्ण जीते थे. पीसीआइ ने भी उसी तरह की रणनीति अपनाई. हर एथलीट को समर्थन देने के बावजूद एथलेटिक्स और बैडमिंटन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था, जिसमें भारत ने कुल 12 पदक जीते. भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा भी इस

# शानदार प्रदर्शन

***टोक्यो 2021 पैरालंपिक में भारत की टोली ने पांच स्वर्ण सहित 19 पदक हासिल किया, यकीनन यह बेमिसाल उपलब्धि है क्योंकि 1968 से 2016 तक देश को सिर्फ 12 पदक ही हाथ लगे थे***

**भारत की पदक तालिका**

| | |
|---|---|
| स्वर्ण | 5 |
| रजत | 8 |
| कांस्य | 6 |
| कुल | 19 |

● **योगेश कठुनिया**
**रजत**, पुरुष डिस्कस थ्रो (एफ56)

● **निषाद कुमार**
**रजत**, पुरुष ऊंची कूद (टी47)

● **मरियप्पन थंगावेलु**
**रजत**, पुरुष ऊंची कूद (टी63)

● **प्रवीण कुमार**
**रजत**, पुरुष ऊंची कूद (टी64)

● **देवेंद्र झंझरिया**
**रजत**, पुरुष जेवलिन थ्रो (एफ46)

● **सुहास यतिराज**
**रजत**, बैडमिंटन, पुरुष एकल (एसएल4)

● **सिंहराज**
**रजत**, मिक्स्ड 50मी. पिस्टल (एसएच1)

● **भवीना पटेल**
**रजत**, टेबल टेनिस महिला एकल (क्लास 4)

● **शरद कुमार**
**कांस्य**, पुरुष ऊंची कूद (टी63)

● **हरविंदर सिंह**
**कांस्य**, तीरअंदाजी, (पुरुष एकल रिकर्व)

● **सुंदर सिंह गुर्जर**
**कांस्य**, पुरुष जेवलिन थ्रो (एफ46)

● **मनोज सरकार**
**कांस्य**, बैडमिंटन, पुरुष एकल (एसएल3)

● **सिंहराज**
**कांस्य**, पुरुष 10मी. एयर पिस्टल (एसएच1)

● **अवनि लेखड़ा**
**कांस्य**, महिला 50 मी. एयर राइफल 3 पोजिशन्स (एसएच1)

सिस्टम के कायल हो गए हैं. वे कहते हैं, ''पीसीआइ अपनी रणनीति में सफल रही. हमें हमेशा लगता था कि हमारी पदक तालिका दो अंकों में रहेगी लेकिन कई कारणों से हम ओलंपिक में ऐसा नहीं कर सके. दीपा मुझसे हमेशा कहती थीं कि हम कम से कम 15 पदक तो जरूर जीत सकते हैं और देखिए हम 19 पदक जीते हैं. अगर मुझे नवंबर में आइओए की सेवा करने का दूसरा मौका मिलता है तो मैं पेरिस के लिए इसी फॉर्मूले को अपनाऊंगा.''

दुनिया पेरिस में अधिक समावेशी ओलंपिक और पैरालंपिक मॉडल की ओर बढ़ रही है. चर्चा यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौता करने जा रहा है जिसके तहत खेलों का नाम बदलकर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स कर दिया जाएगा.

पैरालंपिक की समाप्ति पर कोलकाता की दीवारों पर भारतीय टीम की प्रशंसा में भित्तिचित्र दिखाई देने लगे. भारत के सभी पदक विजेताओं की तस्वीरें बनाई गईं जिनमें से प्रत्येक के नीचे 'गो इंडिया गो' लिखा था. सिर्फ पांच साल पहले, इसकी संभावना न के बराबर थी. अगर 19 पदक दिव्यांगों के लिए सम्मान और सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए रैंप और शौचालय जैसे बुनियादी ढांचे और भविष्य के एथलीटों को अपना खेल कौशल निखारने के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान कराने में सक्षम होते हैं, तो टोक्यो 2021 इतिहास के पन्नों में भारत में बड़े परिवर्तन लाने वाले खेलों के रूप में दर्ज होगा. ■

# उत्तर भारत के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज

उत्तर भारत के उच्च शिक्षा के संस्थानों पर विशेष फोकस को जारी रखते हुए पेश हैं नौ विषयों—आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लॉ, बीबीए और बीसीए—में इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट कॉलेज. ये रैंकिंग मार्केटिंग ऐंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स (एमडीआरए) के सहयोग से तैयार किए गए 2021 इंडिया टुडे बेस्ट कॉलेज रैंकिंग से लिए गए हैं.

## विषयवार नतीजे

### आर्ट्स

**कॉलेजों की रैंक और उनके स्कोर**

| उत्तर भारत में रैंक (प्राइवेट) 2021 | कॉलेज और शहर | इनटेक क्वालिटी और गवर्नेंस | अकादमिक गुणवत्ता | इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल | व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास | करियर की संभावना और प्लेसमेंट | ऑब्जेक्टिव स्कोर | धारणात्मक स्कोर | ओवरऑल स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 250 | 250 | 150 | 200 | 150 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 1 | सेंट स्टीफंस कॉलेज, नई दिल्ली | 206.8 | 177.2 | 129.9 | 180.3 | 131.8 | 826.0 | 996.5 | 1,822.5 |
| 2 | मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, चंडीगढ़ | 163.8 | 126.8 | 82.8 | 91.0 | 102.9 | 567.3 | 865.3 | 1,432.6 |
| 3 | डीएवी कॉलेज, सेक्टर-10, चंडीगढ़ | 168.9 | 126.5 | 79.9 | 87.7 | 83.6 | 546.6 | 830.0 | 1,376.6 |
| 4 | गोस्वामी गणेश दत्त एस.डी. कॉलेज, चंडीगढ़ | 139.8 | 120.2 | 87.6 | 101.7 | 118.7 | 568.0 | 788.7 | 1,356.7 |
| 5 | इसाबेला थोबर्न कॉलेज, लखनऊ | 166.4 | 130.7 | 78.0 | 113.2 | 98.2 | 586.5 | 714.2 | 1,300.7 |
| 6 | एस.एस. जैन सुबोध पीजी (स्वायत्त) कॉलेज, जयपुर | 169.5 | 147.8 | 82.5 | 91.6 | 106.0 | 597.4 | 641.2 | 1,238.6 |
| 7 | एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, जालंधर | 133.5 | 136.7 | 77.6 | 122.8 | 99.3 | 569.9 | 477.5 | 1,047.4 |
| 8 | सेंट विल्फ्रेड्स पीजी कॉलेज, जयपुर | 112.3 | 149.5 | 94.7 | 125.4 | 107.1 | 589.0 | 246.6 | 835.6 |
| 9 | कन्या महाविद्यालय, जालंधर | 144.2 | 136.5 | 100.8 | 98.9 | 56.4 | 536.8 | 274.5 | 811.3 |
| 10 | एमिटी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नोएडा | 90.1 | 144.8 | 91.2 | 102.2 | 89.2 | 517.5 | 290.9 | 808.4 |
| 11 | डीएवी कॉलेज, होशियारपुर | 130.4 | 147.2 | 99.2 | 97.5 | 76.4 | 550.7 | 233.8 | 784.5 |
| 12 | डीएवी कॉलेज, अबोहर, पंजाब | 136.6 | 125.7 | 82.0 | 72.8 | 63.1 | 480.2 | 303.5 | 783.7 |
| 13 | एमिटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, गुरुग्राम | 114.4 | 163.8 | 104.0 | 118.4 | 71.1 | 571.7 | 193.7 | 765.4 |
| 14 | गोपीचंद आर्य महिला कॉलेज, अबोहर, पंजाब | 126.5 | 80.1 | 62.2 | 57.2 | 65.1 | 391.1 | 345.1 | 736.2 |
| 15 | बीबीके डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, अमृतसर | 117.0 | 104.1 | 91.3 | 90.5 | 55.9 | 458.8 | 178.9 | 637.7 |
| 16 | अवध गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ | 136.2 | 124.3 | 62.5 | 85.1 | 79.2 | 487.3 | 150.2 | 637.5 |
| 17 | फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ऐंड सोशल साइंसेज, आइआइएस (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी) जयपुर | 130.7 | 152.8 | 105.4 | 115.5 | 76.1 | 580.5 | 51.8 | 632.3 |
| 18 | डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, फिरोजपुर कैंट, फिरोजपुर, पंजाब | 122.5 | 116.9 | 39.2 | 48.4 | 90.2 | 417.2 | 210.4 | 627.6 |
| 19 | रामा पीजी कॉलेज, लखनऊ | 109.4 | 35.6 | 60.2 | 57.3 | 44.4 | 306.9 | 232.5 | 539.4 |
| 20 | परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सिलेंस, जयपुर | 93.3 | 123.3 | 52.9 | 117.0 | 88.0 | 474.5 | 27.6 | 502.1 |

## साइंस

### कॉलेजों की रैंक और उनके स्कोर

| उत्तर भारत में रैंक (प्राइवेट) 2021 | कॉलेज और शहर | इनटेक क्वालिटी और गवर्नेंस | अकादमिक गुणवत्ता | इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल | व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास | करियर की संभावना और प्लेसमेंट | ऑब्जेक्टिव स्कोर | धारणात्मक स्कोर | ओवरऑल स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 250 | 250 | 150 | 200 | 150 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 1 | सेंट स्टीफंस कॉलेज, नई दिल्ली | 196.0 | 195.2 | 142.0 | 136.3 | 142.0 | 811.5 | 989.1 | 1,800.6 |
| 2 | गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, चंडीगढ़ | 167.6 | 171.0 | 123.9 | 105.5 | 95.1 | 663.1 | 839.5 | 1,502.6 |
| 3 | मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, चंडीगढ़ | 172.3 | 152.8 | 108.2 | 86.7 | 111.7 | 631.7 | 840.6 | 1,472.3 |
| 4 | डीएवी कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़ | 165.5 | 137.7 | 119.2 | 76.4 | 94.7 | 593.5 | 813.4 | 1,406.9 |
| 5 | इसाबेला थोबर्न कॉलेज, लखनऊ | 170.8 | 135.4 | 107.2 | 102.6 | 98.7 | 614.7 | 730.6 | 1,345.3 |
| 6 | एस.एस. जैन सुबोध पीजी कॉलेज (स्वायत्त), जयपुर | 182.7 | 153.6 | 83.5 | 65.1 | 104.0 | 588.9 | 746.5 | 1,335.4 |
| 7 | सेंट विल्फ्रेड्स पीजी कॉलेज, जयपुर | 116.3 | 164.8 | 125.0 | 88.3 | 108.7 | 603.1 | 716.1 | 1,319.2 |
| 8 | एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, नोएडा | 110.4 | 170.2 | 141.0 | 101.3 | 100.9 | 623.8 | 484.1 | 1,107.9 |
| 9 | पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज, जयपुर | 114.5 | 157.5 | 115.2 | 106.8 | 81.8 | 575.8 | 523.4 | 1,099.2 |
| 10 | एमिटी स्कूल ऑफ एप्लाइड साइंसेस, गुरुग्राम | 109.2 | 197.8 | 142.6 | 104.1 | 86.7 | 640.4 | 439.8 | 1,080.2 |
| 11 | कन्या महाविद्यालय (स्वायत्त), जालंधर | 170.6 | 162.3 | 114.2 | 105.5 | 74.3 | 626.9 | 312.3 | 939.2 |
| 12 | डीएवी कॉलेज, अबोहर, पंजाब | 152.0 | 163.3 | 113.3 | 79.5 | 81.0 | 589.1 | 330.4 | 919.5 |
| 13 | बीबीके डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, अमृतसर | 143.6 | 132.3 | 94.3 | 99.3 | 74.5 | 544.0 | 356.9 | 900.9 |
| 14 | स्कूल ऑफ लाइफ ऐंड बेसिक साइंसेज, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर | 129.2 | 154.5 | 119.3 | 126.5 | 81.7 | 611.2 | 213.3 | 824.5 |
| 15 | डीएवी सेंटेनरी कॉलेज, फरीदाबाद | 145.0 | 113.6 | 82.4 | 78.8 | 67.0 | 486.8 | 335.8 | 822.6 |
| 16 | डीएवी कॉलेज, होशियारपुर | 137.3 | 135.3 | 115.4 | 86.0 | 77.8 | 551.8 | 249.7 | 801.5 |
| 17 | फैकल्टी ऑफ साइंसेज, आइआइएस (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), जयपुर | 149.2 | 179.7 | 130.6 | 108.0 | 70.9 | 638.4 | 84.0 | 722.4 |
| 18 | सनातन धर्म कॉलेज, अंबाला कैंट, अंबाला | 113.7 | 66.3 | 31.2 | 63.7 | 62.2 | 337.1 | 382.2 | 719.3 |
| 19 | एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लखनऊ | 97.4 | 175.8 | 142.4 | 13.0 | 89.8 | 518.4 | 187.7 | 706.1 |
| 20 | जगदीश चंद्र डीएवी कॉलेज, दसूया, पंजाब | 118.8 | 112.7 | 90.1 | 55.2 | 70.2 | 447.0 | 204.8 | 651.8 |
| 21 | परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सिलेंस, जयपुर | 88.4 | 105.0 | 62.7 | 63.8 | 83.1 | 403.0 | 172.5 | 575.5 |
| 22 | उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देहरादून | 54.0 | 132.2 | 140.1 | 96.4 | 110.3 | 533.0 | 0.0 | 533.0 |

## कॉमर्स

### कॉलेजों की रैंक और उनके स्कोर

| उत्तर भारत में रैंक (प्राइवेट) 2021 | कॉलेज और शहर | इनटेक क्वालिटी और गवर्नेंस | अकादमिक गुणवत्ता | इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल | व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास | करियर की संभावना और प्लेसमेंट | ऑब्जेक्टिव स्कोर | धारणात्मक स्कोर | ओवरऑल स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 250 | 250 | 150 | 200 | 150 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 1 | गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, चंडीगढ़ | 159.2 | 163.5 | 99.7 | 109.3 | 145.9 | 677.6 | 848.8 | 1,526.4 |
| 2 | इसाबेला थोबर्न कॉलेज, लखनऊ | 127.7 | 129.6 | 101.3 | 130.9 | 123.3 | 612.8 | 723.5 | 1,336.3 |
| 3 | मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, चंडीगढ़ | 145.5 | 117.6 | 80.1 | 111.4 | 119.0 | 573.6 | 698.9 | 1,272.5 |
| 4 | डीएवी कॉलेज, चंडीगढ़ | 157.3 | 126.7 | 97.1 | 68.3 | 122.7 | 572.1 | 654.7 | 1,226.8 |
| 5 | एमिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऐंड फाइनेंस, नोएडा | 103.1 | 160.1 | 99.9 | 93.3 | 125.3 | 581.7 | 640.4 | 1,222.1 |
| 6 | एस.एस. जैन सुबोध पीजी (स्वायत्त) कॉलेज, जयपुर | 163.1 | 151.0 | 94.2 | 84.8 | 134.4 | 627.5 | 593.2 | 1,220.7 |
| 7 | जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, कालकाजी, नई दिल्ली | 76.9 | 159.0 | 71.8 | 159.1 | 105.5 | 572.3 | 390.9 | 963.2 |
| 8 | बीबीके डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, अमृतसर | 125.8 | 90.0 | 76.1 | 98.5 | 95.2 | 485.6 | 471.9 | 957.5 |
| 9 | कन्या महाविद्यालय (स्वायत्त), जालंधर | 141.3 | 127.1 | 93.9 | 111.5 | 105.1 | 578.9 | 363.4 | 942.3 |
| 10 | हंस राज महिला महाविद्यालय, जालंधर | 130.2 | 133.4 | 84.5 | 101.6 | 151.6 | 601.3 | 330.4 | 931.7 |
| 11 | डीएवी कॉलेज, अबोहर, पंजाब | 145.1 | 144.6 | 103.4 | 101.4 | 101.0 | 595.5 | 334.6 | 930.1 |
| 12 | विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नई दिल्ली | 130.3 | 121.3 | 71.6 | 110.1 | 132.5 | 565.8 | 287.6 | 853.4 |

# उत्तर भारत के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज

## कॉमर्स

कॉलेजों की रैंक और उनके स्कोर

| उत्तर भारत में रैंक (प्राइवेट) 2021 | कॉलेज और शहर | इनटेक क्वालिटी और गवर्नेंस | अकादमिक गुणवत्ता | इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल | व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास | करियर की संभावना और प्लेसमेंट | ऑब्जेक्टिव स्कोर | धारणात्मक स्कोर | ओवरऑल स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 225 | 250 | 150 | 175 | 200 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| 13 | डीएवी कॉलेज, होशियारपुर | 138.7 | 153.2 | 95.0 | 101.8 | 119.1 | 607.8 | 203.4 | 811.2 |
| 14 | एफएमएस-विजडम, बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली, राजस्थान | 120.6 | 185.6 | 114.9 | 108.5 | 108.1 | 637.7 | 100.5 | 738.2 |
| 15 | लिंगायाज ललिता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐंड साइंसेज, नई दिल्ली | 113.8 | 146.8 | 107.6 | 117.0 | 108.1 | 593.3 | 143.4 | 736.7 |
| 16 | एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, जालंधर | 94.7 | 128.4 | 47.1 | 70.1 | 136.1 | 476.4 | 259.5 | 735.9 |
| 17 | यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मोहाली | 125.8 | 158.3 | 121.6 | 113.8 | 107.3 | 626.8 | 103.8 | 730.6 |
| 18 | स्कूल ऑफ बिजनेस ऐंड मैनेजमेंट, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर | 120.3 | 148.1 | 120.4 | 121.5 | 93.1 | 603.4 | 126.9 | 730.3 |
| 19 | पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज, जयपुर | 109.7 | 119.4 | 96.7 | 120.2 | 128.4 | 574.4 | 150.6 | 725.0 |
| 20 | स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, आइएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, देहरादून | 63.4 | 164.6 | 108.3 | 103.0 | 133.8 | 573.1 | 132.4 | 705.5 |
| 21 | देवकी देवी जैन मेमोरियल कॉलेज फॉर विमेन, लुधियाना | 136.7 | 75.2 | 91.2 | 107.3 | 106.2 | 516.6 | 160.3 | 676.9 |
| 22 | डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, आइआइएस (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), जयपुर | 119.5 | 176.0 | 120.5 | 125.9 | 85.4 | 627.3 | 30.0 | 657.3 |
| 23 | स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ऐंड कॉमर्स, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, जयपुर | 93.9 | 140.1 | 123.4 | 118.3 | 112.5 | 588.2 | 63.4 | 651.6 |
| 24 | सेंट विल्फ्रेड्स पीजी कॉलेज, जयपुर | 92.6 | 147.7 | 79.3 | 86.3 | 121.2 | 527.1 | 122.0 | 649.1 |
| 25 | अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ | 119.3 | 99.1 | 51.6 | 87.1 | 76.0 | 433.1 | 184.2 | 617.3 |
| 26 | परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस, जयपुर | 118.3 | 150.9 | 86.9 | 129.3 | 120.3 | 605.7 | 3.4 | 609.1 |
| 27 | पंजाब कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, लुधियाना | 88.0 | 144.4 | 108.4 | 109.7 | 82.0 | 532.5 | 49.7 | 582.2 |
| 28 | सनातन धर्म कॉलेज, अंबाला कैंट, अंबाला | 141.0 | 77.7 | 34.7 | 35.0 | 85.6 | 374.0 | 204.0 | 578.0 |
| 29 | उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देहरादून | 81.8 | 137.8 | 123.0 | 100.4 | 96.5 | 539.5 | 31.1 | 570.6 |
| 30 | फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ऐंड बिजनेस मैनेजमेंट, आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टी., हल्द्वानी | 79.7 | 145.3 | 102.7 | 98.3 | 113.9 | 539.9 | 0.0 | 539.9 |
| 31 | रामा पीजी कॉलेज, लखनऊ | 78.7 | 55.8 | 80.2 | 57.7 | 100.1 | 372.5 | 146.0 | 518.5 |

## मेडिकल

कॉलेजों की रैंक और उनके स्कोर

| उत्तर भारत में रैंक (प्राइवेट) 2021 | कॉलेज और शहर | इनटेक क्वालिटी और गवर्नेंस | अकादमिक गुणवत्ता | इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल | व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास | करियर की संभावना और प्लेसमेंट | ऑब्जेक्टिव स्कोर | धारणात्मक स्कोर | ओवरऑल स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 300 | 300 | 240 | 180 | 180 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| 1 | आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली | 142.3 | 186.9 | 166.9 | 122.9 | 123.7 | 742.7 | 621.2 | 1,363.9 |
| 2 | दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, लुधियाना | 195.9 | 223.9 | 155.6 | 120.3 | 78.0 | 773.7 | 577.2 | 1,350.9 |
| 3 | क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना | 155.0 | 200.4 | 200.4 | 124.5 | 93.1 | 773.4 | 551.9 | 1,325.3 |
| 4 | ईरा'ज लखनऊ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, लखनऊ | 139.8 | 201.7 | 185.1 | 133.2 | 115.4 | 775.2 | 539.3 | 1,314.5 |
| 5 | श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बरेली | 146.0 | 174.7 | 184.1 | 120.3 | 93.6 | 718.7 | 389.4 | 1,108.1 |
| 6 | श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ऐंड हेल्थ साइंसेज, देहरादून | 111.1 | 111.6 | 141.1 | 115.0 | 74.7 | 553.5 | 117.6 | 671.1 |

## इंजीनियरिंग

कॉलेजों की रैंक और उनके स्कोर

| उत्तर भारत में रैंक (प्राइवेट) 2021 | कॉलेज और शहर | इनटेक क्वालिटी और गवर्नेंस | अकादमिक गुणवत्ता | इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल | व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास | करियर की संभावना और प्लेसमेंट | ऑब्जेक्टिव स्कोर | धारणात्मक स्कोर | ओवरऑल स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 288 | 264 | 240 | 120 | 288 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| 1 | बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐंड साइंस पिलानी (बिट्स पिलानी), पिलानी | 221.6 | 173.5 | 180.5 | 88.8 | 250.3 | 914.7 | 777.9 | 1,692.6 |
| 2 | थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, पटियाला | 207.1 | 153.3 | 178.7 | 85.6 | 178.9 | 803.6 | 714.9 | 1,518.5 |
| 3 | महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली | 199.5 | 121.0 | 150.6 | 65.5 | 169.6 | 706.2 | 481.8 | 1,188.0 |
| 4 | गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा | 188.5 | 113.0 | 150.5 | 64.5 | 123.0 | 639.5 | 544.3 | 1,183.8 |
| 5 | एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, नोएडा | 140.6 | 166.0 | 160.1 | 67.3 | 147.3 | 681.3 | 471.7 | 1,153.0 |

| उत्तर भारत में रैंक (प्राइवेट) 2021 | कॉलेज और शहर | इनटेक क्वालिटी और गवर्नेंस | अकादमिक गुणवत्ता | इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल | व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास | करियर की संभावना और प्लेसमेंट | ऑब्जेक्टिव स्कोर | धारणात्मक स्कोर | ओवरऑल स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 288 | 264 | 240 | 120 | 288 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| 6 | फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, मणिपाल यूनिवर्सिटी, जयपुर | 163.4 | 115.4 | 170.7 | 85.8 | 180.6 | 715.9 | 394.9 | 1,110.8 |
| 7 | जी.एल. बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐंड मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा | 132.8 | 150.2 | 157.1 | 75.3 | 146.3 | 661.7 | 437.0 | 1,098.7 |
| 8 | दि एलएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जयपुर | 164.3 | 148.0 | 144.5 | 70.3 | 164.1 | 691.2 | 313.1 | 1,004.3 |
| 9 | जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोएडा | 176.9 | 109.5 | 132.8 | 28.3 | 184.4 | 631.9 | 372.2 | 1,004.1 |
| 10 | स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम ऐंड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस), देहरादून | 163.8 | 144.9 | 156.8 | 66.3 | 161.4 | 693.2 | 306.0 | 999.2 |
| 11 | गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, लुधियाना | 190.8 | 122.1 | 160.5 | 63.8 | 113.5 | 650.7 | 336.2 | 986.9 |
| 12 | यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मोहाली | 112.2 | 151.2 | 173.2 | 67.0 | 142.0 | 645.6 | 306.3 | 951.9 |
| 13 | इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, चितकारा यूनिवर्सिटी, राजपुरा, पंजाब | 120.6 | 149.9 | 157.4 | 51.4 | 159.3 | 638.6 | 293.1 | 931.7 |
| 14 | अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद | 168.4 | 116.8 | 142.5 | 68.3 | 120.8 | 616.8 | 260.9 | 877.7 |
| 15 | फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद | 176.3 | 144.5 | 174.4 | 72.0 | 95.4 | 662.6 | 194.5 | 857.1 |
| 16 | स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा | 177.2 | 92.3 | 113.4 | 42.2 | 97.1 | 522.2 | 332.3 | 854.5 |
| 17 | डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, जालंधर | 185.8 | 84.0 | 172.8 | 70.0 | 120.3 | 632.9 | 209.5 | 842.4 |
| 18 | जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ऐंड रिसर्च सेंटर, जयपुर | 170.2 | 83.3 | 108.4 | 68.2 | 157.0 | 587.1 | 253.9 | 841.0 |
| 19 | इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड मैनेजमेंट, जयपुर | 99.9 | 95.6 | 170.2 | 78.9 | 119.1 | 563.7 | 270.6 | 834.3 |
| 20 | श्री रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड मैनेजमेंट, लखनऊ | 123.9 | 86.1 | 139.3 | 45.1 | 84.4 | 478.8 | 353.1 | 831.9 |
| 21 | इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, जयपुर | 101.1 | 128.0 | 179.9 | 68.9 | 91.4 | 569.3 | 262.5 | 831.8 |
| 22 | प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर | 177.0 | 72.8 | 142.0 | 52.1 | 130.0 | 573.9 | 253.9 | 827.8 |
| 23 | स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा | 101.1 | 125.1 | 165.6 | 68.8 | 123.2 | 583.8 | 243.6 | 827.4 |
| 24 | चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, मोहाली | 134.7 | 113.7 | 138.6 | 64.8 | 152.4 | 604.2 | 209.1 | 813.3 |
| 25 | एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ | 152.1 | 132.0 | 165.5 | 56.5 | 137.9 | 644.0 | 131.9 | 775.9 |
| 26 | यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड रिसर्च, प्रयागराज | 127.1 | 115.5 | 122.9 | 49.5 | 136.6 | 551.6 | 145.3 | 696.9 |
| 27 | एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लखनऊ | 127.8 | 143.5 | 163.5 | 30.0 | 137.1 | 601.9 | 88.5 | 690.4 |
| 28 | इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, जीएलए यूनिवर्सिटी, मथुरा | 103.6 | 117.5 | 167.6 | 55.5 | 139.9 | 584.1 | 101.8 | 685.9 |
| 29 | केआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गाजियाबाद | 133.8 | 99.4 | 136.6 | 56.7 | 119.8 | 546.3 | 135.9 | 682.2 |
| 30 | स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा | 162.6 | 142.3 | 135.6 | 77.9 | 55.6 | 574.0 | 106.1 | 680.1 |
| 31 | श्री राम मूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, बरेली | 103.3 | 120.6 | 160.8 | 57.3 | 122.7 | 564.7 | 112.0 | 676.7 |
| 32 | एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐंड मैनेजमेंट, कानपुर | 129.3 | 108.2 | 144.5 | 51.7 | 113.9 | 547.6 | 123.3 | 670.9 |
| 33 | जेआइएमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस, ग्रेटर नोएडा | 168.0 | 121.4 | 151.8 | 31.0 | 90.3 | 562.5 | 95.7 | 658.2 |
| 34 | फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद | 156.8 | 122.7 | 156.1 | 66.6 | 47.2 | 549.4 | 105.5 | 654.9 |
| 35 | गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज, उदयपुर | 126.3 | 121.6 | 164.4 | 49.9 | 93.3 | 555.5 | 75.0 | 630.5 |
| 36 | शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, मेरठ | 126.1 | 121.1 | 143.9 | 55.1 | 109.7 | 555.9 | 73.3 | 629.2 |
| 37 | सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐंड इंजीनियरिंग, मेरठ | 116.3 | 152.1 | 173.9 | 15.3 | 36.1 | 493.7 | 129.4 | 623.1 |
| 38 | रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की | 106.3 | 135.5 | 156.3 | 52.1 | 133.7 | 583.9 | 35.8 | 619.7 |
| 39 | महर्षि मार्कंडेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज, मुलाना-अंबाला | 107.9 | 139.5 | 158.9 | 48.2 | 82.2 | 536.7 | 62.4 | 599.1 |
| 40 | कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर | 128.4 | 66.3 | 164.9 | 78.2 | 71.5 | 509.3 | 82.8 | 592.1 |
| 41 | सेठ जय प्रकाश मुकंद लाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, यमुनानगर | 138.4 | 70.4 | 140.2 | 49.5 | 120.6 | 519.1 | 68.4 | 587.5 |
| 42 | आइटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्रेटर नोएडा | 116.2 | 131.8 | 158.0 | 68.6 | 79.9 | 554.5 | 22.7 | 577.2 |
| 43 | शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून | 107.3 | 102.3 | 167.3 | 69.0 | 94.5 | 540.4 | 22.7 | 563.1 |
| 44 | पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, जयपुर | 99.5 | 125.7 | 149.5 | 59.9 | 79.9 | 514.5 | 23.5 | 538.0 |
| 45 | राजश्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐंड टेक्नोलॉजी, बरेली | 97.1 | 142.5 | 158.2 | 14.5 | 55.4 | 467.7 | 0.0 | 467.7 |

# उत्तर भारत के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज

## आर्किटेक्चर

कॉलेजों की रैंक और उनके स्कोर

| उत्तर भारत में रैंक (प्राइवेट) 2021 | कॉलेज और शहर | इनटेक क्वालिटी और गवर्नेंस | अकादमिक गुणवत्ता | इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल | व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास | करियर की संभावना और प्लेसमेंट | ऑब्जेक्टिव स्कोर | धारणात्मक स्कोर | ओवरऑल स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 275 | 260 | 240 | 150 | 275 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| 1 | सुशांत स्कूल ऑफ आर्ट ऐंड आर्किटेक्चर, गुरुग्राम | 179.3 | 168.7 | 157.4 | 103.7 | 159.8 | 768.9 | 531.6 | 1,300.5 |
| 2 | एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ऐंड प्लानिंग, नोएडा | 188.2 | 166.7 | 170.8 | 98.3 | 164.9 | 788.9 | 510.7 | 1,299.6 |
| 3 | एमबीएस स्कूल ऑफ प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली | 146.1 | 125.3 | 133.2 | 65.8 | 162.4 | 632.8 | 424.4 | 1,057.2 |
| 4 | एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ऐंड प्लानिंग, लखनऊ | 159.9 | 152.2 | 200.0 | 103.8 | 146.4 | 762.3 | 291.7 | 1,054.0 |
| 5 | एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, कानपुर | 158.4 | 126.3 | 185.1 | 101.0 | 163.0 | 733.8 | 260.7 | 994.5 |
| 6 | चितकारा स्कूल ऑफ प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर, पटियाला | 161.2 | 171.3 | 146.2 | 104.2 | 161.6 | 744.5 | 223.2 | 967.7 |
| 7 | स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा | 145.9 | 185.4 | 194.7 | 101.5 | 84.9 | 712.4 | 211.2 | 923.6 |
| 8 | फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर ऐंड प्लानिंग, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ | 173.0 | 153.5 | 180.9 | 102.4 | 147.1 | 756.9 | 154.6 | 911.5 |
| 9 | आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जयपुर | 133.9 | 102.1 | 124.3 | 87.3 | 136.8 | 584.4 | 284.5 | 868.9 |
| 10 | स्कूल ऑफ प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, जयपुर | 151.4 | 140.2 | 177.1 | 100.9 | 139.1 | 708.7 | 82.3 | 791.0 |
| 11 | सुंदर दीप कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, गाजियाबाद | 161.8 | 126.2 | 155.8 | 84.5 | 163.0 | 691.3 | 0.0 | 691.3 |

## लॉ

कॉलेजों की रैंक और उनके स्कोर

| उत्तर भारत में रैंक (प्राइवेट) 2021 | कॉलेज और शहर | इनटेक क्वालिटी और गवर्नेंस | अकादमिक गुणवत्ता | इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल | व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास | करियर की संभावना और प्लेसमेंट | ऑब्जेक्टिव स्कोर | धारणात्मक स्कोर | ओवरऑल स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 210 | 300 | 180 | 240 | 270 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| 1 | आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली | 130.9 | 220.3 | 143.1 | 159.7 | 171.5 | 825.5 | 520.4 | 1,345.9 |
| 2 | लॉयड लॉ कॉलेज, ग्रेटर नोएडा | 131.7 | 224.1 | 130.0 | 172.6 | 172.7 | 831.1 | 489.6 | 1,320.7 |
| 3 | स्कूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम ऐंड एनर्जी स्टडीज, देहरादून | 138.1 | 182.6 | 139.2 | 170.6 | 156.9 | 787.4 | 510.1 | 1,297.5 |
| 4 | एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा | 104.6 | 223.8 | 144.0 | 167.1 | 148.3 | 787.8 | 437.1 | 1,224.9 |
| 5 | स्कूल ऑफ लॉ, आइएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, देहरादून | 113.1 | 224.2 | 141.7 | 156.3 | 159.3 | 794.6 | 289.2 | 1,083.8 |
| 6 | आइसीएफएआइ लॉ स्कूल, देहरादून | 124.2 | 174.7 | 129.9 | 132.3 | 147.8 | 708.9 | 360.2 | 1,069.1 |
| 7 | आइएमएस लॉ कॉलेज, नोएडा | 112.2 | 197.3 | 125.7 | 147.1 | 161.0 | 743.3 | 322.4 | 1,065.7 |
| 8 | स्कूल ऑफ लॉ, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा | 128.1 | 222.8 | 150.2 | 153.8 | 149.8 | 804.7 | 222.6 | 1,027.3 |
| 9 | स्कूल ऑफ लॉ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा | 129.6 | 189.6 | 144.9 | 145.0 | 143.0 | 752.1 | 264.7 | 1,016.8 |
| 10 | लॉ कॉलेज देहरादून, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, देहरादून | 125.6 | 220.5 | 129.5 | 145.8 | 171.8 | 793.2 | 211.3 | 1,004.5 |
| 11 | एमिटी लॉ स्कूल, गुरुग्राम | 118.5 | 220.3 | 154.8 | 159.7 | 154.4 | 807.7 | 196.3 | 1,004.0 |
| 12 | विवेकानंद स्कूल ऑफ लॉ ऐंड लीगल स्टडीज, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (वीआइपीएस), नई दिल्ली | 134.7 | 159.6 | 116.8 | 167.4 | 155.0 | 733.5 | 269.3 | 1,002.8 |
| 13 | एमिटी लॉ स्कूल, लखनऊ | 118.1 | 191.2 | 145.1 | 135.5 | 165.6 | 755.5 | 245.7 | 1,001.2 |
| 14 | सेंट विल्फ्रेड्स कॉलेज ऑफ लॉ, जयपुर | 115.0 | 183.2 | 140.9 | 145.6 | 150.5 | 735.2 | 151.1 | 886.3 |
| 15 | डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, अंबाला | 82.0 | 171.2 | 145.4 | 92.6 | 152.4 | 643.6 | 212.9 | 856.5 |
| 16 | चंद्रप्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज ऐंड स्कूल ऑफ लॉ, नई दिल्ली | 136.1 | 174.0 | 128.7 | 155.9 | 137.5 | 732.2 | 98.6 | 830.8 |
| 17 | सीडलिंग स्कूल ऑफ लॉ ऐंड गवर्नेंस, जयपुर | 121.8 | 212.3 | 149.4 | 143.5 | 45.2 | 672.2 | 135.9 | 808.1 |
| 18 | सेंट सोल्जर लॉ कॉलेज, जालंधर | 116.6 | 115.2 | 116.3 | 146.9 | 162.4 | 657.4 | 117.5 | 774.9 |
| 19 | इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज ऐंड रिसर्च, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ | 108.1 | 130.2 | 140.1 | 83.1 | 140.0 | 601.5 | 145.5 | 747.0 |
| 20 | गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पानीपत | 93.7 | 170.5 | 130.6 | 136.6 | 121.3 | 652.7 | 50.4 | 703.1 |
| 21 | श्री गिरराज महाराज कॉलेज ऑफ लॉ ऐंड प्रोफेशनल स्टडीज, मथुरा | 102.4 | 94.2 | 105.9 | 98.8 | 72.1 | 473.4 | 0.0 | 473.4 |

| उत्तर भारत में रैंक (प्राइवेट) 2021 | कॉलेज और शहर | इनटेक क्वालिटी और गवर्नेंस | अकादमिक गुणवत्ता | इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल | व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास | करियर की संभावना और प्लेसमेंट | ऑब्जेक्टिव स्कोर | धारणात्मक स्कोर | ओवरऑल स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 240 | 270 | 180 | 210 | 300 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| 1 | एमिटी स्कूल ऑफ बिजनेस, नोएडा | 157.0 | 215.4 | 142.6 | 151.7 | 233.8 | 900.5 | 759.5 | 1,660.0 |
| 2 | महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली | 175.6 | 191.4 | 121.9 | 121.3 | 222.9 | 833.1 | 661.1 | 1,494.2 |
| 3 | जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नई दिल्ली | 157.4 | 222.2 | 93.5 | 168.1 | 233.3 | 874.5 | 535.4 | 1,409.9 |
| 4 | गोस्वामी गणेश दत्त एसडी कॉलेज, चंडीगढ़ | 178.3 | 167.0 | 136.3 | 166.6 | 208.4 | 856.6 | 544.8 | 1,401.4 |
| 5 | जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, वसंत कुंज, नई दिल्ली | 152.4 | 152.1 | 77.1 | 149.9 | 214.1 | 745.6 | 632.2 | 1,377.8 |
| 6 | स्कूल ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम ऐंड एनर्जी स्टडीज, देहरादून | 154.9 | 203.1 | 121.9 | 125.9 | 225.6 | 831.4 | 539.2 | 1,370.6 |
| 7 | जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, कालकाजी, नई दिल्ली | 143.1 | 182.9 | 92.0 | 188.0 | 218.8 | 824.8 | 543.3 | 1,368.1 |
| 8 | इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नोएडा | 143.8 | 175.9 | 95.6 | 126.8 | 194.3 | 736.4 | 580.3 | 1,316.7 |
| 9 | स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, आइएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, देहरादून | 117.9 | 123.2 | 115.9 | 124.8 | 206.5 | 688.3 | 594.4 | 1,282.7 |
| 10 | दून बिजनेस स्कूल, देहरादून | 133.6 | 168.9 | 129.4 | 174.7 | 179.0 | 785.6 | 492.2 | 1,277.8 |
| 11 | एस.एस. जैन सुबोध पीजी (स्वायत्त) कॉलेज, जयपुर | 171.0 | 157.7 | 96.9 | 104.5 | 208.8 | 738.9 | 497.7 | 1,236.6 |
| 12 | आ.टी.एस. यूजी इंस्टीट्यूट, मोहन नगर, गाजियाबाद | 158.4 | 185.7 | 119.3 | 162.9 | 201.2 | 827.5 | 407.9 | 1,235.4 |
| 13 | विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, नई दिल्ली | 172.2 | 140.0 | 59.1 | 119.2 | 184.2 | 674.7 | 530.4 | 1,205.1 |
| 14 | एमिटी बिजनेस स्कूल, गुरुग्राम | 118.5 | 204.1 | 125.7 | 143.9 | 168.7 | 760.9 | 441.8 | 1,202.7 |
| 15 | एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, जालंधर | 167.9 | 153.8 | 69.2 | 129.8 | 173.2 | 693.9 | 478.3 | 1,172.2 |
| 16 | डीएवी कॉलेज, सेक्टर-10, चंडीगढ़ | 166.3 | 99.7 | 115.4 | 118.1 | 185.7 | 685.2 | 485.4 | 1,170.6 |
| 17 | कन्या महा विद्यालय जालंधर (स्वायत्त), जालंधर | 197.3 | 141.7 | 116.3 | 127.3 | 205.2 | 787.8 | 382.5 | 1,170.3 |
| 18 | चंडीगढ़ बिजनेस स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मोहाली | 135.5 | 178.7 | 132.0 | 95.7 | 214.2 | 756.1 | 365.9 | 1,122.0 |
| 19 | यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मोहाली | 140.4 | 176.0 | 127.6 | 130.1 | 216.0 | 790.1 | 290.0 | 1,080.1 |
| 20 | लिंगायाज ललिता देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐंड साइंसेज, नई दिल्ली | 152.4 | 161.8 | 107.9 | 126.8 | 197.7 | 746.6 | 332.8 | 1,079.4 |
| 21 | डीएवी सेंटेनरी कॉलेज, फरीदाबाद | 169.5 | 116.9 | 94.2 | 111.7 | 150.9 | 643.2 | 423.3 | 1,066.5 |
| 22 | चितकारा बिजनेस स्कूल, राजपुरा, पंजाब | 126.1 | 185.6 | 140.4 | 169.6 | 142.7 | 764.4 | 299.7 | 1,064.1 |
| 23 | फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, पीसीटीई, लुधियाना | 115.9 | 151.9 | 120.8 | 152.0 | 192.2 | 732.8 | 278.4 | 1,011.2 |
| 24 | फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, आइसीएफएआइ बिजनेस स्कूल, जयपुर | 103.4 | 165.3 | 148.6 | 187.9 | 194.2 | 799.4 | 185.0 | 984.4 |
| 25 | बीबीके डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, अमृतसर | 177.6 | 105.5 | 96.6 | 105.1 | 159.4 | 644.2 | 339.4 | 983.6 |
| 26 | इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, जयपुर | 124.6 | 161.3 | 156.5 | 127.5 | 151.6 | 721.5 | 255.4 | 976.9 |
| 27 | स्कूल ऑफ बिजनेस ऐंड मैनेजमेंट, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर | 148.5 | 148.8 | 126.3 | 150.0 | 185.3 | 758.9 | 217.9 | 976.8 |
| 28 | स्कूल ऑफ बिजनेस, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा | 103.8 | 122.0 | 100.7 | 93.8 | 187.7 | 608.0 | 353.8 | 961.8 |
| 29 | टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, नई दिल्ली | 136.5 | 141.9 | 86.2 | 96.1 | 149.5 | 610.2 | 348.5 | 958.7 |
| 30 | सेंट विल्फ्रेड्स पीजी कॉलेज, जयपुर | 127.4 | 139.4 | 121.5 | 125.5 | 200.8 | 714.6 | 219.5 | 934.1 |
| 31 | पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज, जयपुर | 145.0 | 114.3 | 116.5 | 178.2 | 200.7 | 754.7 | 157.5 | 912.2 |
| 32 | एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, कानपुर | 125.1 | 126.2 | 118.8 | 122.9 | 188.3 | 681.3 | 230.5 | 911.8 |
| 33 | जेआइएमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस, ग्रेटर नोएडा | 106.8 | 94.9 | 80.2 | 85.8 | 203.2 | 570.9 | 333.2 | 904.1 |
| 34 | उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देहरादून | 109.6 | 119.2 | 117.1 | 101.7 | 188.4 | 636.0 | 262.0 | 898.0 |
| 35 | डीएवी कॉलेज, अबोहर, पंजाब | 168.7 | 153.6 | 126.2 | 120.8 | 113.0 | 682.3 | 215.3 | 897.6 |
| 36 | ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐंड टेक्नोलॉजी, मोहाली | 133.0 | 171.4 | 116.4 | 144.4 | 179.0 | 744.2 | 140.3 | 884.5 |
| 37 | स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ऐंड कॉमर्स, संस्कृति यूनिवर्सिटी, मथुरा | 122.6 | 175.9 | 137.0 | 139.6 | 196.6 | 771.7 | 106.2 | 877.9 |
| 38 | देवकी देवी जैन मेमोरियल कॉलेज फॉर विमेन, लुधियाना | 163.4 | 76.1 | 93.9 | 115.9 | 125.9 | 575.2 | 299.3 | 874.5 |
| 39 | पीएसआइटी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, कानपुर | 98.4 | 115.6 | 122.0 | 92.7 | 195.6 | 624.3 | 221.6 | 845.9 |
| 40 | ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, तुला'ज इंस्टीट्यूट, देहरादून | 83.4 | 101.7 | 116.0 | 127.6 | 178.4 | 607.1 | 221.1 | 828.2 |
| 41 | डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, आइआइएस (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), जयपुर | 142.4 | 151.1 | 131.5 | 129.2 | 145.1 | 699.3 | 127.4 | 826.7 |
| 42 | आचार्य विष्णु गुप्त सुभारती कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ऐंड कॉमर्स, मेरठ | 158.4 | 132.5 | 140.4 | 69.3 | 113.1 | 613.7 | 137.6 | 751.3 |
| 43 | फैकल्टी ऑफ कॉमर्स ऐंड बिजनेस मैनेजमेंट, आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हल्द्वानी | 105.2 | 88.5 | 111.1 | 77.4 | 143.6 | 525.8 | 123.7 | 649.5 |
| 44 | इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मेडिसिन्स ऐंड रिसर्च, गाजियाबाद | 98.8 | 117.5 | 80.1 | 100.7 | 135.0 | 532.1 | 65.5 | 597.6 |
| 45 | विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बिजनौर | 142.2 | 133.9 | 85.4 | 81.8 | 126.5 | 569.8 | 22.4 | 592.2 |
| 46 | रामा पीजी कॉलेज, लखनऊ | 108.9 | 36.8 | 89.6 | 113.0 | 123.9 | 472.2 | 108.9 | 581.1 |
| 47 | पं. दीन दयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज, मेरठ | 89.5 | 72.1 | 33.3 | 42.2 | 192.5 | 429.6 | 0.0 | 429.6 |

# उत्तर भारत के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज

## बीसीए

### कॉलेजों की रैंक और उनके स्कोर

| उत्तर भारत में रैंक (प्राइवेट) 2021 | कॉलेज और शहर | इनपुट क्वालिटी और गवर्नेंस | अकादमिक गुणवत्ता | इन्फ्रास्ट्रक्चर और माहौल | व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास | करियर की संभावना और प्लेसमेंट | ऑब्जेक्टिव स्कोर | धारणात्मक स्कोर | ओवरऑल स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 210 | 270 | 240 | 180 | 300 | 1,200 | 800 | 2,000 |
| 1 | एमिटी इ स्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोएडा | 133.2 | 217.0 | 198.5 | 140.0 | 227.6 | 916.3 | 756.6 | 1,672.9 |
| 2 | महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली | 153.0 | 200.3 | 178.5 | 160.4 | 203.1 | 895.3 | 697.8 | 1,593.1 |
| 3 | एम ऐंड ऐक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, बनस्थली विद्यापीठ | 142.6 | 195.1 | 174.2 | 124.3 | 193.8 | 830.0 | 702.8 | 1,532.8 |
| 4 | जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रोहिणी, नई दिल्ली | 142.0 | 203.9 | 134.0 | 148.5 | 224.2 | 852.6 | 600.3 | 1,452.9 |
| 5 | गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, चंडीगढ़ | 157.9 | 175.9 | 186.6 | 142.3 | 209.3 | 872.0 | 573.3 | 1,445.3 |
| 6 | स्कूल ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आइएमएस, नोएडा | 145.3 | 187.9 | 116.5 | 136.1 | 207.4 | 793.2 | 637.6 | 1,430.8 |
| 7 | डीएवी कॉलेज, सेक्टर-10, चंडीगढ़ | 158.6 | 163.3 | 172.0 | 101.8 | 211.4 | 807.1 | 618.5 | 1,425.6 |
| 8 | जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, वसंत कुंज, नई दिल्ली | 141.7 | 178.2 | 139.6 | 122.0 | 207.2 | 788.7 | 608.1 | 1,396.8 |
| 9 | इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐंड साइंस (आइटीएस) यूजी कैंपस, मोहन नगर, गाजियाबाद | 137.4 | 180.7 | 170.8 | 121.9 | 207.9 | 818.7 | 574.8 | 1,393.5 |
| 10 | कन्या महा विद्यालय, जालंधर | 177.4 | 170.2 | 161.1 | 102.9 | 218.6 | 830.2 | 551.8 | 1,382.0 |
| 11 | एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ | 134.3 | 214.0 | 195.0 | 117.6 | 222.1 | 883.0 | 481.3 | 1,364.3 |
| 12 | एस.एस. जैन सुबोध पीजी (स्वायत्त) कॉलेज, जयपुर | 163.9 | 185.5 | 163.4 | 120.9 | 216.3 | 850.0 | 511.3 | 1,361.3 |
| 13 | मेहर चंद महाजन डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, चंडीगढ़ | 139.6 | 201.4 | 171.1 | 130.2 | 214.4 | 856.7 | 488.8 | 1,345.5 |
| 14 | डीएवी कॉलेज, होशियारपुर | 158.1 | 204.6 | 189.7 | 133.8 | 202.0 | 888.2 | 435.3 | 1,323.5 |
| 15 | चंद्रप्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज ऐंड स्कूल ऑफ लॉ, नई दिल्ली | 86.2 | 135.3 | 169.7 | 143.3 | 225.6 | 760.1 | 470.1 | 1,230.2 |
| 16 | यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मोहाली | 145.2 | 186.6 | 196.5 | 143.6 | 215.6 | 887.5 | 326.7 | 1,214.2 |
| 17 | चितकारा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेक्नोलॉजी, पटियाला | 112.1 | 199.6 | 189.1 | 131.9 | 159.4 | 792.1 | 392.3 | 1,184.4 |
| 18 | स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंस ऐंड इंजीनियरिंग, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा | 109.3 | 147.2 | 165.9 | 90.0 | 141.6 | 654.0 | 513.5 | 1,167.5 |
| 19 | जेआइएमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस (जेईएमटीइसी), ग्रेटर नोएडा | 119.9 | 137.0 | 158.3 | 106.4 | 203.4 | 725.0 | 421.8 | 1,146.8 |
| 20 | बीबीके डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, अमृतसर | 155.2 | 154.0 | 136.5 | 88.4 | 210.5 | 744.6 | 387.5 | 1,132.1 |
| 21 | डीएवी कॉलेज, अबोहर, पंजाब | 144.0 | 195.3 | 163.2 | 121.9 | 164.1 | 788.5 | 265.5 | 1,054.0 |
| 22 | पंजाब कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, लुधियाना | 123.1 | 156.0 | 161.0 | 135.4 | 182.2 | 757.7 | 290.2 | 1,047.9 |
| 23 | स्कूल ऑफ कंप्यूटर ऐंड सिस्टम्स साइंसेज, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर | 124.4 | 187.0 | 179.8 | 135.9 | 220.9 | 848.0 | 187.1 | 1,035.1 |
| 24 | सेंट विल्फ्रेड्स पीजी कॉलेज, जयपुर | 129.2 | 189.2 | 175.2 | 101.3 | 202.4 | 797.3 | 148.7 | 946.0 |
| 25 | एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, कानपुर | 112.5 | 135.3 | 161.0 | 88.7 | 199.9 | 697.4 | 227.5 | 924.9 |
| 26 | पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज, जयपुर | 129.9 | 199.7 | 168.0 | 148.9 | 161.0 | 807.5 | 104.2 | 911.7 |
| 27 | डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ऐंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आइआइएस (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी), जयपुर | 149.8 | 182.9 | 194.8 | 119.1 | 189.0 | 835.6 | 68.9 | 904.5 |
| 28 | आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंस, हल्द्वानी | 101.9 | 162.0 | 173.9 | 94.8 | 216.1 | 748.7 | 154.0 | 902.7 |
| 29 | एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, जालंधर | 136.4 | 195.9 | 135.2 | 144.6 | 161.8 | 773.9 | 117.5 | 891.4 |
| 30 | उत्तरांचल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देहरादून | 110.0 | 166.7 | 177.8 | 119.3 | 216.7 | 790.5 | 100.4 | 890.9 |
| 31 | पीएसआइटी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, कानपुर | 126.9 | 168.1 | 171.1 | 75.8 | 199.2 | 741.1 | 116.4 | 857.5 |
| 32 | डीएवी सेंटेनरी कॉलेज, फरीदाबाद | 133.9 | 159.1 | 83.2 | 89.3 | 182.7 | 648.2 | 206.1 | 854.3 |
| 33 | देवकी देवी जैन मेमोरियल कॉलेज फॉर विमेन, लुधियाना | 138.0 | 120.6 | 104.1 | 64.3 | 144.7 | 571.7 | 120.6 | 692.3 |
| 34 | लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज, जयपुर | 111.7 | 141.2 | 104.6 | 95.4 | 185.1 | 638.0 | 0.0 | 638.0 |
| 35 | जगदीश चंद्र डीएवी कॉलेज, दसूया | 128.6 | 137.3 | 114.1 | 78.4 | 114.0 | 572.4 | 9.7 | 582.1 |
| 36 | परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस, जयपुर | 122.8 | 138.1 | 78.9 | 91.4 | 129.3 | 560.5 | 4.6 | 565.1 |
| 37 | पं. दीन दयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज, मेरठ | 75.8 | 114.4 | 50.2 | 38.4 | 176.6 | 455.4 | 99.9 | 555.3 |

*1. रैंकिंग ऑब्जेक्टिव डेटा और धारणात्मक सर्वे डेटा पर आधारित है.*
*2. केवल उन्हीं कॉलेजों की रैंकिंग की गई है जिन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव डेटा जमा किया था.*
*3. रैंकिंग में भाग लेने के लिए केवल उन्हीं कॉलेजों को योग्य माना गया जिन्होंने निम्नलिखित मानक पूरा किया था: कम-से-कम तीन बेच उत्तीर्ण होकर निकले हों; जो फुलटाइम अंडरग्रेजुएट (यूजी) प्रोग्राम ऑफर करते हों.*
*4. सभी स्कोर की गणना दशमलव के एक अंक तक ही की गई है; मानकवार स्कोर जोड़ने में हो सकता है कि त्रुटियां दिख जाएं.*
*5. जिन कॉलेजों की धारणात्मक सर्वे में रैंकिंग नहीं की गई है उनका धारणात्मक स्कोर शून्य है*

किताबें

# समलैंगिक प्रेम की दास्तान

**देवेंद्र राज अंकुर**

हाल ही में रूथ वनिता का हिंदी में एक उपन्यास आया है *परियों के बीच*. कहना तो यह चाहिए कि यह उनका पहला उपन्यास है जो *मेमोरी ऑफ लाइट* नाम से अंग्रेजी में आ चुका है. लेखक ने स्वयं इसका हिंदी में पुनर्लेखन किया है. किताब में अगर यह सूचना न दी गई होती तो निश्चय ही उसे एक मौलिक रचना माना जाता. वनिता ने हिंदी भाषा के जिस तेवर, मुहावरे और व्यवहार के प्रयोग से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्थित अवध रियासत के दौरान कोठों की अंदरूनी दुनिया को उजागर किया है, निश्चय ही उसका चित्रण इस रचना को एक खास पहचान देता है.

यह पहचान मात्र अपने भाषायी स्वरूप के कारण ही नहीं वरन अपनी विषय-वस्तु को लेकर भी बनती है. समलैंगिक प्रेम आरंभ से ही समाज में तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, भले उसकी उपस्थिति हमेशा से रही हो. लेकिन जिस रूप में यह संबंद्ध दो औरतों, मशहर तवायफ चपला बाई और शायरा नफीस बाई के माध्यम से उद्घाटित किया गया है, उसकी कोमलता, सूक्ष्मता और मार्मिकता देखते ही बनती हैं. उसके भीतर से गुजरकर इस रिश्ते को कुछ अपवित्र या अछूत जैसा मानने का एहसास ही खत्म हो जाता है.

सारी कथा नफीस बाई की डायरी के रास्ते हम तक पहुंचती है. मुख्य रूप से लखनऊ और बनारस के साथ-साथ मुख्य किरदार कलकत्ता और दिल्ली से भी होकर आते हैं. कई-कई पगडंडियां साथ चलती हैं. तवायफों के कोठों और उनके घर-परिवार का अंतरंग चित्र—उनका रहन-सहन खान-पान तीज-त्यौहार, वेशभूषा-शृंगार—कोई पक्ष ऐसा नहीं जो हमारी नजरों से अनदेखा रह जाए. उपन्यास के रूप में इसे तत्कालीन तवायफ समाज का गहरा दस्तावेज कहा जा सकता है.

उपन्यास में यथार्थ और कल्पना का अद्भुत संगम है. एक तरफ उस वक्त के मशहूर शायर कथा में जबरदस्त उपस्थिति दर्ज करते हैं, दूसरी तरफ कंपनी राज से जुड़े कई बड़े अफसरान, उनकी बीवियों और इनके बीच रिश्तों की एक लंबी दास्तान से गुजरतीं चपला बाई और नफीस बाई. एक हिंदू, एक मुसलमान पर लगता ही नहीं कि दोनों कहीं अलग हैं. ठीक यही बात शरद और दूसरे मुस्लिम शायरों के रिश्ते के बारे में कही जा सकती है.

इतने सारे ऐतिहासिक तथ्यों, ब्यौरों और रिसर्च के बावजूद कहीं भी किस्सागोई का अंदाज छूटता नहीं. रचना की यही सबसे बड़ी खूबी है. जिस रिश्ते की कहानी सुनाई जा रही है, वह बिना किसी दस्तक के कब कथा में शामिल हो जाता है, पता ही नहीं चलता. इसका एकमात्र कारण है कि जिस सहजता से वनिता ने इस रिश्ते के कोमल तंतुओं को छुआ है उसी सहजता से उपन्यास के दूसरे पात्र भी उसे स्वीकारते हैं, उसमें मदद भी करते हैं.

यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि समलैंगिक को लेकर जो हौवा खड़ा किया जाता रहा है, उसे मिटाने में यह उपन्यास बहुत मददगार साबित होगा. एक बात और—जो लोग इस रिश्ते में सनसनीखेज जैसा कुछ ढूंढते हैं, उन्हें अवश्य झटका लगेगा. वे शायद विश्वास कर पाएं कि ऐसे रिश्ते भी सहज हो सकते हैं—इसके लिए लेखक को बहुत बधाई. ■

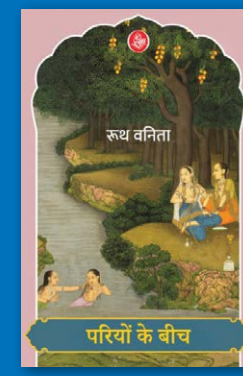


**परियों के बीच**
रूथ वनिता
राजकमल पेपरबैक्स, दिल्ली
कीमतः 199 रुपए

# लोकगाथा का जीवंत दस्तावेज

*कला वसुधा* का आल्हा प्रसंग अंक मात्र पत्रिका ही नहीं एक भरी-पूरी किताब है. संपादक दंपती शाखा वंद्योपाध्याय और डॉ. उषा बनर्जी ने पत्रिका के पूर्व के विशेषांको के क्रम में जिस श्रम से इसका संयोजन किया है वह सचमुच ध्यान खींचने वाला है.

बारहवीं सदी के लोककवि जगनिक का आल्हा खंड उत्तर भारत के दो पराक्रमी योद्धाओं आल्हा और ऊदल की शौर्य गाथा है. इसके गायन की परंपरा इतनी लोकप्रिय हुई कि यह एक शैली के रूप में विकसित हो कर आज आठ शताब्दी बाद भी उतनी ही लोकप्रिय बनी हुई है. बुंदेलखंड से उद्भूत आल्हा-गायन उत्तर भारत के कई क्षेत्रों, अवध और बैसवारा में अपनी विशिष्ट शैलियों के साथ खूब पल्लवित हुआ.

इस अंक में आल्हा के विभिन्न प्रसंगों पर शीर्षस्थ लोकविदों के तीसेक लेख हैं. इसमें जहां आल्हा के प्रणेता जगनिक के बारे में विस्तार से वर्णन है वहीं पर इसके नायक आल्हा-ऊदल का भी. बुंदेलखंड के अल्हैतों पर आलेख के साथ अवध और बैसवारा क्षेत्र के आल्हा की विशेषताएं भी हैं. आल्हा पहले पुरुष ही गाया करते थे लेकिन समय के साथ महिला अल्हैतों ने भी अपना वर्चस्व स्थापित किया है, उनके साक्षात्कार भी इसमें शामिल हैं. 'आल्हा गायन स्वर लिपि' का अध्याय आल्हा गायकी के व्याकरण को प्रकट करता है.

ऐसे समय में जहां पूरा हिंदी का साहित्य कविता-कहानियों में सिमट कर रह गया है, लोक साहित्य पर शोध और उसे संयोजित कर प्रकाशित करना अपने आप में श्रमसाध्य कार्य है. लोक से कट कर आप किसी सभ्यता के साथ न्याय नहीं कर सकते. *कलावसुधा* ने आल्हा पर यह संग्रहणीय विशेषांक निकाल कर एक बहुत बड़ी रिक्ति की पूर्ति की है.

—विजय पंडित

**कलावसुधाः आल्हा प्रसंग**
संपादकः
शाखा बंद्योपाध्याय/
डॉ. उषा बनर्जी
मेलः
kalavasudha01@gmail.com
कीमतः 100 रु.

सवाल+जवाब

# शिष्य हों संकल्प वाले

**मेवाती घराने के दिग्गज गायक पंडित संजीव अभ्यंकर उम्र, सौंदर्य-दृष्टि और शिष्य आदि मामले पर बेबाक राय रखते हुए उसी तरह प्रभावित करते हैं जैसे भक्ति संगीत गाते या रागदारी रंग सुनाते**

**● आप उन सिद्ध खयाल गायकों में से हैं जिन्होंने शुद्ध रागदारी को नई पीढ़ी में भी असाधारण लोकप्रियता दिलाई. आप स्वयं दिग्गज नाम हैं. क्या अभी भी मंच पर बैठते हुए कोई झिझक होती है?**

बेचैनी बस इसी बात की होती है कि क्षमता के मुताबिक जितना मैं दे सकता हूं, उतना दे सकूं. चिंता या डर कभी नहीं रहा. इसकी वजह मंच पर बैठने का आत्मविश्वास है, जो बाल्यकाल से था. संभवतः पिछले जन्म का कोई पुण्य प्रताप हो.

**● पुणे एक दौर में शास्त्रीय संगीत के लिए अपनी अलग साख रखता था. आज वह साख कितनी सुरक्षित है?**

अतीत हमेशा सुंदर होता है , लेकिन वर्तमान और भविष्य भी कोई चीज है. आज नए रसिक आ रहे हैं, उनमें भी वही आग, वही एप्रोच है. 1981 में 11 साल की उम्र में मैंने पहली महफिल गाई. आज चालीस साल हो गए. हर दशक में सुनकार पीढ़ी भी आगे चली जाती है. सिर्फ पुणे क्यों, देश में वे सारे शहर जहां गाने-बजाने का माहौल अपेक्षाकृत सुंदर है वहां दशक बदलते ही दृश्य भी बदलता है.

**● उम्र के असर से आप बेअसर दिखते हैं! बढ़ती जाती उम्र के साथ राग में छिपा सौंदर्य भी पेश करने के ढंग को नई समझ देता है क्या?**

बेशक शरीर की उम्र होती है लेकिन मन की भी होती है. अगर हम उसी का विचार करें तो नेगेटिविटी आती है. फिर व्यसन मुक्त जीवन. कर्म और नैसर्गिक ताकत भी शक्ति देते हैं. उम्र बढ़ने के साथ दृष्टिकोण निस्संदेह विस्तार लेता है. इसे मैं प्रतिभा के पड़ाव कहूंगा. गाना रोज नया लगना भी चाहिए. जैसे हम प्रेयसी से मिलते हैं उसी तरह रोज अपने गाने से मिलें.

**● जो सीखने आते हैं, उनमें न्यूनतम क्या देखकर उन्हें बतौर शिष्य स्वीकार करते हैं?**

कई बातें हैं. गले का स्वभाव पहले. फिर आवाज मेरी गायिकी की प्रकृति के अनुरूप हो. आवाज न हो तो सारी कल्पनाएं मन में ही रह जाएंगी, इसलिए आवाज बेहद जरूरी चीज है. मेरे गाने को लेकर उनका लगाव कितना है? सिर्फ नाम देख कर आए हों तो बात नहीं बनेगी. और बेशक, बेसिक गाना जानते हों. अर्थात् सीखे हों. यानी आगे कुछ सिद्ध करने की इच्छा से आए हों. बाद में उन पर है कि वे मेरा सान्निध्य कितना आत्मसात कर पाते हैं.

**● अभंग गायिकी आपके गले से अधिक असर पैदा करती है. अभंग या कह लें सुगम के प्रति लगाव कैसे आया?**

अभंग या संत रचनाओं के प्रति रुझान स्वाभाविक रूप से बालपन में मिला. मेरे गले की प्रकृति और आवाज का टेक्सचर अभंग के लिए जैसे एकाकार हो गए. लेकिन दोनों में तैरने का आनंद है. रागदारी असीमित समुद्र है और भक्ति संगीत उसका एक मोहक जलाशय. रागदारी में मुझे सभी रसों के शेड्स मिलते हैं जबकि अभंग का मूल रंग भक्ति अथवा निर्गुण रस का बहाव है. पूरी महफिल बगैर दोहराव रागदारी से जीती जाए—इतनी रचनात्मक संपदा मेरे पास हो, यह मेरा लक्ष्य था—और मैंने वह पाया, ऐसा विनम्रता से कह सकता हूं.

—राजेश गनोदवाले

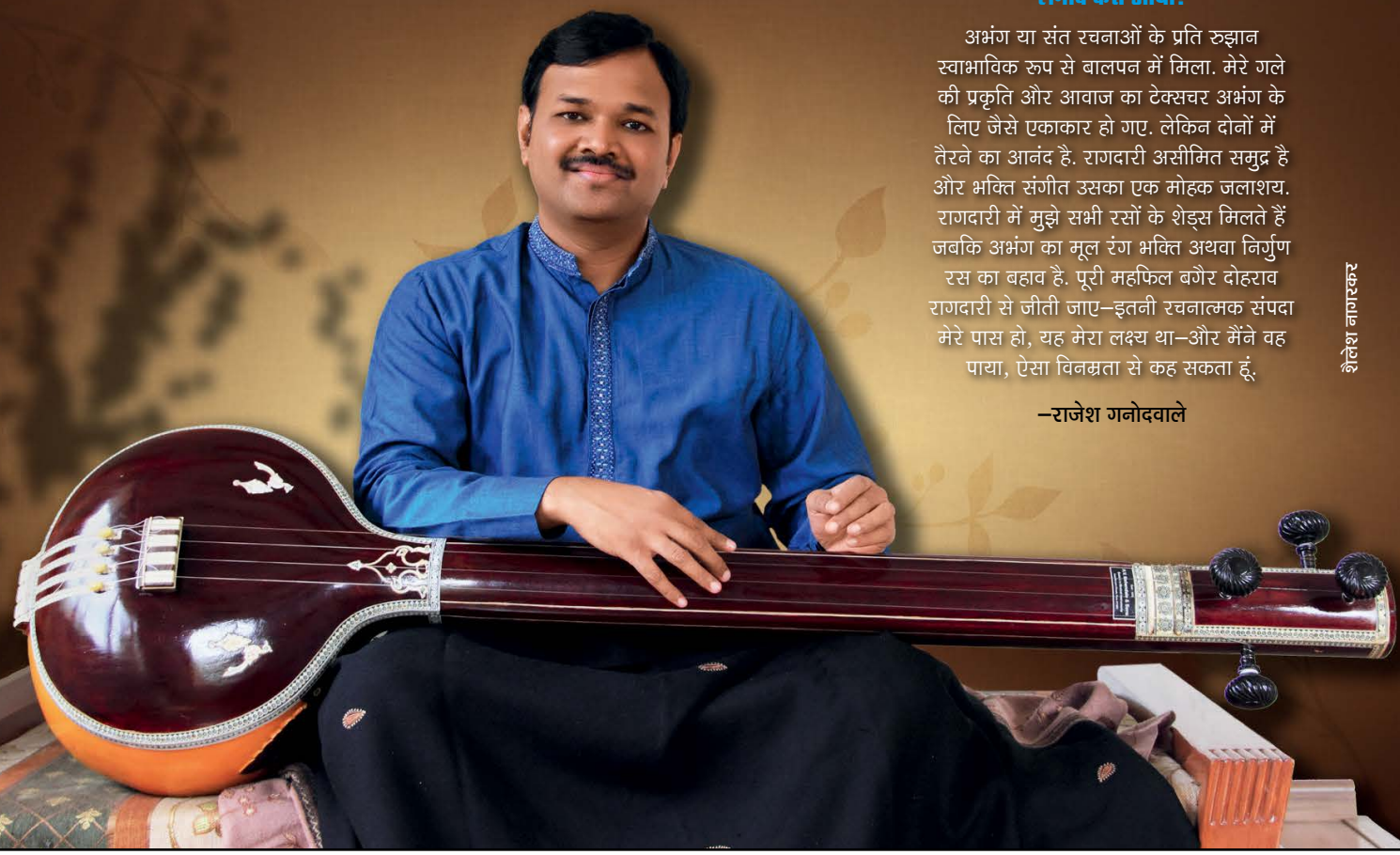

शैलेश नागरकर

आज तक

# देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

IndiaContent

# SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE